20 जून, 2022 ❊ वर्ष 31, पृष्ठ संख्या 60, अंक-6

राजस्थान सुजस

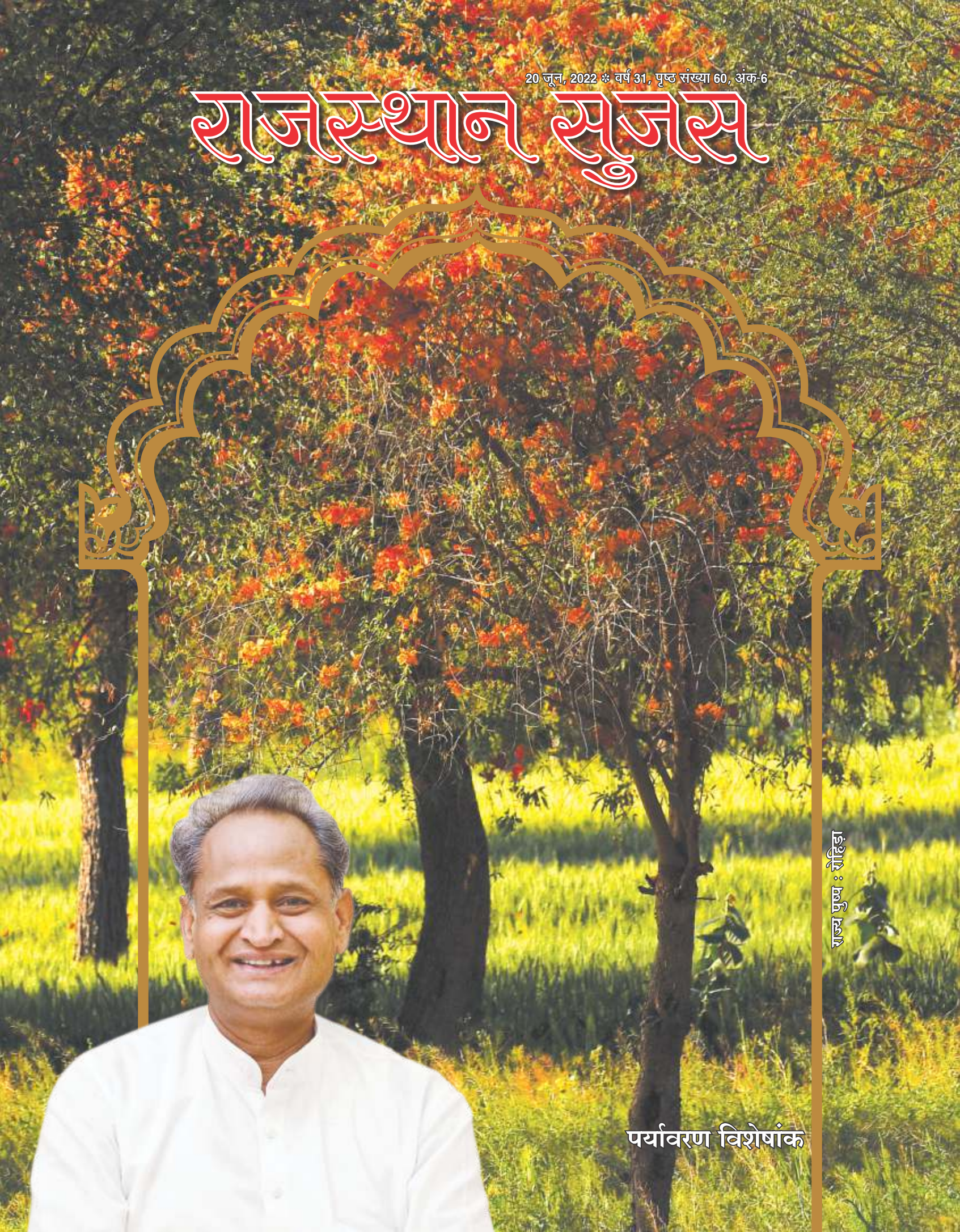

राज्य पुष्प : रोहिड़ा

पर्यावरण विशेषांक

शपथ से आज भी बंधे हैं...

राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में रह रहे गाड़िया लुहार आज भी महाराणा प्रताप के वचन एवं शपथ की पालना करते मिल जायेंगे। हल्दीघाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने अपने सिपाही परिवारों को जन्मभूमि की रक्षा एवं स्वाधीनता की अलख जगाने के लिए वचन देकर गांव-गांव भ्रमण के लिए रवाना किया था। प्रदेश सरकार ने गाड़िया लुहारों के लिए आवास, शिक्षा एवं आजीविका के लिए अनेक योजनाएं चलाई हैं। जिनसे इनके जीवन स्तर में परिवर्तन आया हैं। गाड़िया लुहार घुमन्तू जीवन जीने, लोहे के औजार बनाने एवं चित्तौड़ वापस नहीं जाने की शपथ का पालन कर रहे हैं। पेश है इन मेहनतकश लोगों की जीवनचर्या की एक झलक।

हरिओम सिंह गुर्जर, उप निदेशक, जनसम्पर्क

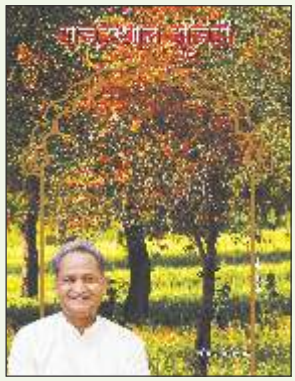

प्रधान सम्पादक
पुरुषोत्तम शर्मा

संपादक
अलका सक्सेना

सह-संपादक
डॉ. लोकेश चन्द्र शर्मा

उप-संपादक
सम्पत राम चान्दोलिया
आशाराम खटीक

आवरण छाया
अशोक गुरावा

राजस्थान सुजस में प्रकाशित सामग्री में व्यक्त विचार लेखकों के अपने एवं आंकड़े परिवर्तनशील हैं। आवश्यक नहीं कि शासन उनसे सहमत हो। सुजस में प्रकाशित सामग्री का विभाग किसी भी रूप में उपयोग कर सकेगा।

ग्राफिक डिजाइनिंग
कृष्णा प्रिंटर्स

सम्पर्क
सम्पादक
राजस्थान सुजस (मासिक)
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग
सचिवालय, जयपुर-302005
मो. नं. 98292-71189
94136-24352
e-mail :
editorsujas@gmail.com
publication.dipr@rajasthan.gov.in
Website :
www.dipr.rajasthan.gov.in

छाया : लक्ष्मण पारंगी

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान का मासिक

वर्ष : 31 अंक : 06 | जून, 2022

इस अंक में

लोक जीवन	02
सम्पादकीय	04
पर्यावरण प्रशिक्षण	11
बातचीत	16
पर्यावरण संरक्षण	17
आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व...	20
ताल छापर : कृष्ण मृगों की अठखेलियां	24
अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क	26
The Tale of the Striped...	28
राजस्थान की गौरवमयी गाथा	32
देशी-विदेशी पर्यटकों को लुभा रहा...	38
केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान	40
पर्यावरण संरक्षण: पहली प्राथमिकता	41
पर्यावरण प्रेमियों का महाकुंभ : खेजड़ली	42
पर्यावरण जन-जागृति दौड़	44
मेघड़ासर का जलाशय : पानी का खजाना	48
वर्षा जल संचयन	50
वन एवं वन्य जीव	52
बच्चों के चेहरों पर मुस्कान लाने का प्रयास	53
ग्रामीण विकास	54
ज्ञान-विज्ञान	56
महिला जागरूकता	57
धरोहर	59
तस्वीर बदलाव की	60

घर से वन तक जैव-विविधता...

05

साक्षात्कार

14

पर्यावरण संरक्षण की जगाई अलख

46

फोटो फीचर

30-31

राजस्थान सुजस के आगामी अंक शिक्षा विशेषांक के लिए मौलिक, अप्रकाशित सामग्री भिजवायें। कृपया अपने आलेख एवं फोटोग्राफ सम्पादक को e-mail : editorsujas@gmail.com पर अथवा डाक से भेजें।

प्रकृति है, तो हम हैं

12

हाड़ौती में वन्यजीव पर्यटन

18

खेल-खिलाड़ी

58

पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय भागीदारी

प्रकृति और व्यक्ति में अंतर्संबंध होता है। प्रकृति के बिना व्यक्ति के जीवन की परिकल्पना संभव नहीं है। भूमि, जल, वायु, आकाश यह सब प्रकृति के घटक है। इन्हीं से मानव जीवन अस्तित्व में है। हमें प्रकृति के संरक्षण के प्रति जागरूक होना है। इस कार्य में सक्रिय भागीदारी हम सभी को निभानी है।

पर्यावरण संरक्षण और विकास में संतुलन अपरिहार्य है। भारतीय संस्कृति प्रकृति के साथ सहयोग व सह-अस्तित्व में विश्वास रखती है। प्रकृति के कण-कण के साथ एकात्मकता का अनुभव और कम से कम हानि पहुँचाना चिरकाल से भारतीय जीवन दर्शन रहा है। भारतीय संविधान के भाग 4क के अन्तर्गत अनुच्छेद 51-क के अनुसार प्रत्येक नागरिक का यह दायित्व है कि वह वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा करे और प्राणिमात्र के प्रति दयाभाव रखे।

राजस्थान सुजस का जून माह का पर्यावरण पर आधारित यह अंक आपके हाथों में है। इस अंक में वन विभाग, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के क्रियान्वयन से लाभान्वित होते आमजन से संबंधित पाठ्य सामग्री का समावेश किया गया है। विभाग के राज्य स्तरीय और संभाग स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्रों पर दिए जा रहे प्रशिक्षणों का भी उल्लेख किया गया है।

प्रतिवर्ष विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रेल, अन्तरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून एवं ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितम्बर को मनाया जाता है। इस दौरान विभिन्न जिलों में पर्यावरण चेतना कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। कोविड-19 से उपजी विपरीत परिस्थितियों ने मानव को प्रकृति की ताकत का एहसास कराया है। प्राणवायु ऑक्सीजन प्रदाता वृक्षों एवं पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ी है। वन, वन्यजीव, प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन एवं उन्नयन की परम्परा हमें वैदिक काल से ही विरासत में मिली है। हम सभी को मिल-जुलकर पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय भागीदार बनना होगा। साथ ही भावी पीढ़ी को भी पर्यावरण संरक्षण के इस अनुष्ठान से जोड़ने के लिए प्रेरित करना होगा।

आपके अमूल्य सुझाव एवं प्रतिक्रियांए हमारा मार्ग सदैव प्रशस्त करती रहेंगी। इसी आशा और विश्वास के साथ राजस्थान सुजस का जून माह का यह पर्यावरण विशेषांक पाठकगण को सादर प्रस्तुत है।

अभिवादन एवं मंगलकामनाओं सहित,

(पुरुषोत्तम शर्मा)
प्रधान संपादक

पर्यावरण संरक्षण से संबंधित बैठक में निर्देश देत हुए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत

घर से वन तक जैव-विविधता संरक्षण

यदि राजस्थान में पाये जाने वाले उष्णकटिबंधीय शुष्क वनों का पुनर्स्थापन और संरक्षण किया जाना है तो घर से वन तक सम्पूर्ण सांस्कृतिक भू-परिदृश्य में जैव-विविधता और उस पर उपलब्ध लोक ज्ञान का संरक्षण आवश्यक है।

● **घर में जैव-विविधता:** सबसे पहले घर के आँगन, बाड़ी, बगिया, बगीचे और आसपास वनस्पति प्रबंध की विविध परम्पराएं देखने को मिलती हैं। यहाँ पर विर्किंग बायोडायवर्सिटी या ऐसी जैव-विविधता जो रोजमर्रा की जिंदगी में काम आती है, को प्राथमिकता दी जाती है। कुछ होम-गार्डन जैव-विविधता के सन्दर्भ में बहुत समृद्ध हैं। कुछ नहीं तो तुलसी सहित आठ-दस प्रजातियों के पौधे तो हर घर में मिल ही जाते हैं। जिस समय मेरे शोध प्रबंध पर कार्य चल रहा था, उस समय एक घर ऐसा मिला जिसके बगीचे में 53 प्रजातियों की वनस्पति मिली। संदेश यह है कि घर में अपने उपयोग के लिये जितने प्रकार की प्रजातियां हम लगा सकते हैं उन्हें लगाया जाना चाहिए। इनमें कुछ प्रजातियां ऐसी हो सकती हैं जो केवल वनों में पाई जाती हैं और घर में उगाने से वनों का विदोहन बचता है। घर में लाकर लगाने पर उपयोगी वन्य प्रजातियों के डॉमेस्टिकेशन की दिशा में भी यह एक कदम है। भारत के उष्णकटिबंधीय वनों की बहुतायत वाले क्षेत्रों में भी होम गार्डन की परम्परा अभी भी यथावत प्रचलन में है और जैव-विविधता संरक्षण, कार्बन संचय और आजीविका सुधार में योगदान करती है।

● **गाँव और शहर में जैव-विविधता:** अब आप कल्पना कीजिये कि अपने घर से थोड़ा बाहर कदम रख रहे हैं और अपने गाँव या शहर में घूम रहे हैं। यहाँ आपको मोहल्ले का बगीचा, रिहायशी क्षेत्रों में इक्का-

डॉ. दीप नारायण पाण्डेय
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख), राजस्थान

दुक्का प्राचीन वृक्ष, अर्बन ग्रीन स्पेस, रास्तों के किनारे रोपी गयी वृक्षों की कतारें, संस्थानों के परिसर में उगाये गये सुन्दर बगीचे, वृक्ष कुंज, बॉटैनिकल गार्डन, सड़कों के किनारे वृक्षावली, खाली पड़ी जमीन में स्वत: पुनरुत्पादित अनौपचारिक हरियाली (इनफॉर्मल ग्रीन स्पेस), बाजारों और सार्वजनिक स्थलों पर रोपित वृक्ष और वनस्पति और ऐसी ही विविध प्रथायें जैव-विविधता संरक्षण, कार्बन संचय, तापमान नियमन और स्वास्थ्य लाभ जैसे कार्य संपन्न करती हैं। गाँव के थोड़ा बाहर निकलने पर पाये जाने वाले देववन, रखत-बनी, ओरण, राड़ी, बड़े बगीचे आदि भी जैव-विविधता संरक्षण में योगदान देते हैं। गाँव और शहर के सम्पूर्ण भू-परिदृश्य में जैव-विविधता संरक्षण की विविध परम्परायें विश्व भर में देखने को मिलती हैं। गाँव के कुओं, बावड़ी, ढर्रे, खलिहान, मंदिरों आदि के आसपास भी वनस्पति मिलती है। यदि गाँव या शहर में नदी नाले हैं तो दोनों तटों में भी वनस्पति का संरक्षण मिल सकता है, जिसे सैक्रेड कॉरिडोर कहा जाता है। मंदिरों के आसपास मंदिर वन, तालाबों की पाल में रोपित वनस्पति या इक्का-दुक्का पुराने वृक्ष व वानस्पतिक एवं प्राणी जैव-विविधता बहुतायत में पाई जाती है। शहरी वनों और हरियाली के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ अनेक हैं और इन क्षेत्रों को बढ़ाये बिना घर से वन तक जैव-विविधता के लाभ प्राप्त नहीं किये जा सकते। हाल में हुये अध्ययन का एक उदाहरण यहाँ दिया जा सकता है। शहरी हरियाली में जमीन के ऊपर और नीचे के जैवभार में औसतन 1901 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर कार्बन स्टॉक पाया गया है।

वैधानिक दृष्टि से राज्य में वनों की स्थिति

वैधानिक स्थिति	क्षेत्रफल (वर्ग किमी.)	प्रतिशत
आरक्षित वन (Reserve Forest)	12176.24	37.05
रक्षित वन (Protected Forest)	18564.45	56.49
अवर्गीकृत वन (Unclasses Forest)	2123.93	6.46
योग	32864.62	100

● **खेत और खलिहान में जैव-विविधता:** जब गाँव में खेतों की ओर बढ़ते हैं, तो वहां पर खेती के साथ वृक्ष उगाने की परम्परा मिलती है। खेतों की मेड़, पानी के स्थान और खेत में बनाई गई झोपड़ी या घर के आसपास विविध प्रजातियों की वनस्पति उगाने की प्राचीन परम्परा आज भी व्यापक रूप से पाई जाती है। कुछ क्षेत्रों में खेत में फसल उगाने के साथ ही एक हिस्से को छोड़ दिया जाता है जहाँ वनस्पतियां स्वत: उगती रहती हैं। इसे लैंड-स्पेयरिंग एप्रोच कहा जाता है। उदाहरण के लिये मध्य-प्रदेश के बुंदेलखंड और बघेलखंड में खेतों की जमीन के बीच में प्राय: आम और महुआ के वृक्ष बगीचों के रूप में लगाये जाते हैं। इन बगीचों में विविध प्रकार की वनस्पतियां स्वत: भी उगती हैं। खेतों के बीच में कुछ ऐसी जमीन भी छोड़ दी जाती है जिसे सदा-पड़त कहते हैं। इस भूमि को कभी हानि नहीं पहुंचायी जाती। यहाँ सांप, बिच्छू, सरीसृप, कीड़े मकोड़े इत्यादि की बहुतायत पाई जाती है। जमीन छोड़ने (लैंड-स्पेयरिंग एप्रोच) के या खेती के साथ वृक्ष उगाने की परम्परा (लैंड-शेयरिंग एप्रोच) के रूप में कृषि वानिकी की प्राचीन और नवीन दोनों ही परम्पराएं शुष्क वनों वाले भौगोलिक क्षेत्रों में विद्यमान हैं।

मौजूदा भूमि-उपयोगों को देखते हुये भारत में कृषि वानिकी से बड़ी आशायें हैं। जलवायु परिवर्तन को कम करने के उद्देश्य से वन क्षेत्रों को बढ़ाने के लिये भारत दृढ़प्रतिज्ञ है। लेकिन अनुमान यह है कि पुनर्स्थापन के लिये अतिरिक्त क्षेत्र केवल 1.58 मिलियन हेक्टेयर ही उपलब्ध हो सकता है, जो संचयी रूप से 61.3 टेराग्राम कार्बन संचित कर पायेगा। यह वैश्विक अध्ययनों से प्राप्त अनुमानों से काफी कम है। परन्तु वर्तमान कृषि भूमि में कृषि वानिकी के लिये 14.67 मिलियन हेक्टेयर उपलब्ध हो सकती है, जहाँ राष्ट्रीय स्तर पर 98.1 टेराग्राम कार्बन संचित किया जा सकता है।

● **प्राकृतिक वन और वन्यजीव संरक्षित क्षेत्रों में जैव-विविधता:** अब आप थोड़ा कल्पना कीजिये कि अपने गाँव या शहर और खेतों के भू-परिदृश्य से आगे चलते हुए आप वनों की ओर जाते हैं। यहाँ भी पारम्परिक ज्ञान का उपयोग कर मानव ने विविध प्रकार से वानस्पतिक जैव-विविधता का परिवर्तन किया है जिसके कारण वन्यप्राणी जैव-विविधता भी बेहतर हुई है। आगे घने वनों में जाते हैं जहाँ संरक्षित वन मिलते हैं। इन्ही में से कुछ क्षेत्रों को राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, टाइगर रिजर्व, लेपर्ड रिजर्व आदि घोषित किया जा सकता है। यहाँ

कोटड़ा वन क्षेत्र में जलग्रहण प्रबंधन कार्य

राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर का अवलोकन करते हुए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत

प्राकृतिक परिवेश में जैव-विविधता का संरक्षण होता है।

कुल मिलाकर संक्षेप में बात यह है कि सांस्कृतिक भू-परिदृश्य में मानव समाज और जैव-विविधता का अटूट संबंध स्थापित है। प्रकृति और मानव का संबंध भी यहाँ स्पष्ट होता है। इस संबंध ने जीवन-यापन को सुगम बनाते हुये संरक्षण की विविध परम्पराओं को जन्म दिया है। यह पारम्परिक ज्ञान एथनोफॉरेस्ट्री के नाम से जाना जाता है। वन पुनर्स्थापन के लिये इस जैव-सांस्कृतिक दृष्टिकोण को साथ लेकर चलना आवश्यक है।

वैश्विक जैव-विविधता संकट को रोकने के लिये केवल वनों और संरक्षित क्षेत्रों में ध्यान केन्द्रित करने से काम नहीं चलेगा। महत्वपूर्ण जैव-विविधता क्षेत्रों, पारिस्थितिक रूप से अक्षुण्ण क्षेत्रों और प्रजातियों की श्रेणियों एवं पारिस्थितिक क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व के लिये सर्वाधिक उपयोगी स्थानों को सुरक्षित करने के लिये न्यूनतम भूमि क्षेत्र के वैश्विक अनुमान स्पष्ट करते हैं कि कम से कम 64.7 मिलियन वर्ग किलोमीटर (स्थलीय क्षेत्र का 44 प्रतिशत) में संरक्षण (संरक्षित क्षेत्रों से लेकर भूमि उपयोग नीतियों तक) की आवश्यकता होगी। उत्साहजनक बात यह है कि संरक्षण के लिये आवश्यक इस भूमि में से 44.9 मिलियन वर्ग किलोमीटर (70.1 प्रतिशत) क्षेत्र वर्तमान में सुरक्षित है। जहां इन जमीनों को चिन्हित किया गया है वहां पर 1.8 बिलियन से अधिक लोग निवास करते हैं। स्वाभाविक है कि जैव-विविधता की सुरक्षा के लिये स्थानीय लोगों को स्वायत्तता, आत्मनिर्णय, समानता और टिकाऊ प्रबंधन को बढ़ावा देने वाली रणनीतियों के माध्यम से जोड़ना आवश्यक है। स्थानीय रूप से भूमि-उपयोग की स्थिति से ज्ञात है कि वर्ष 2030 तक इस भूमि का 1.3 मिलियन वर्ग किलोमीटर मानव द्वारा गहन उपयोग के लिये भू-उपयोग परिवर्तित होने का खतरा है। इस रणनीति के अनुसार भारत में 7,89,331 वर्ग किलोमीटर (24.9 प्रतिशत क्षेत्र) में संरक्षण आवश्यक होगा। इसमें से वर्तमान में संरक्षित क्षेत्रों के अतिरिक्त 4,62,776 (14.6 प्रतिशत) नये क्षेत्र होंगे। इसी के साथ, केवल संरक्षित क्षेत्र घोषित कर देना पर्याप्त नहीं है। प्राणियों की आवाजाही और जीन-प्रवाह को संरक्षित करने के लिये संरक्षित क्षेत्रों को गलियारों

भीलवाड़ा में कृषि वानिकी का एक परिदृश्य

सभी छाया चित्र : पुष्पदीप पाण्डेय

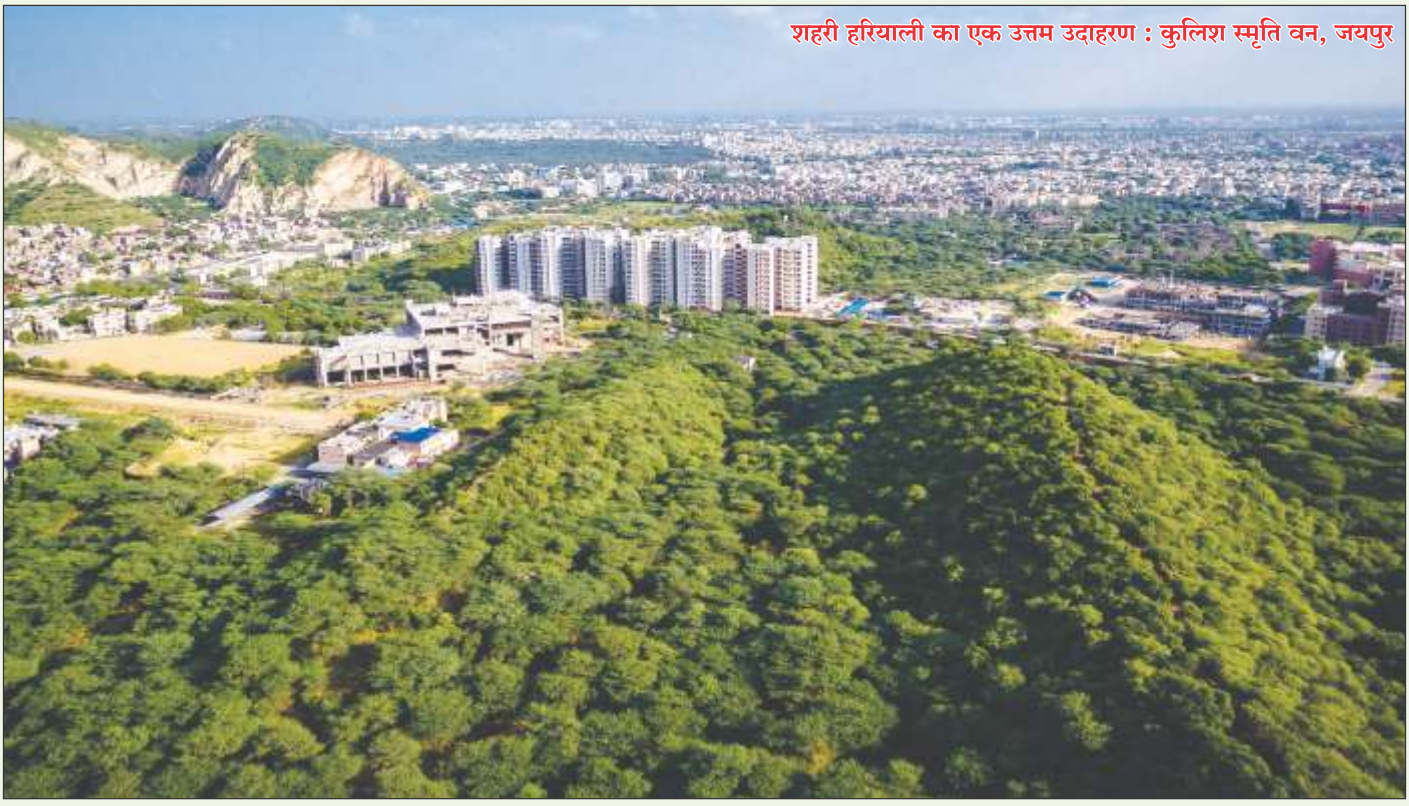
शहरी हरियाली का एक उत्तम उदाहरण : कुलिश स्मृति वन, जयपुर

के माध्यम से जोड़ना भी आवश्यक होगा। संरक्षित क्षेत्रों का वर्तमान वैश्विक नेटवर्क वन्य-प्राणियों की आवाजाही हेतु आवश्यक क्रियात्मक जुड़ाव (फंक्शनल कनेक्टिविटी) प्रदान नहीं करता। मानव दखल को कम करने और नये संरक्षित क्षेत्र घोषित कर ठोस प्रबंध करने से जुड़ाव में सुधार हो सकता है। स्तनपायी प्राणियों की निर्बाध आवाजाही के लिये सबसे अधिक उपयोगी क्षेत्र उनके लिये असुरक्षित है। इनमें से 71 प्रतिशत क्षेत्र वही है जो वैश्विक जैव-विविधता प्राथमिकता में भी आते हैं और 6 प्रतिशत भूमि ऐसी है जहाँ मानव जनसंख्या का मध्यम से उच्च दबाव है। स्वाभाविक है कि केवल वनों को संरक्षित करने से काम नहीं चलेगा।

उष्णकटिबंधीय वनस्पति का वैश्विक कार्बन चक्र में महत्त्वपूर्ण योगदान है। इसमें वैश्विक स्थलीय शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता में वनों का 33 प्रतिशत और सवाना का 30 प्रतिशत योगदान है। वर्तमान में 23 प्रतिशत अपूरणीय कार्बन (इर्रिकवरेबल कार्बन) संरक्षित क्षेत्रों के भीतर है और 33.6 प्रतिशत स्थानीय समुदायों द्वारा प्रबंधित जमीनों पर है। पृथ्वी का आधा अपूरणीय कार्बन केवल 3.3 प्रतिशत भूमि पर केंद्रित है। इसलिये घर से वन तक पाये जाने वाले इन प्राकृतिक स्थलों को उनके अपूरणीय कार्बन भंडार के कारण खोने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं।

इसके साथ ही सम्पूर्ण भू-परिदृश्य में विभिन्न उद्देश्यों के लिये किया जा रहा वन पुनर्स्थापन भविष्य में शुष्क वनों में सूखे से पड़ने वाले दुष्प्रभाव की आशंका को कम कर सकता है। शुष्क वनों के पुनर्स्थापन को बढ़ाने और परिणामस्वरूप जैव-विविधता और पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं को ठीक करने के लिये सम्पूर्ण भू-परिदृश्य की गुणवत्ता का संरक्षण सर्वोपरि है। यह सब तभी प्रबंधित हो सकता है जब घर से वन तक जैव-विविधता का निरंतर संरक्षण किया जाये।

जैसा कि वर्ष 1950 में विश्व के अग्रणी जर्नल में प्रकाशित शोध से पता चलता है, प्राकृतिक पुनरुत्पादन और पौधारोपण के माध्यम से मूल्यवान प्रजातियों को उगाने के बड़े प्रयास भारत सहित दुनिया के विभिन्न देशों के उष्णकटिबंधीय शुष्क वनों में पहले भी हुये हैं, किन्तु सफलता तब भी संदिग्ध ही रही है। आज भी स्थिति में बहुत अंतर नहीं आया है। एक ओर ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट दुनिया के सबसे संकटापन्न वन हैं और दूसरी ओर इन वनों के पुनर्स्थापन पर शोध बहुत कम है।

प्रदेश का वानिकी परिदृश्य : एक दृष्टि में

राज्य का कुल अभिलेखन वन	32864.62 वर्ग किमी
राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सापेक्ष	9.60 प्रतिशत
राज्य का कुल वनावरण	16655 वर्ग किमी
अभिलेखित वन के अंतर्गत वनावरण	12560 वर्ग किमी
अभिलेखित वन के बाहर वनावरण	4095 वर्ग किमी
राज्य का वृक्षावरण	8733 वर्ग किमी
राज्य का कुल वनावरण एवं वृक्षावरण	25388 वर्ग किमी
राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का	7.42 प्रतिशत
प्रति व्यक्ति औसतन वनावरण एवं वृक्षावरण	0.037 हेक्टेयर

वृक्षारोपण करते हुए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत

इसलिये प्रायोगिक रूप से बड़ी संख्या में प्रजातियों का रोपण और सीधी बुवाई आवश्यक होती है। इनमें से कुछ प्रजातियों की प्रारंभिक वृद्धि अच्छी होने से स्थानीय मृदा में सुधार होता है। मिट्टी के अनुकूल होने पर अनुक्रमण में बाद में आने वाली प्रजातियों के उगने में सहायता मिलती है। रोपण हेतु प्रजाति चयन अनेक कारकों पर निर्भर करता है, तथापि स्थानीय ज्ञान को प्राथमिकता देने से पुनर्स्थापन क्षेत्रों का आजीविका सुधार में बेहतर योगदान होने की संभावना रहती है।

जैसा कि पूर्व में स्पष्ट किया गया है, उष्णकटिबंधीय पारिस्थितिक तंत्रों में वैज्ञानिक अध्ययन इतने अधिक नहीं हैं कि इनके पुनर्स्थापन की पूरी समझ प्राप्त की जा सके। जब शोध की कमी हो तो वनों में लम्बे समय से कार्य करने वाले कार्मिकों का अनुभवजन्य ज्ञान और स्थानीय लोगों के पारम्परिक स्थानीय ज्ञान का महत्त्व और भी अधिक हो जाता है। उदाहरण के लिये, यदि पुनर्स्थापन के विभिन्न उद्देश्यों और स्थान विशेष की स्थितियों के अनुरूप प्रजातियों का चयन करना है तो केवल वैज्ञानिक ज्ञान पर्याप्त नहीं होगा। स्थानीय पारिस्थितिक ज्ञान के द्वारा प्रजातियों की स्थानीय उपयोगिता, खतरे की स्थिति और जैविक दबाव के विरुद्ध प्रतिरोध आदि कारकों को समझकर प्रजाति चयन ठीक रहेगा। स्थानीय ज्ञान प्रजातियों के संभावित और वर्तमान उपयोग पर स्पष्ट अंतर्दृष्टि दे सकता है।

घर से लेकर वन तक पायी जाने वाली जैव-विविधता की यह व्यवस्था स्थानीय ज्ञान और स्थानीय निवेश के बिना संभव नहीं है। इसलिये कुछ ऐसी परम्परायें भी हैं जिनका प्रभाव संपूर्ण भू-परिदृश्य में दृष्टिगोचर होता है। इनमें से कुछ तो ऐसी हैं जो जमीन पर दिखाई पड़ती हैं और कुछ ऐसी हैं जो सामाजिक व्यवस्था में परिलक्षित होती हैं। उदाहरण के लिये, हमारा चिंतन, हमारे मानवीय-मूल्य, समाज द्वारा तय किये गये नियम, उन नियमों के अनुरूप हमारे व्यवहार व क्रियाकलाप, वर्जनायें, रीति-रिवाज, नैतिकता जैसी विविध व्यवस्थायें हैं जो घर से लेकर वन तक मानव समाज के मध्य व्याप्त हैं। यही व्यवस्था है जो पीपल, बरगद, आम जैसी प्रजातियों को पूरी तौर पर संरक्षित करने के लिये प्रेरित करती है। यही व्यवस्था है जो अनेक प्राकृतिक आवासों को देववन, ओरण आदि के नाम संरक्षित करने के लिये प्रेरित करती है। यह पूरा विषय बहुत रोचक और व्यापक है। इस विषय में आज तक तीन लाख से अधिक शोधपत्र प्रकाशित हो चुके हैं जो स्थानीय ज्ञान, पारम्परिक ज्ञान, इंडीजीनस नॉलेज, ट्रेडिशनल

- पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग पारिस्थितिकी संतुलन का परिरक्षण, पर्यावरण संबंधी मामलों पर अध्ययन एवं अनुसंधान, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष क्रियाकलाप, प्रचार एवं प्रसार के माध्यम से पर्यावरण चेतना जाग्रत करने का कार्य करता है।
- विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रेल, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून एवं ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितम्बर को विभिन्न जिलों में विभाग द्वारा पर्यावरण चेतना कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं।
- राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा जल प्रदूषण व पर्यावरण संबंधी नियमों, अधिनियमों का पालन करवाया जाता है।
- प्रदेश की जैव विविधता के संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु जन चेतना जागृत करने के उद्देश्य से प्रदेश एवं संभागीय मुख्यालयों पर आमुखीकरण एवं प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा किया जाता है।
- जयपुर और जोधपुर में सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता केन्द्र स्थापित किये गए थे। 7 शहरों में (जयपुर में 2, अजमेर, अलवर, भिवाड़ी, पाली तथा उदयपुर) में नए केन्द्र स्थापित किए हैं।

नॉलेज, लोकल इकोलॉजिकल नॉलेज इत्यादि विषयों पर हैं।

सबसे बड़ा संदेश यह है कि सरकार द्वारा नामित किये गये विविध प्रकार के वनों और वन्यजीव क्षेत्रों में तो संरक्षण आवश्यक है ही, परन्तु केवल इन्ही रणनीतियों के भरोसे जैव-विविधता का संरक्षण संभव नहीं है। इसके लिये घर से वन तक संरक्षण नीतियों का क्रियान्वयन आवश्यक है। यह एक ऐसा परिदृश्य है जो जैव विविधता और लोगों दोनों के लिये काम करता है। मानव-परिवर्तित भूमि को कार्यशील-परिदृश्य के रूप में प्रबंधित करने में जैव विविधता-आधारित स्थानीय तकनीकों का उपयोग किया जा सकता है। ये न केवल पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं के लिये बल्कि वन्य-प्रजातियों के रखरखाव और निरंतरता के साथ ही मानव की आवश्यकताओं को पूरा कर सकती हैं।

संक्षेप में यहाँ यह कहना है कि मानव और प्रकृति के मध्य के रिश्ते सम्पूर्ण सोशल-इकोलॉजिकल सिस्टम को जन्म देते हैं। सामाजिक-पारिस्थितिक तंत्र की इसी व्यवस्था ने मानव को अपने चारों ओर के परिवेश को जैव-विविधता से परिपूर्ण करने में योगदान दिया है। मानव के अपने परिवेश और परिदृश्य के साथ रिश्ते यदि सद्भावी रहते हैं तो पर्यावरण और वन संरक्षण तो होता ही है, साथ ही मानव सभ्यता के दीर्घकाल तक फलते-फूलते रहने की संभावना बढ़ जाती है। आज हम उस युग में जी रहे हैं जब हमें जैव-विविधता का संरक्षण वहां करना होगा जहाँ हम रहते और काम करते हैं। सबसे पहले हमें अपने घरों में पौधों को संरक्षित और पुनर्स्थापन करना होगा। उससे थोड़ा बाहर निकलने पर गाँव और मोहल्ले के बाग-बगीचों में संरक्षण और पुनर्स्थापित करना होगा। उससे आगे खेतों-खलिहानों में, और अंत में, वनों और प्राकृतिक क्षेत्रों में संरक्षण और पुनर्स्थापन करना होगा। स्थानीय प्रजातियों की विविधता पारिस्थितिक पुनर्स्थापन का सबसे मौलिक घटक है। इसके बिना सब सूना है। इन सभी भू-परिदृश्यों में यथा-संभव पुनर्वन्यकरण के सिद्धांतों का भी ध्यान रखना होगा। ●

वन विभाग : एक नजर में

प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल	3,42,239 वर्ग किमी.
प्रदेश का कुल वन क्षेत्र	32,864.62 वर्ग किमी.
कुल भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत वन क्षेत्र	9.60
प्रदेश का कुल वनावरण	16,654.96 वर्ग किमी.
वृक्षावरण	8,733 वर्ग किमी.
वनावरण एवं वृक्षावरण	25387.96 वर्ग किमी.
राज्य पशु	चिंकारा एवं ऊंट
राज्य पक्षी	गोडावण
राज्य वृक्ष	खेजड़ी
राज्य पुष्प	रोहिड़ा
राष्ट्रीय उद्यान 3	
वन्यजीव अभयारण्य	27
कंजर्वेशन रिजर्व	15
बाघ परियोजनाएं	4 (रणथम्भौर, सरिस्का, मुकन्दरा, रामगढ़ विषधारी)
पक्षी स्थल	2 (केवलादेव नेशनल पार्क एवं सांभर झील)
कुल प्रादेशिक मण्डल	38
वन्यजीव मण्डल	16
भारतीय वन सेवा के अधिकारी (कैडर स्ट्रेंथ)	145
राज्य वन सेवा के अधिकारी (स्वीकृत पद)	429
अधीनस्थ सेवा (स्वीकृत पद)	7658
एस.टी.पी.एफ.रणथम्भौर	112
लेखा एवं तकनीकी संवर्ग	710
मंत्रालयिक संवर्गकार्मिक (स्वीकृत पद)	990
चतुर्थ श्रेणी संवर्ग	413
कार्यप्रभारित कर्मचारी	3812

वानिकी एवं वन्यजीव प्रशिक्षण

पौधारोपण कार्यक्रम करते हुए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत

अमर सिंह गोठवाल
आई.एफ.एस.

राजस्थान वानिकी एवं वन्यजीव प्रशिक्षण संस्थान, राजस्थान के वन विभाग के समस्त अधिकारियों एवं अधीनस्थ कार्मिकों, स्वयंसेवी संगठन के सदस्यों, विद्यार्थियों के प्रशिक्षण एवं जागरूकता देने हेतु राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान है। यह प्रशिक्षण संस्थान जयपुर में जे.एल.एन. मार्ग पर जवाहर कला केन्द्र के सामने स्थित है।

वनों पर बढ़ते दबाव का सफलतापूर्वक सामना करने, जन अपेक्षाओं में आ रहे परिवर्तन तथा वन एवं सामान्य प्रबन्धन विधियों में हो रहे नये प्रयोगों, नई सूचना प्रौद्योगिकी तकनीकी के उपयोग से परिचित रहते हुए वैज्ञानिक दृष्टि से वन प्रबन्धन के लिए आवश्यक है कि सभी स्तर के अधिकारियों/कर्मचारियों के समय-समय पर विभिन्न विषयों पर निरन्तर प्रशिक्षण दिये जाते हैं। राज्य में वानिकी प्रशिक्षण संस्थानों में इसी अनुरूप दीर्घकालीन उपयोगी प्रभाव वाले प्रशिक्षण दिये जा रहे हैं एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों में समय की आवश्यकता को देखते हुए परिवर्तन किये जा रहे हैं। राज्य सरकार तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्य में क्रियान्वित की जा रही विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से प्रशिक्षण हेतु सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

राज्य में वन विभाग द्वारा प्रशिक्षण देने हेतु चार संस्थाएं यथा राजस्थान वानिकी एवं वन्यजीव प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर, वन प्रशिक्षण केन्द्र, अलवर, मरु वन प्रशिक्षण केन्द्र, जोधपुर एवं वन्यजीव प्रबंधन एवं रेगिस्तान परितंत्र प्रशिक्षण केन्द्र, तालछापर में स्थित है। प्रशिक्षण कार्यो की राज्य के वन एवं वन्यजीव प्रबन्धन के सन्दर्भ में उपयोगिता, प्रासंगिकता, विश्वसनीयता और वैधता बढ़ाने हेतु पाठ्यक्रम में परिवर्तन, प्रशिक्षण प्रविधियों में सुधार तथा नवीन शोध पर आधारित पाठ्य सामग्री का संयोजन तथा संकाय सदस्यों की दक्षता वृद्धि प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। संस्थानों में सभी विषयों के प्रशिक्षित वक्ताओं व विद्वानों को आमंत्रित कर प्रशिक्षण दिलाए जाने की व्यवस्था है।

- **राजस्थान वानिकी एवं वन्यजीव प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर**
- **मरु वन प्रशिक्षण केन्द्र, जोधपुर**
- **वन प्रशिक्षण केन्द्र, अलवर**
- **वन्यजीव प्रबंधन एवं रेगिस्तान परितंत्र प्रशिक्षण केन्द्र तालछापर, चूरू**
- **सेंटर फॉर कन्जरवेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एण्ड क्लाइमेटचेंज (CCNRECO)**

विभाग में राजस्थान वानिकी एवं वन्यजीव प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर (RFWTI) द्वारा विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। सामान्य प्रशिक्षण एवं प्राकृतिक संसाधन के प्रबंधन के विषयों पर व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने हेतु ''सेंटर फॉर कन्जरवेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एण्ड क्लाइमेटचेंज'' की स्थापना की गई है। जिसका वर्चुअल उद्घाटन मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा 18 दिसम्बर 2021 को किया गया। जिसके अन्तर्गत विश्वस्तरीय पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थानों से समन्वय स्थापित कर उच्चस्तरीय रिजल्ट ऑरियंटेड प्रशिक्षण आयोजित किया जाना सम्भव हो सकेगा।

इस सेंटर का संचालन राजस्थान सलाहकार संस्था रजिस्ट्रेशन अधिनियम के तहत पंजीकृत संस्था ''अमृता देवी सोसायटी फॉर फोरेस्ट्री एण्ड वाइल्डलाईफ ट्रेनिंग'' के माध्यम से संचालित किया जायेगा। ●

वानिकी प्रशिक्षण केन्द्र

प्रकृति है, तो हम हैं

छाया चित्र : सविता चौहान

डॉ. सत्यनारायण सिंह
भा.प्र.से. (से.नि.)

महात्मा गांधी ने कहा था ''आप प्रकृति से अपनी जरूरत के अनुसार ही लें तो वह तुम्हें हमेशा देती रहेगी और यदि उसका दोहन करना प्रारम्भ किया तो वह तुम्हें दुविधा देना प्रारम्भ कर देगी।'' पश्चिमी उपभोक्तावादी-साम्राज्यवादी मूल्यों के मुकाबले के संदर्भ में गांधीजी का चिंतन और अधिक प्रासंगिक हो गया है। आज गांधीजी की बातों ने भूमण्डलीकरण के परिप्रेक्ष्य में एक नया व व्यापक आयाम ग्रहण कर लिया है, जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

गांधी ने कहा था ''भारत के सामने अपनी आत्मा खो देने का खतरा है। वह इसे खोकर जीवित नहीं रह सकता इसलिए उसे आलस्यपूर्ण व असहाय होकर यह नहीं कह देना चाहिए कि मैं पश्चिम के प्रवाह से बच नहीं सकता। उसे अपने स्वयं के लिए और विश्व के लिए इतना दृढ़ होना चाहिए कि वह उसका प्रतिरोध कर सके। उसे हर हाल में प्रकृति को बचाना है, ऐसा विकास नहीं करना जो प्रकृति को नष्ट कर दे।'' हम उपयोगितावादी के बजाय उपभोक्तावादी हो गये हैं। उपभोक्तावादी जीवनशैली प्राकृतिक संसाधनों का जरूरत से ज्यादा उपयोग करवा रही है। बढ़ती जनसंख्या व बढ़ती संस्कृति ने जरूरत से ज्यादा प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया है।

इन्सान केवल खुद के स्वार्थ में सिमटा हुआ है, जीव जन्तुओं के घरों पर भी कब्जा जमाया है। अपने पैरों को पसारते हुए हम जंगलों तक पहुंच गये, हमें पता चला जब जानवरों ने शहरों में हंगामा मचाना प्रारम्भ कर दिया। वन्य जीवों के जीवन पर जलवायु परिवर्तन व वनों के विनाश से खतरा है। हम फैशन व कपड़ा उद्योग से पानी प्रदूषित कर देते है। पक्षियों का भी पर्यावरण में महत्त्वपूर्ण योगदान है। हम भूल गये सादगीपूर्ण जीवन से ही सतत विकास संभव है।

जलवायु परिवर्तन में हमारी आदतें जिम्मेदार हैं। बढ़ते प्रदूषण, दूषित जल, कटते जंगल, बंजर होती धरा को थोड़े से बदलाव से बचा सकते हैं। पानी की बोतलें, कॉफी कप्स, पेपर नैपकीन, टिशू पेपर, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम कर हम पेड़ों को बचा सकते है। आज हम विकास, जीवन व प्रकृति को एक ही पैमाने से समझते है। हवा, मिट्टी, जंगल, पृथ्वी के संतुलन में वन व पर्यावरण की अहम भूमिका है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया सबके विकास विनाशकारी सिद्ध होने लगे हैं। पालने वाली प्रकृति अब विनाश पर उतर आई है। समझने, संभलने का

वक्त आ गया है। यदि क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग इसी तरह जारी रहे तो अनेक प्रकार के पेड़ व प्रजातियां नष्ट हो जायेंगी।

छोटे-छोटे बदलाव से बड़ा बदलाव संभव होता है। पर्यावरण संरक्षण से ही हम अपने बच्चों को अच्छा व शुद्ध वातावरण दे सकते हैं। गृहणियों को पर्यावरण सुरक्षित रखने की शुरुआत अपनी रसोई से करनी चाहिए। सिल्वर फाइल की जगह सूती कपड़ा काम में लें। पानी, बिजली की बचत करें, पेड़ पौधे लगायें, प्लास्टिक का उपयोग कम करें, कचरा निस्तारण सुचारू रूप से करें। घर परिवार में, सहकर्मियों में, स्कूल, कॉलेज, परिवहन, होटल्स में शेयरिंग से पर्यावरण की रक्षा करें। अधिक से अधिक कम्युनिटी में, बचत व बदलाव से पर्यावरण शुद्ध रखा जा सकता है। आज पूंजीवादी विकृतियां जीवन मूल्य बन रही हैं। सड़क, बांध, भवन निर्माण अनुपात में पेड़ भी लगाये जाने चाहिए।

व्यक्तिवादी नहीं बनें, सामाजिक व सामुदायिक जिम्मेदारियों को निभाएं। घर की तरह मोहल्ले को साफ रखें, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण (कचरा, मैला, गंदा पानी, फ्लश वाटर) से बचें। सोलर पावर का उपयोग करें, रहन-सहन, खानपान की आदतें बदलें, सार्वजनिक स्थान की पवित्रता बनाये रखें, पानी के स्रोत को गन्दा करना व कचरे को जलाना बन्द करें। स्नानघर में पानी को वेस्ट नहीं करें, लाल बत्ती पर मोटरवाहन को बंद करें। पुरानी कहावत थी ''घी ढुल जाये मगर पानी व्यर्थ ना जाय।'' पानी का रिसाइकल करें, पानी का बार-बार उपयोग करें, वर्षा जल बचाये, कार व फर्शों की धुलाई में पानी खर्च नहीं करें।

मनोरंजन का मुख्य स्रोत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है खेलकूद, व्यायाम, योग, सांस्कृतिक गतिविधियां बन्द हो रही है, दिखावे की मनोवृत्तियां बढ़ रही है, सस्टेनेबल फैशन नहीं रहा। पोखर, ताल, नदी प्रत्येक में गन्दगी व कूड़ा करकट प्रवाहित करते हैं, उनका पानी तो प्रदूषित होता ही है समुद्र में बहकर जाने वाला कचरा किनारों पर एकत्रित होकर वातावरण प्रदूषित व संकुचित कर रहा है। इन सभी छोटी-छोटी बातों से, मानसिक बदलाव से पर्यावरण बचाया जा सकता है। प्रकृति से जुड़े, शुरुआत करें, छोटी पहल भी कारगर साबित होगी। घर के हर हिस्से को इकोफ्रेंडली बनाये, छोटी-छोटी बातों से पर्यावरण बचाने के बड़े सबक सिखायें।

पौधारोपण हमारे लिए इच्छा का विषय बनना चाहिए ताकि प्रकृति एवं भविष्य को बेहतर बनाने के लिए यह काम आज और अभी से शुरू कर सकें। स्वयं का बगीचा तैयार करें, घर पर पौधे लगायें। ●

छाया चित्र : पद्म सैनी

इको ट्यूरिज्म के लिए आकर्षण का केन्द्र : राजस्थान

"विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत शृंख्ला अरावली के साथ ही हमारे प्रदेश में अनेक पहाड़ियां हैं। वर्षभर स्थानीय एवं प्रवासी पक्षी भारी संख्या में राज्य में आते रहते हैं। राजस्थान प्रदेश में सुनहरा थार मरुस्थल है। राजस्थान खनिजों के लिए देश का अजायबघर भी है। मरु भूमि क्षेत्र में नमकीन पानी की झीलें हैं। सांभर एवं लूणकरणसर आदि इको ट्यूरिज्म के लिए भरपूर आकर्षण के स्थल हैं। प्रदेश में ऐसे क्षेत्र भी हैं जो साल्ट फ्लैटस हैं जो खूबसूरत एवं अनोखे तो हैं ही, वन्य जीव क्षेत्र भी हैं जिनमें नैसर्गिक जैव विविधता है, जो कि इको ट्यूरिज्म का महत्त्वपूर्ण केन्द्र हैं।"

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री हेमाराम चौधरी से जनसम्पर्क अधिकारी राजेश यादव द्वारा लिए गए साक्षात्कार के महत्त्वपूर्ण अंश...

राज्य में वनों की वर्तमान स्थिति क्या है?

राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की तुलना में अभिलेखित वन क्षेत्र 9.60 प्रतिशत है तथा कुल वनावरण एवं वृक्षावरण मात्र 7.42 प्रतिशत ही है। प्रदेश की विषम परिस्थितियाँ यथा दो-तिहाई मरुप्रदेश, शुष्क जलवायु, अल्प वर्षा, वृक्षाच्छादित क्षेत्र की कमी, अत्यधिक जैविक दबाव एवं दीमक के प्रकोप के बावजूद वृक्षाच्छादित क्षेत्र में वृद्धि को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए प्राकृतिक वनों की स्थिति को स्थानीय लोगों की सहभागिता एवं वन विकास के जरिये सुधारने की नितांत आवश्यकता है, ताकि पारिस्थितिकीय एवं पर्यावरणीय संतुलन बने रहने के साथ-साथ वनों से प्रदेशवासियों के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लक्ष्यों की प्राप्ति भी संभव हो सके। राज्य सरकार इस दिशा में निरंतर प्रयासरत है। वन विभाग द्वारा वन विकास एवं वन्यजीव संरक्षण के कार्यो को स्थानीय वन सुरक्षा समिति एवं अन्य विभागों का भी सहयोग लिया जा रहा है। वन महोत्सव कार्यक्रम, जन जागरूकता शिविर, पौध वितरण, वन एवं वन्यजीव संरक्षण में उल्लेखनीय कार्य करने वाले व्यक्ति, संस्था, एन.जी.ओ, वन सुरक्षा समिति एवं विभागीय कर्मचारियों को पुरस्कृत किया जाने के अतिरिक्त घर-घर औषधि योजना, ईकोटूरिज्म को प्रोत्साहन आदि गतिविधियों के माध्यम से आमजन की भागीदारी को सुनिश्चित किया जा रहा है।

प्रदेश में वन नीति की क्रियान्विति के लिए क्या प्रयास किये जा रहे है?

वर्तमान में प्रदेश में राज्य वन नीति 2010 प्रभावी है। प्रदेश की विषम जलवायु परिस्थितियों एवं वन क्षेत्रों पर बढ़ते हुए जैविक दबाव को दृष्टिगत रखते हुए वन विभाग द्वारा राज्य वन नीति के अनुरूप निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रदेश में जनसहभागिता से संचालित वन विकास एवं वन संरक्षण के विभिन्न कार्यक्रमों हेतु लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। राज्य में नई वन नीति जल्द ही राज्य में लागू हो जाएगी। वन, वन्यजीव एवं पर्यावरण संरक्षण, संवर्द्धन एवं उन्नयन के क्षेत्र में कार्य करने वाली स्वयं सेवी संस्थाएं एवं सामाजिक संस्थाएं भी इन कार्यों से जुड़कर सहभागिता निभा सकेंगी। इस नई वन नीति के द्वारा प्रदेश में वन एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति आमजन में वनों के प्रति जागरूकता में इजाफा किया जा सकेगा।

रामगढ़ विषधारी अभयारण्य जैसे नवाचारों का प्रादेशिक पर्यटन की दृष्टि से आप क्या भविष्य देखते है?

देश-विदेश में पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान को विशिष्ट पहचान दिलाने में प्रदेश के वन्यजीव संरक्षित क्षेत्रों की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। वन्यजीव प्रबन्धन के संदर्भ में रामगढ़ विषधारी टाईगर रिजर्व, रणथंभार कन्जर्वेशन रिजर्व, शाहबाद कन्जर्वेशन रिजर्व इत्यादि अनेक सकारात्मक प्रयास राज्य सरकार द्वारा किये गये हैं। इसके अतिरिक्त आमागढ़ लेपर्ड सफारी, उदयपुर बर्ड पार्क, मरूधरा बायोलॉजिकल पार्क, बीकानेर, पुष्कर बायोलॉजिकल पार्क, अजमेर इत्यादि अनेक नये स्थल वन्यजीव संरक्षण के साथ-साथ वन्यजीव पर्यटकों को भी बढ़ावा देगा। हाल ही में सरकार द्वारा प्रदेश के जैविक उद्यानों में वास कर रहे वन्य जीवों के संरक्षण में आमजन की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से उनको गोद लिये जाने के लिए प्रारम्भ की गई है। सरकार द्वारा किये जा रहे नवाचारों से राजस्थान शीघ्र ही वन्यजीव पर्यटन में देश में अग्रणी होगा।

विविधता भरे प्रदेश में पर्यावरण पर्यटन की क्या संभावनाएं है ?

विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली के साथ ही हमारे प्रदेश में अनेक पर्वत एवं पहाड़ियां हैं। जिन पर घने जंगल है साथ ही बड़ी-बड़ी झीलें, बांध एवं वेट्लेन्डस है। वर्षभर स्थानीय एवं प्रवासी पक्षी भारी संख्या में आते रहते हैं। राजस्थान प्रदेश में सुनहरा थार मरूस्थल है। राजस्थान खनिजों के लिए देश का अजायबघर है। मरु भूमि क्षेत्र में खारे पानी की झीलें सांभर एवं लूणकरणसर ईको टूरिज्म के लिए आकर्षण का केन्द्र है। प्रदेश में ऐसे क्षेत्र भी हैं जो साल्ट फ्लैटस है जो खूबसूरत एवं अनोखे तो हैं ही, बहुत अच्छे वन्य जीव क्षेत्र भी हैं जिनमें नैसर्गिक जैव विविधता है जैसे रणथम्भौर, सरिस्का आदि। गैर वन्यजीव क्षेत्र जैसे फलोदी कुरजां प्रवासी पक्षी का निवास क्षेत्र है जो ईको टूरिज्म का महत्त्वपूर्ण स्थल है।

प्रदेश में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने की दृष्टि से राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी-2021 लागू की गई है। इसके तहत स्थानीय स्तर पर इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विभागों के समन्वय से प्राप्त सुझावों के आधार पर जिला स्तरीय योजना तैयार की जा रही है। नवीन पॉलिसी के क्रियान्वयन से जहां एक ओर स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, वहीं दूसरी ओर स्थानीय स्तर पर रोजगार में अभिवृद्धि होगी।

राज्य में वन विकास एवं पर्यावरण संरक्षण में क्या परिवर्तन आया है ?

जापान इंटरनेशनल कॉऑपरेशन एजेन्सी (जायका) के सहयोग से राज्य में इंदिरा गांधी क्षेत्र वृक्षारोपण परियोजना, अरावली वृक्षारोपण परियोजना, वानिकी विकास परियोजना, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना-प्रथम एवं राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना-द्वितीय चलाई गई हैं। परियोजनाओं में वृक्षारोपण एवं वन्यजीवों के संरक्षण तथा जैव विविधता संरक्षण के कार्य करवाये गये हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान, देहरादून द्वारा 2021 में प्रकाशित रिपोर्ट में गत 10 वर्षों में राज्य के वन क्षेत्रों में बढ़ोत्तरी हुई है, जिसके फलस्वरूप राज्य में वनों के घनत्व में लगभग 550 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है जो कि राज्य में वनों के विकास के प्रयासों का सार्थक परिणाम है।

राज्य पक्षी गोडावण के संरक्षण के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

राज्य पक्षी गोड़ावण के संरक्षण हेतु भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून के तकनीकी सहयोग से जैसलमेर जिले के सम में स्थापित केन्द्र में अण्डों की कृत्रिम हैचिंग द्वारा 18 चूजे प्राप्त किये जाकर उनका पोषण किया जा रहा है। परियोजना के अनुसार इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुये गोडावण की एक फाउण्डर पॉपुलेशन बढ़ाने का कार्य अगले एक वर्ष में पूर्ण हो जाने की संभावना है। तत्पश्चात फाउण्डर पॉपुलेशन से जन्मे गोड़ावणों को उनके संरक्षित क्षेत्रों में छोड़ा जा सकेगा। अभी तक योजना के परिणाम उत्साहवर्धक है एवं आशा है कि विश्व में राजस्थान ही इस प्रजाति के संरक्षण को सफल कर सकेगा।

जनजातीय क्षेत्रीय विकास की क्या स्थिति है ?

वन विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं यथा कैम्पा, पर्यावरण वानिकी (ईटीएफं), परिभ्रांषित वनों का पुनरारोपण, जलवायु परिवर्तन एवं मरू प्रसार रोक, भाखड़ा नहर एवं गंग नहर वृक्षारोपण, नाबार्ड, इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में पुन: वृक्षारोपण इत्यादि योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में 377.30 करोड़ रुपये व्यय किये जाकर 32442.57 हेक्टेयर भूमि पर वृक्षारोपण कार्य किया गया है। इस वर्ष 2022-23 में इन योजनाओं के अन्तर्गत 56547.64 हेक्टेयर वन क्षेत्र में जुलाई माह से वृक्षारोपण कार्य किया जायेगा।

जनजातीय क्षेत्रों में विभिन्न जनजातियों को लाभांवित करने हेतु विभिन्न योजनाओं यथा नाबार्ड, कैम्पा, परिभ्रांषित वनों का पुनरारोपण, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में 50.58 रुपये करोड़ व्यय किये गये है एवं जनजातीय क्षेत्रों में वर्ष 2022-23 हेतु विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत 53.42 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान रखा गया है। जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग (नोडल विभाग) अनुसार प्रदेश में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियम 2006 के प्रावधानों अंतर्गत माह मार्च, 2022 तक 45646 वन अधिकार पत्र (30862.28 हैक्टेयर क्षेत्र) जारी किये गये हैं। प्रदेश के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा राजस्थान पंचायतीराज (उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के संबंध में उपान्तरण) अधिनियम 1999 के नियम 2011 एवं नियम 2013 के तहत तेंदु पत्ता एवं बांस विदोहन से प्राप्त आय को राज्य वित्त आयोग पैटर्न पर अनुसूचित क्षेत्रों की ग्राम पंचायतों को सम्बन्धित क्षेत्र में विकास कार्यो हेतु हस्तानान्तरित किया जा रहा है।

प्रदूषण निराकरण के लिए प्रदेश सरकार क्या प्रयास कर रही है ?

पर्यावरण प्रदूषण रोकने के लिए राज्य के लघु स्तरीय प्रदूषक जल प्रदूषण उद्योगों के समूहों में प्रदूषित जल के उपचार हेतु राज्य में संयुक्त उपचार संयंत्र स्थापित किये गये हैं एवं उद्योगों द्वारा हैजार्डियस वेस्ट निष्पादन हेतु राज्य में दो सामूहिक उपचार व निष्पादन सुविधाएं गांव गुडली-उदयपुर व बालोतरा-बाड़मेर में स्थापित की गयी हैं। राज्य में ई-वेस्ट के उचित निस्तारण हेतु बजट घोषणा 2022-23 में राज्य सरकार द्वारा ई-वेस्ट पॉलिसी बनाने एवं ई-वेस्ट हेतु रिसाइक्लिंग पार्क विकसित करने के कार्य किये जायेंगे। साथ ही राज्य सरकार द्वारा अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों में प्रदूषण के प्रभावी उन्मूलन हेतु कार्य योजना तैयार करवाई गयी है। राज्य सरकार द्वारा राज्य के एनसीआर क्षेत्र में स्थापित उद्योगों को स्वच्छ ईंधन पर परिवर्तित किया जा रहा है। कुल चिन्हित 525 इकाइयों में से 225 इकाइयां सीएनजी में परिवर्तित हो चुकी हैं तथा 126 इकाइयां बायोमास ईंधन पर संचालित हैं। ●

वनाच्छादित क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य आरंभ

“राज्य में वनाच्छादित क्षेत्रफल को वर्ष 2040 तक तीन गुणा करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जा रहा है। इस योजना के तहत वन भूमि, चरागाह (गोचर), ओरण, सार्वजनिक स्थलों पर वृक्षारोपण के साथ-साथ राज्य के निवासियों को बड़े पौधे उपलब्ध करवाकर राज्य में हरियाली विस्तार के प्रयास किए जाएंगे।”

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री शिखर अग्रवाल से सहायक निदेशक सम्पत राम चांदोलिया से हुई बातचीत के अंश...

वन-पर्यटन की प्रदेश में क्या संभावनाएं हैं ?

जयपुर में दो लेपर्ड रिजर्व एवं एक लायन सफारी के बाद एक टाइगर सफारी शुरू की जा रही है। साथ ही रामगढ़ विषधारी में टाइगर सफारी तथा झुंझुनूं में लेपर्ड सफारी प्रारम्भ करने के प्रयास किए जा रहे है।

वन्य जीव संरक्षण के इन प्रयासों से प्रदेश में पर्यटन से क्या लाभ होंगे ?

वन्य जीव संरक्षण से न केवल क्षेत्र में हरियाली बल्कि पूरे ईको सिस्टम का विकास होता है। साथ ही पर्यटकों के आने से इन क्षेत्रों से जुड़े लोगों की आय में भी वृद्धि होती है।

रणथम्भौर एवं अन्य अभयारण्यों में बाघों की संख्या में आशातीत इजाफा हर्ष का विषय है, पर इनकी बढ़ती संख्या के चलते क्या नए सुरक्षा कदम उठाए जा रहे हैं ?

सुरक्षा हेतु आवश्यक सभी कदम उठाने के साथ नए टाइगर रिजर्व की स्थापना की जा रही है जिससे एक तरफ अधिक घनत्व वाले स्थानों पर संघर्ष कम किया जा सके वहीं दूसरी ओर अन्य स्थानों पर बाघों की संख्या में बढ़ोत्तरी की जा सके।

पर्यावरण प्रदूषण से बचाने के लिए प्रदेश सरकार क्या प्रयास कर रही है?

सभी बड़े शहरों में विशेष रूप से ध्यान देकर मैकेनिकल स्वीपिंग, वृक्षारोपण, सड़कों के किनारे इंटर लॉकिंग टाइल्स लगाने इत्यादि जैसे कार्य कराए जा रहे हैं जिससे वायु की गुणवत्ता में आवश्यक सुधार लाया जा सके।

स्वच्छता एवं ''कचरा प्रबंधन'' से पर्यावरण संरक्षण की दिशा में राज्य सरकार क्या कार्य कर रही है?

ठोस एवं तरल कचरे के साथ-साथ ई-वेस्ट के बेहतर प्रबंधन पर ध्यान दिया जा रहा है।

हाल ही में सरिस्का वन में लगी आग चर्चा का विषय बनी, वनों में लगने वाले दावानल के लिए विभाग द्वारा क्या इंतजाम किए जा रहे हैं?

बेहतर उपकरण एवं प्रशिक्षण के साथ-साथ फायर लाइन बनाने पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है।

प्रदेश में वन क्षेत्र में कितनी बढ़ोतरी हुई, आगामी वर्षा ऋतु में कितनी संख्या में पौधे लगाये जायेंगे, साथ ही उनके रख रखाव व पानी की क्या व्यवस्था होगी ?

राज्य में वनाच्छादित क्षेत्रफल को वर्ष 2040 तक तीन गुणा करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है। इस योजना के तहत वन भूमि, चरागाह (गोचर), ओरण, सार्वजनिक स्थलों पर वृक्षारोपण के साथ-साथ राज्य के निवासियों को बड़े पौधे उपलब्ध करवाकर राज्य में हरियाली विस्तार के प्रयास किए जाएंगे।

वन विभाग की नर्सरियों से किस प्रकार पौधे उपलब्ध कराये जाते है?

वन विभाग की नर्सरियों की क्षमता के अनुरूप अधिक से अधिक उपयोग के साथ यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं कि आमजन को उनकी पसंद अनुसार पौधे दिए जा सके। इस हेतु फलदार पौधों पर भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। ●

COMMUNITY PLANTATION ON WORLD ENVIRONMENT DAY THE MOUNT ABU WAY

Dr. Arun K. Sharma
Mount Abu

Common sense, which is the least common, prompts us to do what is the best we have to combat immediately the much talked about, least attended and much less done for – the global warming. In simple word anyone would counsel that planting trees is the best and the simplest way to fight this scourge of this heinous juggernaut of global warming.

Proving that it is the quality and not the quantity, the municipality of Mount Abu led by the proactive SDM Mount Abu, Kanishk Kataria, IAS, the young Chairman, the visionary Commissioner have gone all out for community, sustain plantation, that too in a devout dedicated, aesthetic manner. There are not enough words to complement them for this. Their efforts were fortified by none other than the wings of our proud defenses forces, the braves of Indian Army and courageous CRPF Soldiers. IMA Mount Abu too has put its best foot for the same, together with the green brigade if PFA Mount Abu.

They have not only seen that the best quality, tall saplings are planted, but facilities are assured to water them, till they are safe, secure, sturdy trees. The future will show the beautiful boulevards, lined by their respective varieties like Gulmohar Avenues, Amaltas Avenue. Jacaranda Avenue, Kahcnar Avenue,Bottle Brush Avenue, Harshringaar Avenue etc. Not only the roads but the long neglected prestigious park of Mount Abu, the Kamala Nehru Park has been donned up, with array of Kachnar saplings and the planters there in filled with various hued Bougainville. They have further gone to share that hence forth the roads would be named accordingly, with the loud and clear message – a tree a day, no other way. ●

Be not be the first by whom the new is tried, nor yet the last to lay the old aside. The paradigm applies in all walks of life, including the walk for environment. Walk cautiously in the precarious condition we have created with our senseless exploitation of fossil energy in the name of progress and development. The race of one-up-man-ship for protean causes has led to the pitiable, concerning plight of the suffering, threatening conditions of the beleaguered earth, which is our only home in the unfathomable universe. We have not counted are blessings, rather have squandered all the goodies so very munificently nature has provided us with .We are not reducing, reusing, recycling but are trying to talk about untested risky means just to satiate our gluttony, just like the cooling by reengineering. The idea is really fanciful but are the risk factors deeply investigated and shared?

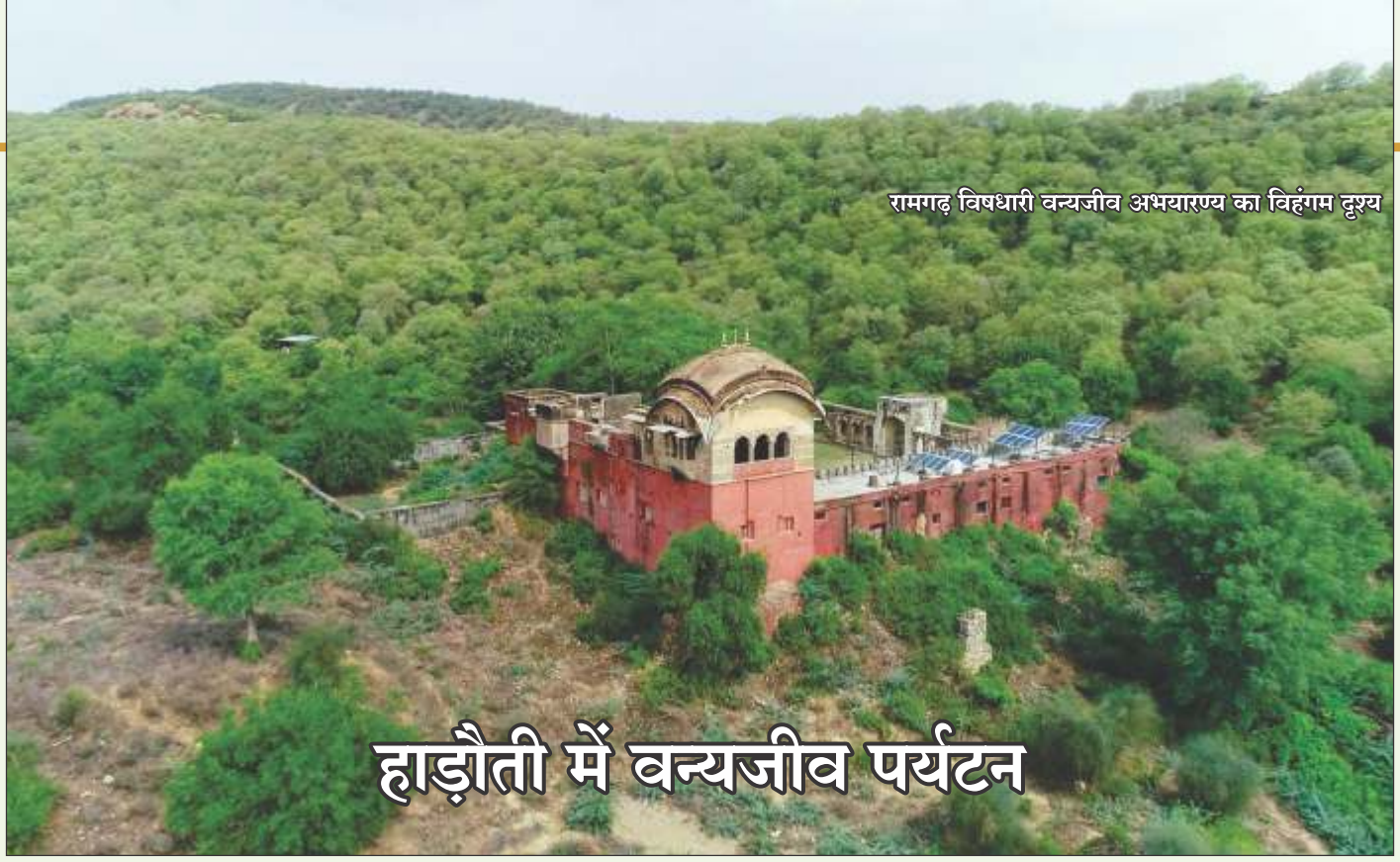

रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य का विहंगम दृश्य

हाड़ौती में वन्यजीव पर्यटन

प्रदेश का चौथा बाघ अभ्यारण्य

रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य

हाड़ौती के बूंदी जिले के रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व अभयारण्य बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। इससे पूर्व राजस्थान में रणथम्भौर (सवाई माधोपुर), सरिस्का (अलवर), मुकन्दरा (कोटा) टाइगर रिजर्व अभयारण्य थे। रणथम्भौर क्षेत्र से बाघों की स्पिलऑवर पॉपुलेशन रामगढ़ अभयारण्य क्षेत्र में आती रही है। बाघों को उपयुक्त आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा 16 मई, 2022 को नोटिफिकेशन जारी कर रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। इससे ना केवल बाघों को रहवास के लिए सुरक्षित वातावरण मिलेगा बल्कि हाडौती सहित सम्पूर्ण प्रदेश में पर्यटन के नये द्वार खुलेंगे।

इस अभयारण्य में वर्षभर हरियाली एवं जैव विविधता के साथ जल की उपलब्धता आकर्षण है। रियासत काल में बूंदी रियासत द्वारा इस अभयारण्य के विकास के साथ शिकारगाह, महलों का निर्माण भी कराया गया था। यहां की पहाड़ियों एवं जल स्रोतों में जैव विविधता के कारण आने वाले समय में यह पर्यटकों के लिए नया स्पॉट बनेगा।

रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को राज्य सरकार द्वारा 20 मई, 1982 को वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था। इस अभयारण्य का कुल क्षेत्रफल 303.43 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान राज्य की स्थापना से पूर्व ही यहां बाघ, पैंथर, स्लॉथ बीयर, सांभर, चीतल, सीवेट, बिल्ली आदि अनेक प्रकार के जीव मिलते रहे हैं।

हरिओम सिंह गुर्जर
उप निदेशक, जनसम्पर्क, कोटा

इस क्षेत्र में विन्ध्यांचल के तीखे पहाड़ की मौजूदगी है और साथ में अरावली के शंकुनुमा पहाड़ियाँ भी स्थित है। रामगढ़ अभयारण्य को बाघों का ''जच्चा घर'' भी कहा जाता है। रणथम्भौर में पाये जाने वाले बाघों की जन्म स्थली रामगढ़ को ही माना जाता है। रामगढ़ अभयारण्य का मुख्य आकर्षण बाघों की उपस्थिति एवं बाघों का इस क्षेत्र से जुडाव है। वर्तमान में यहां रणथम्भौर टाइगर रिजर्व से एक नर बाघ टी-115 गत दो वर्षो से निवास कर रहा है। यह प्रदेश के दो टाइगर रिजर्व रणथम्भौर टाइगर रिजर्व एवं मुकन्दरा हिल्स टाइगर रिजर्व के मध्य स्थित है तथा वन्यजीवों के सुरक्षित आवागमन में कोरिडोर का कार्य करता है।

प्रशासनिक व्यवस्था

यह अभयारण्य वन मण्डल वन्य जीव कोटा के क्षेत्राधिकार में आता है। जिसको प्रशासनिक दृष्टि से रामगढ़ रेंज एवं जैतपुर रेंज में बांटा गया है। यहां पर सहायक वन संरक्षक, दो रेंज एवं आठ नाके क्रमश: खटकड़, पिपल्या माणक चौक, विषधारी, खरियाड़ी रजवास, झरपीर, शिकार बुर्ज रामगढ़ भैरूपुरा, धैलाई, गुढ़ा मकदूदा, चम्पा बाग एवं बूदी की नंगी पहाड़ियां आते हैं। इसके बफर वन क्षेत्र में भीलवाड़ा जिले का 9548 हैक्टेयर वन क्षेत्र भी सम्मिलित है।

अभयारण्य में वनस्पति एवं वन्य जीव की स्थिति

अभयारण्य की मुख्य वनस्पति प्रजातियों में धौंक, सालर, बबूल, पलाश, गुर्जन, खैर, जामुन, अमलताश, खेजड़ी, पीलू, लहसोडा आदि है। वन्यजीवों में अभयारण्य का शीर्ष परभक्षी बाघ है, इसके अलावा पैंथर, भालू, स्ट्रिप्ड हाईना, सीवेट, जैकाल, जंगली बिल्ली, लोमड़ी, जंगली सूअर, लंगूर, नीलगाय, खरगोश सहित झाउ चूहा, चीतल, सांभर आदि है।

अभयारण्य में सरीसृप भी काफी संख्या में पाये जाते है, जिनमें कोबरा, क्रेत, रैट स्नेक, रॉक पायथन, कीलबैक आदि। मेज नदी एवं अन्य पानी के स्रोत के कारण यहां पर मार्श क्रोकोडाइल, टर्टल एवं कछुए भी अच्छी मात्रा में पाये जाते हैं। मेज नदी को अभयारण्य की जीवन रेखा माना गया है। अभयारण्य में विभिन्न प्रकार के स्थानीय एवं प्रवासी पक्षी निवास करते हैं। जिनमें से मुख्य रूप से क्रेन, स्टोर्क, स्नाईप, वैगटेल, गीज, किंग फिशर, रूडिशैल डक आदि हैं।

अभयारण्य के अंदर स्थित ग्राम–

अभयारण्य की सीमा के अन्दर कुल 9 ग्राम बसे हुए हैं, जिनमें भैरूपुरा, केशवपुरा, भीमगंज, जावरा, हरिपुरा, गुलखेड़ी, गुढ़ामकदूका, दलेलपुरा एवं धूंधलाजी का बाड़ा शामिल है। ●

वर्ष 2022 के वाटर हॉल की वन्यजीवों की गणना के अनुसार वन्य जीवों की संख्या:–

न.	वन्य जीव का स्थानीय नाम एवं जूलोजिकल नाम		संख्या
1	बाघ	Tiger (Panthera tigris)	1
2	बघेरा	Panther or Leopard	12
3	सियार/गीदड़	Jackal (Canis aureus)	26
4	जरख	Hyaena (Hyaena hyaena)	18
5	जंगली बिल्ली	Jungle Cat (Felis chous)	5
6	लोमड़ी	Fox (Vulpes bucapus)	5
7	भेड़िया	Indian Wolf (Canis lupus Pallipes)	6
8	भालू	Sloth Bear (Melursus ursinus)	18
9	बिज्जू छोटा	Small Indian Civets (Viverra cibetha)	12
10	बिज्जू बड़ा	Large Indian Civet (Viverra cibetha)	5
हर्बीवोर			
1	चीतल	Chital (Axis axis)	96
2	सांभर	Sambar (Cervus unicolor)	40
3	काला हिरण	Black Buck (Antelope cervicapra)	1
4	रोजड़ा/नील गाय	Nilgai (Boselaphus tragocamelus)	472
5	जंगली सूअर	Wild pig (Sus scrofa)	148
6	सेही	Indian porcupine (Hystrix indica)	19
7	लंगूर	Semnopithecus	414
	कुल		1296
पक्षी			
1	गिद्ध	Indian Longbilled Vulture	21
2	जंगली मुर्गी	Grey Jungle fowl (Gallus sonneragti)	6
3	मोर	Peacock	1136
4	कुल		1163
	कुल सभी		2459

आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत एवं मौजूद लोग

आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व बनेगा देश भर में नजीर

आलोक आनन्द
सहायक निदेशक, जनसम्पर्क

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत प्रदेश में वन्यजीवन और पर्यावरण को समृद्ध बनाने के लिए बेहतर कदम उठा रहे हैं। रामगढ़ विषधारी टाइगर प्रोजेक्ट के कदम ने पूरे देश में राजस्थान का गौरव बढ़ाया है। पर्यावरण संरक्षण के लिए पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय की स्थापना की गई है। राजस्थान वन विकास निगम का गठन किया गया है। नई राजस्थान पारिस्थितिकी पर्यटन नीति-2021 लागू की गई है। इसी दिशा में एक और ऐतिहासिक कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री ने आमागढ़ लेपर्ड सफारी का शुभारंभ किया है। जयपुर में झालाना लेपर्ड सफारी के बाद यह दूसरी लेपर्ड सफारी होगी।

आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व बनेगा जयपुर का नया आकर्षण

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 22 मई, 2022 को अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व वन एवं वन्यजीव संरक्षण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। जयपुर देश का अकेला ऐसा शहर है जहां दो लेपर्ड सफारी है। आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व और झालाना लेपर्ड रिजर्व। वन खंड का कुल क्षेत्रफल 16.36 वर्ग किमी है। अरावली पर्वत शृंखलाओं पर स्थित आरक्षित इस वन खण्ड में आमागढ़ 1524 हैक्टेयर में फैला हुआ वन क्षेत्र है। यह सफारी प्रदेश के पहले लेपर्ड रिजर्व झालाना व नाहरगढ़ अभयारण्य के मध्य स्थित है। इसकी भौगोलिक स्थिति दो महत्त्वपूर्ण वनक्षेत्रों के बीच में स्थित होने के कारण यह वन क्षेत्र वन्य जीव संरक्षण एवं कॉरिडोर

विकास की दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बन जाता है। आमागढ़ वन खण्ड से लगते हुए ही आरक्षित वन खण्ड लालबेरी 112 हैक्टेयर क्षेत्र में स्थित है। इनकी पैरिफेरी करीब 28.6 किलोमीटर है। लेपर्ड यहां का प्रमुख वन्य जीव है। आमागढ़ वन क्षेत्र में लगभग 15 लेपर्ड हैं।

इस वन क्षेत्र में लेपर्ड के साथ ही अन्य वन्य जीव भी प्रचूर मात्रा में पाए जाते हैं, जिनमें मुख्यत: हायना, जैकाल, जंगली बिल्ली, लोमड़ी व सीवेट कैट हैं। शाकाहारी वन्य प्राणियों में सांभर, नीलगाय, खरगोश आदि वन्य प्राणी हैं। यह वन क्षेत्र एक उष्ण कटिबन्धीय, मिश्रित 'पतझड़' मानसूनी वन क्षेत्र है। यहां मुख्यत: रेतीले प्लेन एरिया में टोटलिस, कुमठा, खेजड़ी पहाड़ी के ढलान पर धौंक, सालर, गोया खैर आदि वनस्पति मौजूद हैं।

पक्षियों में स्थानीय व प्रवासी पक्षी सहित करीब 250 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। मोर, तीतर, डव, बैवलर, मैना, पैराकीट, रौबिन, वुड पैकर, बुल-बुल, शिकरा आदि स्थानीय पक्षी हैं। पिट्टा, पैराडाइज पलाई कैचर, गोल्डन औरियल, पाइड कुक्कू, यूरेशियन कुक्कू, यूरेशियन रौलर, औरियन्ट स्कूप आउल, पैलिड स्कूप आउल, नौर्दन गौसौक, यूरेशियन स्पैरोहीक आदि प्रवासी पक्षी हैं जो देश-विदेश के विभिन्न कोनों से प्रजनन व भोजन की तलाश में आते हैं।

जयपुर बन सकता है लेपर्ड केपिटल आफ द वर्ल्ड

जयपुर शहर के पूर्व और उत्तर में अरावली पर्वत शृंखला है। यहां झालाना, आमागढ़ और नाहरगढ़ जैसे वन्यजीव बाहुल्य क्षेत्र हैं। ये जंगल जयपुर के 88.54 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं। इन जंगलों में करीब 85 लेपर्ड विचरण करते हैं। पिछले कुछ समय में झालाना ने दुनिया भर के वन्यजीव प्रेमियों के बीच एक अलग पहचान बनाई है।

आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व

पिछले 3 सालों में जयपुर लेपर्ड संरक्षण के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। इनकी संख्या में इन प्रयासों की वजह से अच्छी बढ़ोतरी हुई है। झालाना लेपर्ड रिजर्व में वर्ष 2018 में जहां सिर्फ 20 लेपर्ड थे, वहीं इनकी संख्या अब बढ़कर 44 पहुंच गई है। इन क्षेत्रों में मृदा जल संरक्षण, ग्रासलैण्ड विकास, वृक्षारोपण, वाटर प्वाइंट्स निर्माण जैसे कार्यों से यह सुपरिणाम सामने आये हैं। आमागढ़ के विकास से इस कार्य में तेजी आएगी और जयपुर की बघेरों की वजह से प्रसिद्धि बढ़ेगी।

पिछले 3 सालों में इको टूरिज्म की तरफ पर्यटकों का रूझान बढ़ा है। वर्ष 2017-18 में जहां 15 हजार 479 पर्यटक झालाना में सफारी के लिए आए थे वहीं वर्ष 2021-22 में 25 हजार 278 पर्यटक झालाना में सफारी का आनंद उठा चुके हैं। आमागढ़ में सफारी विकसित होने पर इस संख्या में और तेजी से इजाफा होगा।

आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व का एक मनोहारी दृश्य

क्यों खास है लेपर्ड ?

लेपर्ड जिसे तेंदुआ भी कहा जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप में बाघ, शेर और स्नो लेपर्ड के बाद पाया जाने वाला चौथा सबसे बड़ा बिड़ाल है। यह अपने आप को परिस्थितियों के अनुसार ढालने की क्षमता रखता है और इसी वजह से पहाड़ी से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक पाया जाता है। पेड़ों पर चढ़ने की अपनी क्षमता के कारण यह बाघ और शेरों के क्षेत्रों में भी अपना अस्तित्व बनाए रखता है। यह एक अवसरवादी शिकारी है जो पक्षियों से लेकर हिरणों तक का शिकार आसानी से कर लेता है।

कैसे आनंद लिया जा सकता है, आमागढ़ लेपर्ड सफारी का ?

इस क्षेत्र में सफारी का आयोजन सुबह और शाम दो पारियों में किया जाएगा। पर्यटन को व्यवस्थित करने के लिए प्रत्येक पारी में सीमित संख्या में वाहनों के प्रवेश की अनुमति होगी। पर्यटकों की सुविधा के लिए सफारी टिकट ऑनलाइन उपलब्ध होंगे और बुकिंग वेबसाइट https://sso.rajasthan.gov.in पर की जा सकती है। आमागढ़ सफारी के लिए टिकट खिड़की और प्रवेश द्वार प्रसिद्ध गलता मंदिर की ओर जाने वाली सड़क पर सिसोदिया रानी बाग के ठीक आगे स्थित है। ●

हाइना

सभी छाया चित्र : सुमित जुनेजा

ताल छापर अभयारण्य में विचरण करते हुए कृष्ण मृग

ताल छापर : कृष्ण मृगों की अठखेलियां

अजय कुमार
सहायक निदेशक, जनसम्पर्क

चूरू जिले के ताल छापर कृष्ण मृग अभयारण्य में काले हिरणों की अठखेलियां अनायास ही दर्शकों का ध्यान खींचती हैं। अभयारण्य में चार हजार से अधिक काले हिरण हैं, जो देशी-विदेशी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र हैं। जैव विविधता से भरपूर इस अभयारण्य में काले हिरणों के अलावा लोमड़ी, नीलगाय, मरु लोमड़ी, चिंकारा, खरगोश, जंगली बिल्ली, मरु बिल्ली, जंगली सूअर आदि वन्यजीव हैं तथा प्रवासी पक्षियों के ठहराव का यह एक मुख्य केंद्र है। 300 से अधिक प्रजातियों के पक्षी यहां विभिन्न मौसमों में देखे जा सकते हैं। राज्य सरकार की ओर से अभयारण्य में आने वाले सैलानियों के लिए विभिन्न सुविधाएं दी जा रही हैं और आने वाले समय में सुविधाओं तथा सांस्कृतिक व पर्यटन के विस्तार से लिए जिला प्रशासन पहल पर अब यहां के ओपन थिएटर को फिर से शुरू करने, स्टार गेजिंग, केमल सफारी, स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा बनाए उत्पादों के विक्रय के लिए क्राफ्ट शॉप, कैफेटेरिया सहित विभिन्न गतिविधियों को शुरू करने की दिशा में काम किया जा रहा है। आने वाले दिनों में इसके और अधिक बेहतर परिणाम दिखाई देंगे।

ताल छापर काले हिरणों का एक प्राकृतिक आवास स्थल है। घास का यह समतल मैदान कुछ-कुछ अफ्रीका के सवाना के घास के मैदानों जैसा नजर आता है। यहां छितराए हुए खेजड़ी, देशी बबूल आदि वृक्ष हैं। अभयारण्य के पश्चिमी दिशा में गोपालपुरा ग्राम के पास कुछ पहाड़ियां स्थित हैं। ब्रिटिश काल में ताल छापर अभयारण्य बीकानेर रियासत का शिकारगाह था। अभयारण्य का रख-रखाव शिकारगाह के रूप में बीकानेर रियासत द्वारा शाही मेहमानों के लिए किया जाता था। आजादी के बाद राज्य सरकार ने 1962 में इसे वन्यजीव आरक्षित क्षेत्र घोषित कर इसमें शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध लागू कर दिया। कालान्तर में इसे अभयारण्य घोषित किया गया।

काले हिरण हैं मुख्य आकर्षण

काले हिरण अभयारण्य का मुख्य आकर्षण हैं। इसके अलावा यहां लोमड़ी, रोझ, चिंकारा, खरगोश, जंगली बिल्ली आदि पाये जाते हैं। वन्य जीवों के अलावा देशी-विदेशी पक्षियों के प्रवास स्थल के तौर पर यह अभयारण्य मशहूर है। यहां विभिन्न मौसमों में दिखाई देने वाली 200 से भी ज्यादा प्रजातियों में डेमोयजिल क्रेन (कुरजां), हेरोन, काईट, ईगल, वल्चर, सैंडग्रूज, बी-ईटर, बबलर, किंग फिशर, साइक, ब्लैक विगड स्टिल्ट, सनबर्ड, लार्कस आदि प्रमुख हैं। यहां मिलने वाले सरी सर्प वर्ग के जन्तुओं में मुख्यत: गोह, सांडा, काला नाग, गिरगिट आदि हैं।

तेज दौड़ने वाला खूबसूरत प्राणी है कृष्ण मृग

कृष्ण मृग लम्बी दूरी तक तेज दौड़ने वाला बहुत ही खूबसूरत जीव है। यह 60-80 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। इसकी खाल चिकनी और मुलायम बालों से भरी होती है। कृष्ण मृग की

कंधे तक औसत ऊंचाई 80 सेमी तथा औसत वजन 40 किग्रा होता है। नर के सींग होते हैं जो चक्राकार कंधों की ओर झुके हुए तीन-चार घुमाव लिये हुए होते हैं तथा 75 सेमी तक लम्बे होते हैं। जन्म के समय नर एवं मादा दोनों हल्के भूरे रंग के होते हैं। तीन वर्ष का होते-होते नर के सींग पूर्ण विकसित हो जाते हैं तथा ऊपरी हिस्सा काले रंग का हो जाता है। नीचे का आधा हिस्सा भूरे रंग का रहता है। काले हिरण मुख्यत: 25-30 के समूह में रहते हैं लेकिन गर्मियों में इसके 500-700 तक के झुंड भी देखे जा सकते हैं। समूह की मुखिया ज्यादातर समझदार मादा होती है। कुछ समूह सिर्फ मादाओं के, कुछ सिर्फ नर हिरणों के तथा कुछ समूहों में नर एवं मादा हिरण मिश्रित रूप से भी दिखाई पड़ते हैं। मादा हिरण 19 से 23 माह में पूर्ण विकसित हो जाती है जबकि नर हिरण को पूर्ण विकसित होने में 3 वर्ष लगते हैं। मादा हिरण शरीर एवं सुन्दरता में श्रेष्ठ नर को चुनती है। मादा अमूमन एक बार में एक ही बच्चे को जन्म देती है। बच्चा लगभग एक वर्ष तक मादा के साथ ही रहता है। गर्भकाल 150 दिन होता है। कृष्ण मृग की आयु 10-12 वर्ष तक होती है।

सर्दियों में रहता है घूमने का अनुकूल समय

वन अधिकारियों के मुताबिक, 28'27.5 उत्तर अक्षांश एवं 73'47.5 पूर्वी देशांतर पर स्थित इस अभयारण्य का तापमान सर्दियों में शून्य डिग्री तो गर्मियों में 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। मार्च से जून तक गर्मी रहती है। जुलाई से सितंबर तक वर्षा एवं अक्टूबर से फरवरी तक सर्दी का मौसम रहता है। जयपुर-सुजानगढ़-नोखा स्टेट हाईवे पर जयपुर से 215 किमी दूरी पर स्थित इस अभयारण्य में घूमने का श्रेष्ठ समय सर्दियों के मौसम में रहता है। अभयारण्य क्षेत्र में पाई जाने वाली मुख्य वनस्पति घास है जिसमें मोथ, लापला, घोडा दूब आदि मुख्य हैं। झाड़ियों में मुख्यत: बेर, लाणा आदि हैं। वृक्ष बहुत कम मात्रा में छितराए हुए हैं जिनमें खेजड़ी, देशी बबूल, केर, जाल आदि मुख्य हैं।

विदेशी होकर भी यहां के लोकगीतों में रमी कुरजां

हजारों मील का सफर तय करके ताल छापर आने वाला पक्षी डेमोयजिल क्रेन (कुरजां) अब यहां की संस्कृति का हिस्सा है। राजस्थानी लोक के प्रसिद्ध विरह गीत 'कुरजां ए म्हारो भंवर मिला दीज्यो ए...' सहित अनेक गीत इसके उदाहरण हैं। डेमोयजिल क्रेन (कुरजां) क्रेन प्रजाति में सबसे छोटी तथा सबसे ज्यादा पाई जाने वाली प्रजाति है। कुरजां की ऊंचाई लगभग 3 फीट व वजन 2-3 किग्रा होता है। यह धूसर रंग की होती है, सिर व गर्दन काले रंग की होती है। नर और मादा की पहचान जरा मुश्किल होती है। बच्चे राख जैसे सलेटी रंग के होते हैं। लाल आंखों के पीछ सुस्पष्ट कर्ण-शिखाओं से इसकी आसानी से पहचान हो जाती है। ये समूह में रहती हैं। इनकी बोली सुनकर ऐसा लगता है मानो समुद्र का कोलाहल सुनाई दे रहा है। वी-आकार में अनुशासित तरीके से कुरजां को उड़ते हुए देखकर कोई भी सम्मोहित हुए बिना नहीं रह सकता। डेमोयजिल क्रेन पश्चिम यूरोप से लेकर मध्य एशिया से पश्चिम चीन तक पाई जाती है। इनकी मुख्य आबादी मध्य एशिया, कजाकिस्तान, मंगोलिया है। कुरजां मुख्यत: सूखे घास के मैदानों (सवाना, स्टेपीज, अर्द्धशुष्क मरुस्थलीय) का पक्षी है। ये कृषि क्षेत्रों, सूखे घास के मैदानों, प्राकृतिक नमी वाले क्षेत्रों को अपने प्रवास एवं भोजन के लिए इस्तेमाल करती हैं। ये अपने अण्डे जमीन पर ही देती हैं तथा एक बार में दो अण्डे देती हैं। अण्डे की देखभाल नर एवं मादा दोनों द्वारा 27-29 दिन तक की जाती है। 55-65 दिनों में बच्चे पहली बार उड़ते हैं। कुरजां का भोजन मुख्यत: अनाज के दानें, दालें, कीड़े-मकोड़ें, पौधों के अवशेष इत्यादि हैं। ये केवल सर्दियां बिताने के लिए भारत में आती हैं। यहां पर अण्डे नहीं देती हैं। यह 250-300 के झुण्ड में सितम्बर-अक्टूबर माह में आना शुरू होती हैं तथा फरवरी-मार्च के महीने में यहां से वापस जाना शुरू हो जाती हैं।

नियमित सांस्कृतिक गतिविधियां शुरू करने की कवायद

अभयारण्य में विभिन्न सुविधाएं सरकार की ओर से दी जा रही हैं। ताल छापर में वन विभाग का विश्राम गृह स्थित है जिसका रख-रखाव वन विभाग द्वारा किया जाता है। अभयारण्य में वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट एवं डेजर्ट ईको-सिस्टम ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट आरम्भ हो गया है। पर्यटकों के ठहरने हेतु इनमें छः कमरों की सुविधा उपलब्ध है। छापर-सुजानगढ़ स्टेट हाईवे अभयारण्य को दो भागों में बांटता है। अभयारण्य में घूमने, निरीक्षण एवं गश्त हेतु कच्चा ट्रेक बना हुआ है। यहां एक ओपन एयर थिएटर बना हुआ है, जिसमें नियमित सांस्कृतिक गतिविधियां शुरू करने की कवायद चल रही है। यहां स्विस टैंट लगाया गया है तथा कैमल सफारी, क्राफ्ट शॉप आदि शुरू किए जा रहे हैं। ●

कृष्ण मृग

अभेड़ा बायोलोजिकल पार्क, कोटा

अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क

राजेश यादव
जनसम्पर्क अधिकारी, वन विभाग

रेंज अभेड़ा की स्थापना वर्ष 2012 में वन मण्डल कोटा के वनखण्ड सकतपुरा का 309.06 हेक्टेयर क्षेत्र जोड़कर किया गया था। इसमें 143 हेक्टेयर क्षेत्रफल में अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क प्रस्तावित किया गया जिसके प्रथम चरण का कार्य वर्तमान में पूर्ण हो चुका है। अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क को तीन ब्लॉक्स में विभाजित किया है, क्रमश: प्रशासनिक ब्लॉक, मेन ब्लॉक एवं ग्रीन बेल्ट। प्रशासनिक ब्लॉक में कार्यालय भवन, आवासीय भवन एवं अन्य प्रशासनिक भवन प्रस्तावित है। मेन ब्लॉक में बायोलॉजिकल पार्क का निर्माण किया गया है, जहां पर वर्तमान में चिड़ियाघर के वन्य जीव एवं अन्य चिड़ियाघरों से लाये गये वन्य जीव रहेंगे। तृतीय ब्लॉक में 33 हैक्टर वन भूमि में ट्रेंचिंग ग्राउण्ड के प्रभाव को एवं आस-पास के क्षेत्र में वायु प्रदूषण को कम करने के लिये ग्रीन बेल्ट विकसित की गई है। वर्तमान में यहां 20,000 पौधे लगाये जा चुके हैं। अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क के समीप अभेड़ा महल तथा अभेडा तालाब स्थित हैं, जो कि पर्यटन की दृष्टि से दर्शनीय स्थल हैं।

निर्माण कार्य की स्थिति

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क कोटा का मास्टर ले आउट प्लान अनुमोदन उपरान्त नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की बैठक में यू.आई.टी. को कार्यकारी एजेन्सी नियुक्त करने का निर्णय लिया गया। यू.आई.टी. सचिव एवं वन विभाग के मध्य एम.ओ.यू. किया गया।

अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क कोटा को विकसित करने हेतु प्रथम चरण के लिये 20 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये। मेन ब्लॉक में 44 एनक्लोजर बनाये जाने है जिसमें प्रथम चरण के अन्तर्गत वर्तमान में 13 एनक्लोजर क्रमश: टाइगर, पेंथर, लॉयन, जैकाल, इण्डियन फॉक्स, इण्डियन वुल्फ, स्लॉथ बीयर, हायना, सांभर, चीतल, चिंकारा, ब्लैक बक, नीलगाय एवं सर्विस रोड, वाटर ड्रेनेज से सम्बन्धित कार्य पूर्ण हो चुके हैं। नगर विकास न्यास कोटा द्वारा अभेडा बायोलॉजिकल पार्क के प्रथम फेज में 13 एनक्लोजर का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।

अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क, कोटा

अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क में पर्यटकों हेतु मूलभूत सुविधाएं जैसे पेयजल, शौचालय, बैठने की सुविधा इत्यादि विकसित कर दी गई हैं। अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क में प्रवेश हेतु टिकटिंग प्रणाली भी विकसित कर दी गई है। पर्यटकों की सुविधा एवं वन्यजीवों के प्रति रूचि पैदा करने के लिए जगह-जगह पर प्रदर्श बोर्ड भी लगाये गये हैं। कुछ वन्यजीव जैसे टाइगर, लॉयन, स्लोथ बीयर, इंडियन फॉक्स को दूसरे चिड़ियाघर से लिये जाने की प्रक्रिया चल रही है।

अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क का मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा लोकार्पण किया गया। आमजन के लिए पार्क खोल दिया गया है।

अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क से संबंधित मुख्य बिन्दु:-

- केन्द्रीय चिडियाघर प्राधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा अभेडा बायोलॉजिकल पार्क कोटा के स्थापना की स्वीकृति 1 दिसम्बर 2021 से दी जा चुकी है। केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, नई दिल्ली से इसकी मान्यता हेतु आवेदन (फोर्म-1) निर्धारित शुल्क के साथ भिजवाया जा चुका है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 1743 दिनांक 15.03.2022 से आवेदन में संशोधन कर पुन: केन्द्रीय चिडियाघर प्राधिकरण, नई दिल्ली को भेजा जा चुका है। वांछित कार्यवाही केन्द्रीय चिडियाघर प्राधिकरण, नई दिल्ली से अपेक्षित है।
- अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क, कोटा में दूसरे चिड़ियाघर से वन्यजीव लाने हेतु प्रस्ताव केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, नई दिल्ली को भिजवाया गया है। सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, उदयपुर से इंडियन

अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क, कोटा

फॉक्स एवं एक नर लॉयन, नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, जयपुर से एक टाइगर एवं नगालैण्ड जूलोजिकल पार्क, नगालैण्ड से हिमालयन बियर लाने हेतु प्रस्ताव केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, नई दिल्ली को पूर्व में भेजे गये हैं, जिस पर कार्यवाही अपेक्षित है। ●

अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क, कोटा

अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क, कोटा का अवलोकन करते हुए पर्यटक

छाया चित्र : हरिओम सिंह गुर्जर

सरिस्का बाघ अभयारण्य

The Tale of the Striped: Reminiscing Sariska's History

Rajesh Kumar Gupta, IFS,
Secretary to Chief Minister

I am nestled in the oldest fold mountain ranges of Aravallis, formed approximately 2 billion years ago, in Pre-Cambrian era. Let me dive into the depths of time and take you on a journey of my glory, downfall, struggle and success- my journey from zero to 25 tigers in a span of 14 years, as I am about to celebrate the 14th anniversary of my rebirth in 2008.

My forests became turning points in the lives of individuals and institutions. PadmaShri Kailash Sankhala lamented after shooting his first Tiger from a machan on an Acacia tree in Madhogarh, Sariska. Humbled in guilt, he touched the tiger's body to beg his pardon and promised never to repeat the murder and dedicated his life to the cause of Tiger conservation as the first Project Tiger Director of India. The debacle in 2005 changed the course of Tiger management by the National Tiger Conservation Authority, offering an opportunity to revise the conservation strategy for all the other Tiger reserves.

I am a relic of the past. The Pandavas of Mahabharata are said to have passed the secret year of their exile in my forests of the Matsya King Vairata and Pandupole. I conceal the medieval history of the Moghuls and the Maharajas in the forts of Kankwari & Bhangarh, Sariska Palace and the Shikar Oudhies. I am the land visited by Akbar and Jahangir for hunting tigers and panthers.

I was a part of the Alwar Princely State and was managed as a hunting reserve. Shooting blocks were permitted for hunting by DFO Bharatpur, in the second fortnight of the month for a mere 95 rupees for a Tiger and 55 rupees for a Leopard. Speechless animals, adults and cubs were shot, sometimes wiping the entire family. What a sport where all the rules were in the favour of the shooters. I wept silently amidst the cacophony of crimes on Sariska soil.

My Dhok and Khair forests were plundered repeatedly on rotational basis in the name of management, sole attention being swelling the forest revenue. Prior to 1900 I was managed as Roondhs (Grass reserves) and Banis (Fuel and Game preserves) Departments. Under the charge of the first forest officer of the Alwar State, Mr F L Coombs, these Departments were merged into the Forest Department in 1903. His proposal for the Coppice with Standards (CWS) system was institutionalised by his successors wherein annual coupes were marked for firewood, charcoal and katha. This resulted in exploitation and degradation of my best dhok forests by private contractors.

My green forests were spared the axe only after 1970s, even though I was declared a Reserve Area in 1955 for approx.100 sq.kms. and upgraded to a Sanctuary in 1958. In 1978 I was included in the list of Tiger Reserves by Project Tiger, 5 years after my lucky nine counterparts including Ranthambore in Sawai Madhopur. My managers said that prospects of copper mining perhaps delayed my inclusion in the Project Tiger in the initial stage.The samples of ore from nine bored holes by Geological Survey of India in 1972-73, established the metallurgy to be uneconomic and that's how my treasures were saved. Today, I flourish with one of the densest forests in Rajasthan.

I have seen the elites and commons visit me to appreciate the picturesque creation of God but I have never been given the significance like Ranthambore. Ranthambore was relieved of the pain of biotic interference by its dwellers in 1976 by relocation of 12 villages. But in Sariska, in 1966-67, two grazing camps - Kalighati and Slopka were relocated and it was only in 1976 when villages Karnakwas and Kiraska were relocated to Bandipul, Dulawa and Sirawas. My happiness was ephemeral as several relocated families returned to resettle in a new village- Naya Kundalka, putting a jolt to the efforts for the next 31 years, when Bhagani was relocated in 2007. Today I still have 26 villages housed within me inflicting biotic pressure for their survival. My

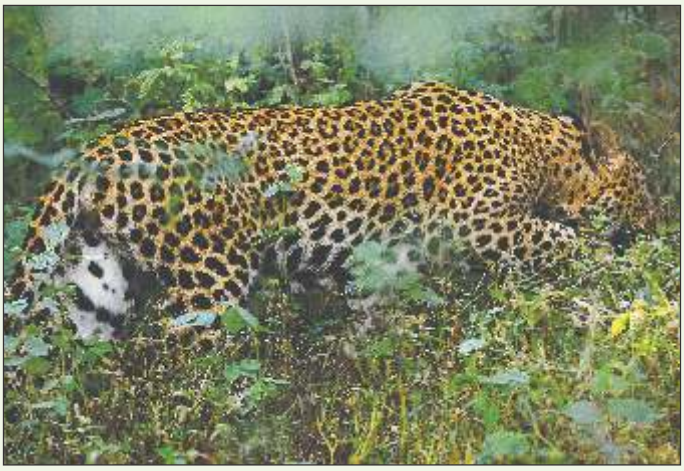

new team of protectors are trying assiduously to relocate them and I see greater progress and consequent better breeding in the Tigers.

My pristine forests were roamed by numerous Tiger fathers and mothers and their cubs. It was a heaven for them with plenty of prey supported with the nutritious Anogessius, Capparis and Zizyphus leaves. I have one of the highest prey densities among the important Tiger Reserves of the country. But from 2002 to 2004, poachers entered my home, infiltrating from various boundaries and shot the Tigers, completely exterminating the population by 2004. First they poached the Tigers and Leopards in the periphery and finally reached the heart of Sariska in Kalighati - Malajorka plateau, to kill the last tiger in 2004. They came in groups of 5-10 and laid two leg-hold traps to ensure the murder of the King. At night they would descend from the trees after hearing distressed roars of the tiger trapped in the jaw of the trap. They would then shoot the graceful beast by shooting in the mouth so that the skin was not damaged thereby fetching a good price. Leopards being smaller were beaten by sticks on the head. I could hear the echo of the gun shot in my serene valleys but my protectors did not pay heed and gradually I lost all my striped angels. Conservationists used terms "Tigerless Sariska, sariskarisation, poacher's paradise'' for the pain inflicted to Sariska. I was crucified and maligned internationally by tiger conservationists due to the negligence of my protectors, greed of the poachers and and vengeance of the villagers.

The dark days from November 2004 to June 2008 were spent in agony thinking of the zenith of my glory and the nadir of its downfall. A team of dedicated men entered and I could feel vibrations of hope that would relieve me of my curse. Suddenly there were activities buzzing in my area. Night patrollings on foot and vehicles with high beam search lights lifted my spirits. There were frequent raids in the villages along my fringes with arrests of dreaded poaching gangs, revamping of the protection framework and scientific monitoring of the Tiger's distant cousin with rosette marks,who were now the Kings of Sariska, roaming even in areas they dared not enter when the Tiger was inhabiting in the Kingdom. With good fodder in my forests, the prey population especially Sambar, increased in number thereby augmenting the large prey availability. AJT John Singh, a dedicated scientist, who would visit me almost every year from WII would say,"Sambar Conservation is Tiger conservation".

After a gap of 3.5 years, I could see the preparations for two 1 hectare enclosures at Nayapani. For the first time helicopters landed on my soil. Finally on the auspicious day of 28th June 2008, the MI 17 helicopter landed amidst rains and unloaded the most prestigious cargo in Tiger Conservation history. At 1.13 pm the King set foot in his lost kingdom and there was joy in my forests. There were louder alarm calls of the sambars, chitals and the langurs. I could feel the echoes in my valleys. The melancholy turned to melodies. I wept as the rain poured onto the soil of a historic massacre, for that day, Sariska was reincarnated.

The male tiger ST 1 was joined by his paramour ST2 tigress on 4th July 2008. Together they roamed in my wilderness and in 2012, I could see the first two cubs. I was on my way to resurrection now. Till date, Sariska has been supplemented by 9 tigers over a span of 11 years from Ranthambore and the progeny has increased by 26. Sadly I lost 3 cubs and seven adults but I am surviving with 25 tigers. Researchers say that due to anthropogenic disturbances the stress conditions to the reintroduced Tigers, especially females, in my wilderness areas have resulted in high faecal glucocorticoid metabolite (f GCM) concentrations, leading to low reproductive abilities. My counterpart in Panna also faced the same shame after me. Tigers were reintroduced in 2009, a year after my reincarnation, but due to its large inviolate spaces, the population has crossed 60 in a span of 13 years.

I dream of protection to my core natal areas for Tiger mothers giving birth to more cubs.I dream to see a litter size of 4 for the Tigers of Sariska which is presently 2 to 2.5. I dream to see the carrying capacity of Tigers increase to fifty. I long to see villages from the Core Area relocated and the villagers leading better lives outside my borders, with secured livelihoods. I must live.

फोटो फीचर

जैव विविधता

राजस्थान की सदानीरा नदी चम्बल के आस–पास जैव विविधता देशी–विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करती है। अलग–अलग मौसम में अलग–अलग प्रजाति के पुष्प जहां धरा को रंगीन बनाते हैं, वहीं नदी एवं आस–पास के जलस्रोतों में जीव–जन्तुओं की अठखेलियां पर्यटकों को अनायाश ही रोमाचिंत करती हैं।

छाया चित्र : हरिओम सिंह गुर्जर

पर्यावरण संरक्षण की अलख

कल, आज और कल

सिर साटे, रूंख रहे, तो भी सस्तो जांण

डॉ. गोरधन लाल शर्मा
राजस्थान प्रशासनिक सेवा

पर्यावरण का सीधा-सरल अर्थ है प्रकृति का आवरण। कहा गया है कि प्राणी जगत को चारों ओर से ढकने वाला प्रकृति तत्व, जिनका हम प्रत्यक्षत एवं अप्रत्यक्षत, जाने या अनजाने उपभोग करते हैं तथा जिनसे हमारी भौतिक, आत्मिक एवं मानसिक चेतना प्रवाहित एवं प्रभावित होती है। यह पर्यावरण भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तीन प्रकार का कहा गया है। स्थलीय, जलीय, मृदा, खनिज आदि भौतिक, पौधे, जन्तु, सूक्ष्मजीव एवं मानव आदि जैविक एवं आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक आदि सांस्कृतिक तत्त्वों की परस्पर क्रियाशीलता से समग्र पर्यावरण की रचना और परिवर्तनशीलता निर्धारित होती है।

पृथ्वी सभी मनुष्यों की ज़रूरत पूरी करने के लिए पर्याप्त संसाधन प्रदान करती है, लेकिन लालच पूरा करने के लिए नहीं। प्रयास करें कि जब आप आये थे उसकी तुलना में पृथ्वी को एक बेहतर स्थान के रूप में छोड़ कर जाएं। एक देश जो अपनी मिट्टी को नष्ट कर देता है वह खुद को नष्ट कर लेता है। जंगल हमारी भूमि के फेफड़े हैं, वे हमारी हवा को शुद्ध करते हैं और लोगों को नयी ताकत देते हैं।

प्राचीन भारत में पर्यावरण संबंधी चेतना

भारतीय संस्कृति में प्रकृति की रक्षा पर जोर दिया गया है। लोक जीवन में वृक्ष पूजा, वन संरक्षण का ही उदाहरण है। अनेक वृक्ष, जिनमें नीम, पीपल, वट, शमी और तुलसी शामिल हैं, पवित्र माने जाते हैं। औषधीय विशेषताओं के कारण इन सबका महत्त्व रहा है। इसलिए इनकी सुरक्षा की जाती है और आज भी इनकी पूजा होती है। बड़े और छोटे वृक्षों के संरक्षण की कामना अनेक प्राचीन ग्रंथों में की गई है। वृक्ष संरक्षण की अभिलाषा आज तक बरकरार है। घर-घर में नीम, तुलसी का होना, इसी धारणा को पुष्ट करता है। पीपल दिन-रात ऑक्सीजन का उत्सर्जन करता है तथा प्रदूषित वायु को अमृततुल्य बनाता है।

हमारे दर्शन और संस्कृति में प्रकृति को बहुत ही आदरपूर्ण और सम्मानजनक स्थान दिया गया है। मनुष्य प्रकृति का विजेता नहीं है, प्रकृति केवल उसके उपभोग के लिए रची हुई नहीं है। सम्पूर्ण सृष्टि पवित्र है और पर्यावरण की रक्षा सबका कर्तव्य है, ये बातें आम आदमी में कई सदियों से मान्यता प्राप्त हैं। अनेक समुदायों में वृक्षों को बचाने की परम्परा है, जो इसी विश्व दृष्टि का परिणाम है।

वैदिक काल में वायुमण्डल को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए यज्ञ

अथवा अग्निहोत्र जैसे कर्मकाण्ड की चर्चा मिलती है, जो नित्य दिनचर्या में सम्मिलित था। यह प्रश्न उठता है कि जहाँ प्रकृति के प्रति, अपने पर्यावरण के प्रति ऐसी दृष्टि हो, वहाँ भी सम्पूर्ण विश्व के साथ-साथ नए-नए पर्यावरणीय संकट कैसे सामने आ रहे हैं? इसके उत्तर में सर्वप्रथम यह कहा जा सकता है कि पर्यावरण को किसी एक देश की सीमा से आबद्ध नहीं किया जा सकता है। इस पर समष्टिगत दृष्टि से ही विचार करना उचित है।

ऋषि-मुनियों ने न केवल पर्यावरण को प्रदूषित करने से मानव जीवन एवं सृष्टि पर पड़ने वाले हानिकारक विनाशक परिणामों की ओर संकेत किया, अपितु पर्यावरण की रक्षा एवं हम जो कुछ प्रकृति से प्राप्त कर रहे हैं, उसे उन्हें लौटाकर, पर्यावरण को प्रदूषित करने की अपेक्षा, उसे संरक्षित एवं संवर्धित करने का भी आदेश दिया है। इस प्रकार शास्त्रों में सम्पूर्ण प्राकृतिक शक्तियों को शान्त करने व लोक कल्याणकारी बनाए रखने की प्रार्थना की गई है। हमें यह हमारे पूर्वजों से उत्तराधिकार में नहीं मिला, ये हमें अपने बच्चों से उधार में मिला है।

हमारे शास्त्रों में पर्यावरण संरक्षण

प्रकृति के पंचमहाभूत- क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर- भौतिक एवं जैविक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। वेदों में भी मूलत: इन पंचमहाभूतों को ही दैवीय शक्ति के रूप में स्वीकार किया गया है। इसीलिए गीता में भगवान कृष्ण ने प्रकृति के पाँच तत्वों के स्थान पर आठ तत्त्वों का उल्लेख किया है। शास्त्रों में कहा गया है कि ईश्वर को प्रकृति में, जानवरों में, पक्षियों में और पर्यावरण में पाया जा सकता है।

वेदों में पर्यावरण से सम्बन्धित अधिकतम ऋचाएँ यजुर्वेद तथा अथर्ववेद में प्राप्त होती हैं। ऋग्वेद में भी पर्यावरण से सम्बन्धित सूक्तों की व्याख्या उपलब्ध है। अथर्ववेद में सभी पंचमहाभूतों की प्राकृतिक विशेषताओं और उनकी क्रियाशीलता का विषद् वर्णन है। आधुनिक विज्ञान भी प्रकृति के उन रहस्यों तक बहुत बाद में पहुँच सका है जिसे वैदिक ऋषियों ने हजारों वर्ष पूर्व अनुभूत कर लिया था। इतना ही नहीं, वेदों में प्राकृतिक तत्त्वों से अनावश्यक और अमर्यादित छेड़छाड़ करने के दुष्परिणामों की ओर भी संकेत किया गया है तथा मानव को सीख भी दी गई है कि पर्यावरण सन्तुलन को नष्ट करने के दुष्परिणाम समस्त सृष्टि के लिए हानिकारक होंगे।

यजुर्वेद में जैव-विविधता के संरक्षण की दृष्टि से एक महत्त्वपूर्ण ऋचा मिलती है, जिसमें कहा गया है, वे जो नैतिक मर्यादाओं को स्वीकार करने की इच्छा रखते हों, यह वायु उनके लिए सुखकर हो, जल धाराएँ उनके लिए सुखकर हों, यहाँ तक कि ये वनस्पतियाँ नीति परायण जीवन-यापन करने वाले हम सबके लिए सुखकर हो जाएं। रात हमारे लिए सुखकर हो और भोर भी हमारे लिए सुखकर हो, हे सृष्टिकर्ता! हमारे लिए पृथ्वी और स्वर्ग सुखकर हो जाएं, वन देवता हमारे लिए सुखकर हो जाएं, सूर्य हमारे लिए सुखकर हो जाएं और धेनु हमारे लिए सुखकारी हो जाएं।

अथर्ववेद के भूमि-सूक्त में पृथ्वी को माँ की संज्ञा दी गई है। पृथ्वी को माँ मानने से और संवेदना से ओत-प्रोत होने से पर्यावरण प्रबन्धन के लिए कुछ बचता ही नहीं। भारतीय चिंतन परम्परा में पारिस्थितिकी के संरक्षण हेतु वृक्ष (जंगल) का महत्त्व मानव जीवन में सर्वाधिक है। यहाँ वृक्षों को देवता मानकर उसकी सेवा करने की सोच अपनाई गई है।

उपनिषदों में भी अग्नि, जल, वायु, आकाश आदि को सम्मानजनक स्थान प्रदान कर इसकी महत्ता को स्वीकार किया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि तत्कालीन ऋषियों को न केवल पर्यावरण की महत्ता का ज्ञान था, बल्कि वे इसके संरक्षण को भी प्रश्रय देते थे। मनुस्मृति में कहा गया है कि वृक्षों में भी चेतना होती है तथा वे भी सुख-दुख का अनुभव करते हैं। इसको सर जगदीश चन्द्र बोस के वैज्ञानिक प्रयोगों ने सिद्ध भी कर दिया है जिसे विश्व समुदाय ने स्वीकार भी किया है।

वृक्षों के प्रति नई पीढ़ी में ऐसी जागरूकता जरूरी

मरुस्थल के औरण – परम्परागत संरक्षण

थार मरुस्थल के बीच बसे सरहदी जिले जैसलमेर में पर्यावरण संरक्षण लोक जीवन का अभिन्न हिस्सा है। हजारों वर्षों से यहां के महत्त्वपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रों जैसे कुछ घास मैदानों, घने कंटीले वृक्षों से आच्छादित क्षेत्रों, बरसाती नदियों के कैचमेंट, यहां के विशेष खड़ीन खेतों के आसपास, मन्दिरों और वीर झुंझारों के देवस्थानों के चारों तरफ की जमीन को औरण के नाम से सुरक्षित छोड़ने की परम्परा रही है। परंपरा व मान्यताओं के अनुसार यहां पेड़ों को काटना तो दूर टहनी तक उठाना पाप माना जाता है।

औरण सदियों से अपने आसपास के गांवों को मौसमी बेर, कैर, सांगरी, कुम्भट जैसे देसी फलों, शहद, गोंद, पत्तियों, छाल, जड़ी-बूटियों, चारा, घास इत्यादि की उपलब्धता को सुनिश्चित करने का काम करते रहे हैं। इन औरणों के होने के कारण यहाँ पर प्राचीन समय में लोग, कई-कई वर्षों तक पड़ने वाले अकालों में भी पेड़ों की छाल और जंगली घासों के बीज खाकर जिंदा रहते थे।

लोकजीवन में प्रचलित मान्यताओं में इन औरणों में पेड़ काटने और खेती करने पर प्रतिबंध रहा है, इस बात पर विश्वास नहीं करने पर माना जाता है कि औरण से सम्बन्धित देवी-देवताओं का प्रकोप किसी प्रकार की अनहोनी लाता है, जिसको शांत करने के लिये देवस्थानों पर चांदी के पेड़ चढ़ाने का प्रचलन भी रहा है। अधिकांश औरणों के देवस्थानों से जुड़े होने के कारण, रियासतकाल में इनमें वन्यजीवों का शिकार भी प्रतिबंधित था, इस कारण आज भी कुछ औरणों में गोडावण, चकारा और प्रवासी पक्षियों की आवाजाही बनी रहती है। जैसलमेर जिले की अधिकांश बरसाती जल धाराएं व नदियां, किसी न किसी औरण से ही निकल कर रास्ते के विभिन्न गांवों के भू-जलस्तर, तालाबों और खडीनों में वर्षाजल को नियंत्रित करती हैं। इन औरणो में मौजूद प्राचीन पेड़ आंधी तूफान व बरसात में भी मिट्टी के अपरदन को रोकने का महत्त्वपूर्ण कार्य करते हैं।

औरण – इको पर्यटन की प्रबल संभावनाएं

पर्यावरण से जुड़े लोग मानते हैं कि जैसलमेर के प्राचीन औरण महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पर्यावरण धरोहर हैं, जिन्हें भावी पीढ़ियों के लिये सुरक्षित रखना और इन्हें नेचर हेरिटेज के रूप में मान्यता दिलवाकर इको पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करना महत्त्वपूर्ण है। कुछ प्रमुख प्राचीन और विशेष औरण -भादरियाराय

चीतल

छाया चित्र : अशोक गुरवा

औरण, देगराय औरण, आशापुरा औरण देवीकोट, श्रीपाबूजी औरण, मालणबाई औरण, कालेडूंगरराय औरण, पन्नोधराय औरण, आईनाथजी औरण, हड़बूजी औरण, नागणेची औरण, नागाणाराय औरण, जियादेसर औरण, सोहड़ाजी औरण, डूंगरपुरजी औरण, बिकनसी जी औरण, भोपों की औरण, पाबूजी औरण, योद्धा डूंगरपीर जी का औरण, जानरा गांव में स्थित मालण बाई जी का औरण जैसलमेर की स्थापना से भी पुराना है।

रोटू गांव – पर्यावरण संरक्षण की गौरवशाली परंपरा

राजस्थान के नागौर जिले में एक गांव रोटू ने पर्यावरण संरक्षण की मिसाल कायम की है। यहां लोगों के घरों में वन्य जीव स्वच्छंद होकर घूमते हैं, इस गांव में पेड़ों की परिवार के सदस्य की तरह देखभाल की जाती है। रोटू में पर्यावरण संरक्षण की गौरवशाली परम्परा 550 साल से चली आ रही है। किसी जमाने में इस गांव और आसपास के रेतीले इलाके में एक भी पेड़ ऐसा नहीं था, जिसकी छाया में लोग बैठ सकें। ग्रामीणों की इसी परेशानी को दूर करने के लिए इस गांव में आए गुरु जंभेश्वर महाराज ने 550 साल पहले एक रात में खेजड़ी के 3700 पेड़ लगाकर पर्यावरण संरक्षण का पहला बीज रोपा था। इस परंपरा को अब गांव के युवा और बुजुर्ग बखूबी निभा रहे हैं. उस समय लगाए गए खेजड़ी के पेड़ आज भी सुरक्षित हैं।

अब हर साल एक हजार पेड़ लगाने की मुहिम जारी है। पेड़ की छंटाई पर भी यहां पाबंदी है। साथ ही गांव में हो रहे सड़क या मकान निर्माण के बीच यदि कोई पेड़ आता है तो उसे काटा नहीं जाता है, बल्कि उस निर्माण की प्लानिंग में बदलाव कर दिया जाता है। पेड़ों के साथ ही वन्य जीवों की सुरक्षा को लेकर भी इस गांव के ग्रामीण खास तौर पर सजग हैं। यही कारण है कि इस गांव की सीमाओं में चिंकारा और काले हिरण जैसे वन्य जीव खेतों में और घरों के आसपास स्वच्छंद विचरण करते दिखाई पड़ते हैं। रेतीले टीलों के बीच रोटू गांव की सीमा में खड़े खेजड़ी के हजारों हरे-भरे पेड़ वीर योद्धाओं की भांति खड़े दिखाई देते हैं। जो रेतीले रेगिस्तान के तमाम हमलों को झेलकर भी यहां के लोगों को जीवटता और कभी हार नहीं मानने का संदेश दे रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा इस गांव के आसपास 112 हैक्टेयर में रोटू वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया।

प्रमुख पर्यावरण आंदोलन

भारत में विकास के साथ-साथ पर्यावरण आधारित संघर्ष भी बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि विकास नीति पर्यावरणीय संतुलन को खतरे में

राज्य वृक्ष : खेजड़ी

छाया चित्र : सविता चौहान

डालकर बनायी जा रही है। जबकि सतत या टिकाऊ विकास (Sustainable Development) की अवधारणा आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के समन्वय का मुफीद समाधान है। लेकिन आर्थिक विकास पर्यावरण पर हावी हो रहा है। सार्वजनिक नीति में परिवर्तन के माध्यम से पर्यावरण की रक्षा के लिए होने वाले विरोध को पर्यावरण आंदोलन कहा जा सकता है। हरित आंदोलन या पर्यावरण आंदोलन को पर्यावरण के संरक्षण या विशेष रूप से पर्यावरण के प्रति झुकाव वाली राज्य नीति के सुधार के लिए एक सामाजिक आंदोलन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, सार्वजनिक नीति में परिवर्तन के माध्यम से पर्यावरण की रक्षा के लिए होने वाले विरोध को पर्यावरण आंदोलन बोला जा सकता है।

• बिश्नोई आंदोलन

बिश्नोई भारत का एक धार्मिक सम्प्रदाय है जिसके अनुयायी राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तरप्रदेश और मध्यप्रदेश आदि प्रदेशों में पाये जाते हैं। श्रीगुरु जम्भेश्वर (1451-1536) को बिश्नोई पंथ का संस्थापक माना जाता हैं जिन्हें जम्भोज़ी के नाम से भी जाना जाता हैं। इस सम्प्रदाय के संस्थापक ने अपने अनुयायियों के लिए 29 नियम दिये। 'बिश्नोई' दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है: बीस + नौ अर्थात जो उनतीस नियमों का पालन करता है। इन्हीं 29 नियमों अर्थात बीस और नौ के कारण ही इस सम्प्रदाय का नाम बिश्नोई पड़ा। लोग उन्हें भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं। उनके 120 शब्द प्रमाणिक रूप से उपलब्ध हैं, जिन्हें पांचवां वेद कहा जाता है। जम्भोजी ने कहा था - 'जीव दया पालणी, रूंख लीलो न घावें' जिसका अर्थ है - ''जीव मात्र के लिए दया का भाव रखें, और हरा वृक्ष नहीं काटें''

यह आंदोलन वनों की कटाई के खिलाफ 1700 ईस्वी के आसपास ऋषि सोमजी द्वारा शुरू किया गया था। उसके बाद अमृता देवी ने आंदोलन को आगे बढ़ाया। विरोध में बिश्नोई समुदाय के 363 लोग मारे गए थे। जब इस क्षेत्र के राजा को विरोध और हत्या का पता चला तो वह गाँव गये और माफी मांगी तथा क्षेत्र को संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया। उल्लेखनीय है कि यह कानून आज भी मौजूद है।

• अमृता देवी का खेजड़ली आंदोलन

सन् 1730 में राजस्थान के मारवाड़ में खेजड़ली नामक स्थान पर जोधपुर के महाराजा द्वारा हरे पेड़ों को काटने से बचाने के लिए, अमृता देवी ने अपनी तीन बेटियों आसू, रत्नी और भागू के साथ अपने प्राण त्याग दिए। उसके साथ 363 से अधिक अन्य बिश्नोई खेजड़ी के पेड़ों को बचाने के लिए शहीद हो गए। खेजड़ली का नाम खेजड़ी (प्रोसोपिस सिनेरेरिया) पेड़ों से लिया गया है, जो गाँव में बहुतायत में थे। अमृता देवी ने राजा के सैनिकों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, क्योंकि बिश्नोई धर्म में हरे पेड़ों को काटना मना है। इसलिए अमृता देवी पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान भी देने को तैयार थीं। उन्होंने कहा कि - सिर साटे, रूंख रहे, तो भी सस्तो जांण। अर्थात ''यदि किसी व्यक्ति की जान की कीमत पर भी एक पेड़ बचाया जाता है, तो भी वह सही है।''

इन्हीं उपदेशों का पालन करते हुए अमृता देवी पेड़ों को बचाने के लिए पेड़ से चिपक गई जिसके बाद महाराजा के सैनिकों द्वारा कुल्हाड़ी से वार करने पर उनकी मृत्यु हो गई। अमृता देवी के बलिदान के बाद उनकी तीनों बेटियों ने भी पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी। यह खबर पूरे गांव और और बिश्नोई समाज में आग की तरह फैल गई जिसके बाद कुल 363 लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान का बलिदान दिया। अंत में हार मानकर राजा के सैनिकों को वापस जाना पड़ा। यह खबर जब महाराजा अभय सिंह के पास पहुंची तो उन्होंने तुरंत ही पेड़ों को ना काटने का आदेश जारी कर दिया और सैनिकों को दंडित भी किया। उन्होंने पूरे बिश्नोई समाज को आश्वासन दिया कि उनके क्षेत्र में अब कोई पेड़ नहीं कटेगा। राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार के वन विभाग ने जंगली जानवरों के संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण में योगदान के लिए प्रतिष्ठित राज्य स्तरीय अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार शुरू किया है। पुरस्कार में नकद 25000 रुपये और प्रशस्ति पत्र शामिल हैं।

• चिपको आन्दोलन

यह एक पर्यावरण-रक्षा का आन्दोलन था जो भारत के उत्तराखण्ड राज्य (तब उत्तर प्रदेश का भाग) में किसानो ने वृक्षों की कटाई का

विरोध करने के लिए किया था। वे राज्य के वन विभाग के ठेकेदारों द्वारा वनों की कटाई का विरोध कर रहे थे और उन पर अपना परम्परागत अधिकार जता रहे थे। श्री सुंदरलाल बहुगुणा और श्री चंडी प्रसाद भट्ट इस आंदोलन के नेता थे। इस आंदोलन की सबसे उल्लेखनीय विशेषताएं महिलाओं की भागीदारी थी।

- **अप्पिको आंदोलन**

यह आंदोलन भी चिपको आंदोलन की तरह पर्यावरण संरक्षण के लिये चलाया गया एक क्रांतिकारी आन्दोलन था। या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो उत्तर का चिपको आंदोलन दक्षिण में 'अप्पिको' आंदोलन के रूप में उभरकर सामने आया था। यह आंदोलन अगस्त, 1983 में कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ क्षेत्र में शुरू हुआ था। यह आन्दोलन वनों की सुरक्षा के लिए कर्नाटक में पांडूरंग हेगडे के नेतृत्व में शुरू हुआ था।

- **साइलेंटघाटी आंदोलन**

केरल की शांत घाटी 89 वर्ग किलामीटर क्षेत्र में है जो अपनी घनी जैव-विविधता के लिए मशहूर है। यहाँ कुंतीपूंझ नदी पर एक परियोजना के अंतर्गत 200 मेगावाट बिजली निर्माण हेतु बांध का प्रस्ताव रखा गया था। केरल सरकार इस परियोजना के लिए बहुत इच्छुक थी लेकिन इस परियोजना के विरोध में वैज्ञानिकों, पर्यावरण कार्यकर्ताओं तथा क्षेत्रीय लोगों के स्वर गूंजने लगे। इनका मानना था कि इससे इस क्षेत्र के कई विशेष फूलों, पौधों तथा लुप्त होने वाली प्रजातियों को खतरा है। इसके अलावा यह पश्चिमी घाट की कई सदियों पुरानी संतुलित पारिस्थितिकीय को भारी हानि पहुँचा सकता है। सरकार को 1985 में इसे राष्ट्रीय आरक्षित वन घोषित करना पड़ा।

- **जंगल बचाओ आंदोलन**

इस आंदोलन की शुरुआत 1980 में बिहार से हुई थी। बाद में यह आंदोलन झारखंड और उड़ीसा तक फैल गया। 1980 में सरकार ने बिहार के जंगलों को मूल्यवान सागौन के पेड़ों के जंगल में बदलने की योजना पेश की। इसी योजना के विरुद्ध बिहार के सभी आदिवासी कबीले एकजुट हुए और उन्होंने अपने जंगलों को बचाने के लिए एक आन्दोलन चलाया। इसे 'जंगल बचाओ आंदोलन' का नाम दिया गया था। कई पर्यावरणविद इस आंदोलन को ''राजनैतिक लालच का खेल और लोकलुभावनवाद'' कहते हैं।

- **नर्मदा बचाओ आंदोलन**

यह आंदोलन भारत में चल रहे पर्यावरण आंदोलनों की परिपक्वता का उदाहरण है। इसने पहली बार पर्यावरण तथा विकास के संघर्ष को राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनाया जिसमें न केवल विस्थापित लोगों बल्कि वैज्ञानिकों, गैर सरकारी संगठनों तथा जनता की भी भागीदारी रही। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध परियोजना का उद्घाटन 1961 में पूर्व प्रधानमंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू ने किया। तीन राज्यों-गुजरात, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान के मध्य एक उपयुक्त जल वितरण नीति पर कोई सहमति नहीं बन पायी। 1969 में, सरकार ने नर्मदा जल विवाद न्यायधिकरण का गठन किया ताकि जल संबंधी विवाद का हल करके परियोजना का कार्य शुरू किया जा सके। पर्यावरणविदों और स्थानीय लोगों ने 1985 से हाइड्रो-बिजली के उत्पादन के लिए नर्मदा पर बांधों के निर्माण के खिलाफ विरोध शुरू कर दिया था, जिसे नर्मदा बचाओ आंदोलन के नाम से जाना जाता था। मेधा पाटकर इस आंदोलन की नेत्री रही हैं, जिन्हें श्रीमती अरुंधति राय, श्री बाबा आमटे और श्री आमिर खान का समर्थन मिला।

- **टिहरी बांध विरोधी आंदोलन**

टिहरी बांध उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में भागीरथी और भिलंगना नदी पर बनने वाला एशिया का सबसे बड़ा तथा विश्व का पांचवां सर्वाधिक ऊँचा (अनुमानित ऊँचाई 260.5 मी) बांध है। इसके निर्माण की स्वीकृति 1972 में योजना आयोग ने दी थी। ऐसा अनुमान है कि टिहरी जलविद्युत परिसर के पूर्ण होने पर यहाँ से प्रतिवर्ष 620 करोड़ यूनिट बिजली का उत्पादन होगा जो दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों के लोगों को बिजली तथा पेयजल की सुविधा उपलब्ध करायेगा। इस परियोजना का श्री सुंदरलाल बहुगुणा तथा अनेक पर्यावरणविदों ने कई आधारों पर विरोध किया।

इस प्रकार जल, जंगल, जमीन, जीव-जंतु और जलवायु संरक्षण के लिए हमें पेड़, पानी, प्रकृति, पृथ्वी, पशु-पक्षी और पर्यावरण को बचाना ही होगा। ●

देशी विदेशी पर्यटकों को लुभा रहा है प्रदेश का इको टूरिज्म

एक क्लिक पर बुक कर सकते हैं प्रदेश में वन्यजीव अभयारण्यों की सफारी

डॉ. आशीष खण्डेलवाल
सहायक निदेशक, जनसम्पर्क

राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इसका अधिकांश भू-भाग मरु क्षेत्र है। राज्य में मौजूदा वन क्षेत्र 32,864.62 वर्ग किलोमीटर है, जो प्रदेश के भू-भाग का लगभग 9.60 प्रतिशत है।

राजस्थान की जलवायु विषम है। यहां ग्रीष्मकाल में अत्यधिक गर्मी एवं शीतकाल में अत्यधिक ठंड रहती है तथा पश्चिमी भागों में धूलभरी आंधियां एवं लू चलती है। राज्य में वर्षा की कमी रहती है। राज्य में पशुओं की संख्या मानव संख्या से अधिक है। ऐसी परिस्थितियों में राज्य में वृक्षारोपण एवं लगाए गए वृक्षों को जीवित रख पाना अत्यन्त चुनौतीपूर्ण कार्य है।

वृक्षारोपण एवं वन तथा वन्यजीव संरक्षण के प्रति समर्पित लोगों को सार्वजनिक रूप से मान्यता दिलाये जाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार तथा अन्य पुरस्कार विभिन्न श्रेणियों में प्रतिवर्ष प्रदान किये जाते हैं। राज्य के राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभयारण्यों के विकास की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है तथा 'ईको टूरिज्म' को बढ़ावा दिया जा रहा है। स्थानीय लोगों को लाभान्वित किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

जैव विविधता के लिए राजस्थान राज्य पूरे देश में लोकप्रिय है। विषम जलवायु व सीमित वन क्षेत्र होने के उपरांत भी राज्य में वन्य जीवों के संरक्षण में किये गये सतत प्रयासों के परिणामस्वरूप देश-विदेश से लाखों पर्यटक इन वन्य जीवों के स्वच्छन्द विचरण के अवलोकन के लिए राजस्थान में स्थित अभयारण्यों व राष्ट्रीय उद्यानों में आते हैं। दुनिया में लुप्त हो रहे दुर्लभ वन्य जीवों व पक्षियों को संरक्षण देने में भी राज्य का वन विभाग महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। राज्य में पांच चिड़ियाघर, 4 टाइगर रिजर्व, 27 वन्यजीव अभयारण्य एवं 15 कन्जर्वेशन रिजर्व स्थित हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल 11943.362 वर्ग किमी है। वन्य जीवों के संरक्षण के लिये विभिन्न विकास कार्य कराये जा रहे हैं।

वन एवं पर्यावरण विभाग की ओर से राज्य में नई इको टूरिज्म पॉलिसी-2021 प्रभावी की गई है। राजस्थान की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक और पारिस्थितिकीय विविधताओं के कारण प्रदेश की अर्थव्यवस्था में पर्यटन उद्योग का बड़ा महत्त्व है। सामान्य

रणथम्भोर (सवाईमाधोपुर) में सफारी का आनंद लेते पर्यटक

पर्यटन के साथ-साथ इको टूरिज्म को प्रोत्साहित कर न सिर्फ पर्यटन उद्योग को बढ़ाया जा सकता है, बल्कि प्रदेशवासियों के लिए रोजगार के अनन्य अवसर भी प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके साथ ही प्रदेश की जैव विविधता, वन और वन्य जीव संरक्षण में भी प्रदेशवासियों की सहभागिता को सुनिश्चित किया जा सकता है।

इको टूरिज्म पॉलिसी-2021

पिछले वर्षों में इको टूरिज्म परिदृश्य में व्यापक बदलाव आने की वजह से नई संभावनाएं उत्पन्न हुई हैं। इको टूरिज्म क्षेत्र में किए गए सीमित कार्यों के उत्साहवर्धक परिणाम भी सामने आए हैं। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए राजस्थान में इको टूरिज्म पलिसी-2021 को और भी अधिक प्रभावी बनाकर जारी किया है। नीति में ट्रैकिंग, बर्ड वाचिंग, हाइकिंग, बोटिंग ओवर नाइट कैंपिंग, सफारी, साइकिलिंग सहित पर्यावरण एवं पारिस्थितिकीय संरक्षण के अनुकूल सभी प्रकार की गतिविधियों को शामिल किया गया है। इस नीति के अनुसार वन, वन्य जीव एवं संरक्षित क्षेत्रों के साथ-साथ अन्य स्थानों पर भी इको टूरिज्म के कार्य स्थानीय समुदाय की भागीदारी से किया जा सकते हैं। इस नीति को राजस्थान राज्य पर्यटन नीति से समन्वय रखते हुए अगले 10 वर्षों के लिए तैयार किया गया है। इसका प्रारूपण पर्यावरण, पारिस्थितिकीय, वन्य जीव संरक्षण और जैव विविधता संरक्षण से संबधित स्थानीय नियमों, दायित्वों और सतत प्रबंधन के सिद्धांतों को ध्यान रखकर किया गया है।

पर्यटन क्षेत्र को तेजी से बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने वर्ष 2001 में 'राजीव गांधी पर्यटन विकास मिशन' की शुरुआत थी। इस मिशन ने राजस्थान में पर्यटन विकास के एक नए युग की शुरुआत की। पर्यटन विकास के लिए एक नियोजित और केंद्रित दृष्टिकोण देने के लिए, राज्य ने 2001 में 'राजस्थान की पर्यटन नीति' की भी घोषणा की, इस तरह की नीति की घोषणा करने वाले देश के पहले राज्यों में से एक बन गया। यह नीति निवेश को आकर्षित करने और घरेलू और विदेशी पर्यटकों की बढ़ती संख्या को बढ़ावा देने के लिए रोडमैप बनी।

इको टूरिज्म की दिशा में राज्य सरकार के आईटी आधारित नवाचार

प्रदेश में इको टूरिज्म को बढ़ाने और पर्यटकों को एक ही स्थान पर सभी सुविधाएं देने के लिए राज्य सरकार की ओर से एक वेब सुविधा संचालित की जा रही है। इसकी मदद से पर्यटक एक ही स्थान पर बैठे हुए अपनी मनपसंद वाइल्डलाइफ सफारी की जानकारी जुटा सकते हैं और उनके लिए टिकट भी बुक करा सकते हैं। इसके लिए न तो उन्हें किसी कतार में लगने की जरूरत होती है और न ही उन्हें परेशान होना होता है।

अरण्यक

ऑनलाइन सफारी की बुकिंग और परमिट के लिए राज्य सरकार के वन विभाग ने अरण्यक नामक सेवा शुरू की है। इसके माध्यम से पर्यटन निम्न सफारियों की बुकिंग एक ही स्थान से कर सकते हैं।

- **रणभम्भोर टाइगर रिजर्व, सवाई माधोपुर**
- **सरिस्का टाइगर रिजर्व, अलवर**
- **केवलादेव नेशनल पार्क, भरतपुर**
- **झालाना और आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व कन्जर्वेशन, जयपुर**
- **सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, उदयपुर**
- **सज्जनगढ़ वाइल्डलाइफ सेंचुरी, उदयपुर**
- **माउंट आबू वाइल्डलाइफ सेंचुरी, सिरोही**
- **एलिफेंट विलेज, जयपुर**
- **नाहरगढ़ जूलॉजिकल पार्क, जयपुर**
- **बर्ड पार्क, जयपुर**
- **माचिया बायोलॉजिकल पार्क, जोधपुर**
- **बर्ड पार्क, उदयपुर**
- **अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क, कोटा**

इस वेब सुविधा का पता है-

https://bit.ly/Arayanyak

केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान

राजस्थान के पूर्वांचल का सिंह द्वार भरतपुर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के कारण विश्व पटल पर है। 29 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले इस राष्ट्रीय अभयारण्य को विदेशी पक्षियों के प्रवास ने वर्ष 1981 में नेशनल पार्क का दर्जा दिलाया था। वर्ष 1964 के बाद से साइबेरियन पक्षियों के 400 के लगभग 100 जोड़े हर वर्ष इस उद्यान में लंबा प्रवास कर अपना वंश बढ़ाते रहे हैं। राजस्थान सरकार ने इस राष्ट्रीय उद्यान के लिए चंबल नदी से 65 एमसीएफटी व गोवर्धन ड्रेन से 450 एमसीएफटी पानी उपलब्ध करवाकर इस उद्यान की जलापूर्ति को लगभग पूरा कर दिया है। वर्ष 2021-22 के इस बजट सत्र में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के लिए चंबल नदी से डेडिकेटेड पाइपलाइन डालने की भी घोषणा की है जो कि बहुत ही सराहनीय पहल है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की घोषणा निश्चय ही वन्य जीवों के लिए जीवनदान साबित हुई है।

प्रकाश चंद्र शर्मा
वरिष्ठ पत्रकार

वर्ष 1956 में स्थापित और वर्ष 1981में राष्ट्रीय अभयारण्य का दर्जा पाने वाला यह अभयारण्य अपने आप में अनूठा है। यूनेस्को की ओर से घोषित दुनिया के हेरिटेज क्षेत्रों में से यह एक है। यहां वृक्ष, झाड़ और घास के अलग-अलग क्षेत्र भी है। सारसों के लिहाज से तो यह दुनिया का सबसे समृद्ध पक्षी उद्यान है। साइबेरिया से सारसों के झुंड 6 हजार किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय करके यहां आते रहे हैं। देशी-विदेशी कुल परिंदों की तादात यहाँ एक लाख के करीब मानी जाती रही है। यहां लगभग तीन हजार चीतल, आठ सौ सियार, तीन सौ जंगली सूअर और इतने ही अजगर व अन्य जीव-जन्तु हैं। गर्मियों के समय मे प्रवासी पक्षी अपने वतन को लौट जाते हैं और सितम्बर-अक्टूबर में घना प्रवास पर आ जाते हैं। ●

पर्यावरण संरक्षण पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत

पर्यावरण संरक्षण: पहली प्राथमिकता

पूरण मल
जनसम्पर्क अधिकारी, सीकर

प्राणी जगत के अस्तित्व के लिए पृथ्वी, आकाश, नक्षत्र, तारे, सूर्य, चन्द्र पर्वत, समुंद्र, अग्नि, हवा,पानी, खनिज, वनस्पति आदि ये सब हमें प्रकृति से नि:शुल्क उपहार स्वरूप प्राप्त होते हैं। इन्हीं का नाम पर्यावरण है। प्राणी जगत के अस्तित्व के लिए इन सभी की आवश्यकता है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। प्रकृति द्वारा इन सभी के कार्य निश्चित हैं। अत: प्रकृति के सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न होते हैं। जैसे दिन के बाद रात, सर्दी के बाद गर्मी, फिर वर्षा इत्यादि प्रकृति के परिवर्तन क्षतिपूर्ति अथवा बढ़ोतरी को सम पर लाकर संतुलित कर देते हैं।

इसी प्रकार वायु जिसमें जीवनदायिनी शक्ति होती है। उसकी भी स्वच्छता पर्यावरण की अनुकूलता के लिए परम आवश्यक है। वायु की स्तुति भी वेदों में की गई है। वायु इतनी स्वच्छ हो कि जिससे जीवों का निरन्तर सम्यक् विकास होता रहे। किन्तु वर्तमान परिस्थितियों में विकास की प्रक्रिया के साथ-साथ वायु प्रदूषण में भी तीव्रता आई है। वाहनों से निकलने वाला धुआं, कारखानों की जहरीली गैसें, कार्बन डाई ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाई ऑक्साइड, सीसा, कैडमियम आदि वायुमंडल को प्रदूषित कर देते हैं। जब वायुमंडल में बाहरी स्त्रोतों से विविध प्रदूषण यथा गैस, धूल, दुर्गन्ध, धुआं आदि इतनी मात्रा में उपस्थित हो जाये कि उसमें वायु के नैसर्गिक गुणों में अन्तर आ जाये , जिससे मनुष्य जीवों एवं प्राकृतिक सम्पदा को हानि पहुंचने लगे तो उसे वायु प्रदूषण कहते है। वायु प्रदूषण से पर्यावरण को अत्यधिक क्षति पहुंचती है व पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है, समुद्र जल स्तर में बढ़ोत्तरी हो जाती है। ओजोन परत के दुष्प्रभावित होने से मानव को कई तरह की बीमारियों से ग्रसित होने का खतरा बढ़ जाता है। पर्यावरण प्रदूषण आज सम्पूर्ण विश्व के लिए एक चिन्ता का विषय बना हुआ है। इसके लिए अनेक कारण उत्तरदायी हैं।

जनसंख्या वृद्धि प्रदूषण के कारणों में मुख्य है। जनसंख्या अधिक होने से प्रकृति का सन्तुलन बिगड़ जाता है। कृषि भूमि के विकास ओर नई तकनीक के प्रयोग से कृषि प्रदूषित हो जाती है। कीटनाशकों के प्रयोग से भूमि एवं जल का प्रदूषण बढ़ जाता है। शहरीकरण से उत्पन्न आवास की समस्या के परिणामस्वरूप वृक्षों की कटाई और खनन कार्य से धरती की सेहत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राकृतिक साधनों का विदोहन रोकना आवश्यक है। बड़े बांधों पर अधिक जोर एवं विलासितापूर्ण जीवनशैली भी पर्यावरण के लिए घातक सिद्ध हो रही है। प्रदूषण के इस विषय पर जितनी गहराई से दृष्टिपात करें, उतनी ही भीषणता दिखाई देती है। कोविड के समय ऑक्सीजन के लिए हमने अपनों को तरसते देखा है। अगर हम सब एक एक पेड़ लगाएं, तो कितने टन ऑक्सीजन बनेगी और जब तक जीवन रहेगा तब तक यह पेड़-पौधे हमें ऑक्सीजन देते रहेंगे। एक तरह से हम अपने लिए ऑक्सीजन प्लांट तैयार कर लेंगे। पर्यावरण जितना स्वच्छ होगा, उतना ही बेहतर हमारा जीवन होगा। ●

पर्यावरण प्रेमियों का महाकुंभ : खेजड़ली

सिर साठे रूंख रहे, तो भी सस्तो जांण' को चरितार्थ किया अमृता देवी बिश्नोई के महान बलिदान ने,
दुनिया का अनूठा वृक्ष मेला, पर्यावरण प्रेमियों का महाकुंभ जहाँ जुटता है।
जब वृक्षों की रक्षा के लिए एक साथ 363 शहीदों ने अपने प्राणों की आहूति दी,
तो पर्यावरण चेतना का पैगाम गूंजा और खेजड़ली दुनिया का अद्वितीय शहादत तीर्थ बन गया।

आकांक्षा पालावत
जनसंपर्क अधिकारी, जोधपुर

पर्यावरण प्रेम का एक अनूठा उदाहरण आज भी दरख़्तों में सांस ले रहा है। जोधपुर से 25 किलोमीटर दूर खेजड़ली गाँव में बसे लोगों की रगों में पर्यावरण के प्रति प्रेम का दरिया परंपरा बनकर उमड़ता रहता है। उनके इसी प्रेम और परंपरा का प्रतीक है विश्व का एक मात्र वृक्ष मेला, जो हर वर्ष भाद्रपद शुक्ल दशमी को आयोजित होता है।

यह कोई साधारण मेला नहीं है जिसे केवल परंपरा के नाम पर मनाया जाता है, बल्कि यह मेला उस महान बलिदान, उन शहीदों के स्मरण में शहादत पर्व के रूप में मनाया जाता है, जिन्होंने वृक्षों की रक्षार्थ सर्वोच्च बलिदान देते हुए अपने प्राणों की आहुति देकर अमिट इतिहास रच दिया।

समूचे विश्व में अद्वितीय पहचान रखने वाला यह वृक्ष मेला केवल जोधपुर के खेजड़ली में मनाया जाता है। इस बलिदान, इस त्याग के पीछे एक स्वर्णिम इतिहास है। एक ऐसा इतिहास जिसने संसार को यह सिद्ध करके दिखाया कि 'सर साठे रूख रहे, तो भी सस्तो जांण' केवल एक कहावत या मान्यता नहीं है बल्कि एक जीवंत उदाहरण है, जो प्रकृति एवं पर्यावरण प्रेम की अमर गाथा सदियों तक सुनाते हुए पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन के प्रति प्रेरणा का संचार करता रहेगा।

पर्यावरण संरक्षण के लिए हुए इस बलिदान की स्मृति में खेजड़ली गांव में हर वर्ष 5 जून बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है, जहाँ पर्यावरण प्रेमियों का कुंभ जुटता है। विश्व भर में यह एक मात्र वृक्ष मेले के रूप में प्रसिद्ध है। जाम्भोजी को मानने वाले बिश्नोई समाज के लोग आज भी वन और वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं।

इस महान बलिदान की कालजयी गाथा

एक साधारण महिला की यह असाधारण कहानी 18वीं सदी की है, जब मारवाड़ अर्थात जोधपुर रियासत में महल के सिपाही खेजड़ली गांव पहुंचे और खेजड़ी के वृक्ष काटने लगे। वहां मौजूद बिश्नोई समाज

बैठक में दिशा निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत

की एक महिला अमृतादेवी ने उन्हें रोका। सिपाही नहीं माने तो वह पेड़ से चिपक गई, लेकिन सिपाहियों ने उस पर भी कुल्हाड़ी चला दी। यह देखकर महिला की बेटियां आसू, भागू और रत्नी भी अन्य पेड़ों से चिपक गई, रियासत के क्रूर सिपाहियों ने इन्हें भी मौत के घाट उतार दिया।

जब यह समाचार आस-पास के गांवों में फैला तो 60 गांवों के 217 परिवारों के 294 पुरुष और 65 महिलाएं भी वृक्षों को काटे जाने का विरोध करने पहुंचे और वृक्षों की रक्षा के लिए इन सभी ने भी अपने प्राणों की बलि दे दी।

एक साथ 363 लोगों के बलिदान की सूचना जब रियासत तक पहुंची तो हतप्रभ प्रशासन ग्लानि से भर उठा और तुरंत आज्ञा वापस ली। पश्चाताप से भरे राजा ने प्रायश्चित करते हुए एक लिखित आदेश जारी किया, जिसके अनुसार मारवाड़ में खेजड़ी के वृक्ष को कभी नहीं काटा जाएगा। इस प्रकार उन 363 पर्यावरण प्रेमियों के बलिदान के फलस्वरूप आज तक मारवाड़ में खेजड़ी के वृक्ष को काटना निषेध है। खेजड़ी को मरूस्थल का कल्पवृक्ष भी कहा जाता है।

मुख्यमंत्री श्री गहलोत की घोषणा में बना खेजड़ली शहीद स्मारक

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा 2020-21 की अनुपालना में खेजड़ली शहीद स्मारक का निर्माण हुआ। इसके लिए कार्यकारी एजेंसी जोधपुर विकास प्राधिकरण ने कुल 45 लाख रुपए की लागत से यह कार्य किया। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा 3 जून 2021 को इस शहीद स्मारक का वर्चुअल उद्घाटन किया गया। खेजड़ली शहीद स्मारक की गोल संरचना के अन्तर्गत चारों ओर बड़े-बड़े शिलापट्ट बनाकर 363 शहीदों के नाम अंकित किये गए हैं।

वृक्ष संरक्षण की प्रेरणा जगाता धाम

अमृतादेवी और पर्यावरण की रक्षा में सर्वस्व न्योछावर कर देने वाले पर्यावरण सेनानियों के बलिदान का साक्षी खेजड़ली प्रकृति की पूजा का वह धाम बन चुका है जहाँ साल भर लोगों का तांता लगा रहता है। दूर-दूर से लोग यहाँ आकर इन शहीदों का पावन स्मरण करते हुए शीश झुकाते हैं और पेड़ों की रक्षा की शपथ लेकर लौटते हैं। ●

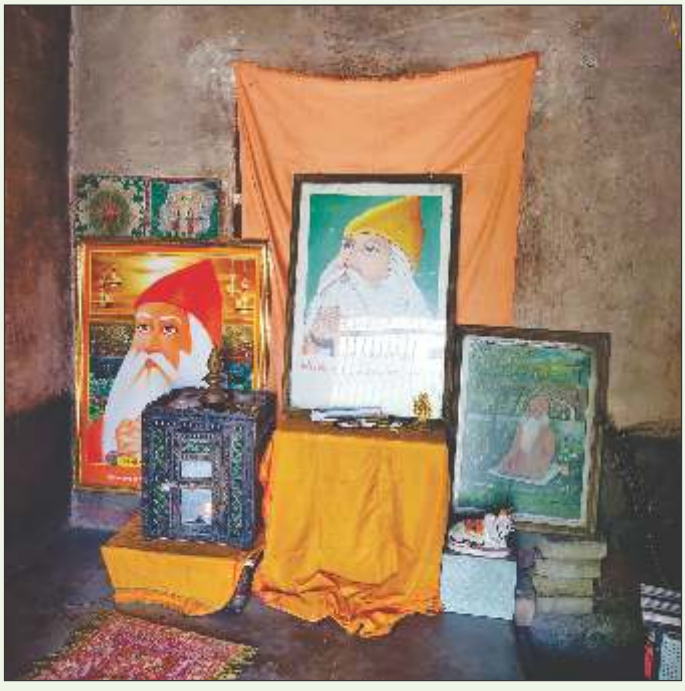

विश्व पर्यावरण दिवस

पर्यावरण जन–जागृति दौड़

उदय शंकर
सदस्य सचिव, रा.रा.प्र.नि.म.

प्रत्येक वर्ष 5 जून को पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल एवं अन्य विभागों के साथ विश्व पर्यावरण दिवस के समारोह का आयोजन करता है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, राजस्थान सरकार एवं अन्य विभागों के सहयोग से विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जिसमें मुख्य रूप से सुबह 7 बजे अल्बर्ट हॉल, रामनिवास बाग से पर्यावरण जन जागृति दौड़ का आयोजन किया गया। यह दौड अल्बर्ट हॉल से प्रारम्भ होकर त्रिमूर्ति सर्किल, जे.डी.ए. सर्किल, गांधी सर्किल, से वापस जे.डी.ए. सर्किल, त्रिमूर्ति सर्किल, होते हुए अल्बर्ट हॉल पर आकर समाप्त हुई। इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस–2022 की थीम 'ऑन्ली वन अर्थ' (Only One Earth) रखी गयी। साथ ही राजस्थान सरकार द्वारा इस अवसर पर विशेष थीम 'सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध' रखी गयी।

विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कार्यक्रम के दौरान निम्नलिखित कार्यक्रमों का शुभारम्भ किया :–

- ''स्टेट क्लाईमेंट चेंज एक्शन प्लान'' का विमोचन।
- वायु गुणवत्ता निगरानी हेतु प्रयुक्त मोबाईल वैन को हरी झण्डी दिखाकर रवानगी।
- ई–वेस्ट संग्रहण हेतु प्रयुक्त वाहनों को हरी झण्डी दिखाकर रवानगी।
- पर्यावरण जनजागृति हेतु ''रन फॉर एन्वायरमेंट'' को हरी झण्डी दिखाकर रवानगी।
- पर्यावरण जनजागृति हेतु लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने पर्यावरण प्रदूषण को लेकर आम जन को सजग किया। श्रीमती उषा शर्मा, मुख्य सचिव ने अपने सभी प्रतिभागियों से 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज़ प्लास्टिक वस्तुओं पर लगने वाले प्रतिबंध की पालना करने की अपील की साथ ही उन्होंने आम–जन से स्वेच्छा से इन सभी वस्तुओं का उपयोग आज ही से बंद करने की अपील की।

पर्यावरण जन जागृति दौड़ मे राज्य सरकार, स्थानीय प्रशासन एवं पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, वन विभाग के अधिकारी, सेना व पुलिस के जवान, एन. सी. सी. के कैडेट्स, एन.एस.एस. के स्वयंसेवक, मार्शल आर्ट्स के स्काउट एवं गाइड्स अभियांत्रिकी महाविद्यालयों के छात्र, एन.जी.ओ एवं जयपुर शहर के आमजन ने भाग लिया।

लोगों ने पर्यावरण जन–जागृति हेतु लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया गया। इस प्रदर्शनी में प्रतिबंधित सिंगल यूज़ प्लास्टिक वस्तुओं एवं अन्य विकल्पों को भी समझाया गया। दौड़ में उपस्थित

प्रतिभागियों के लिए उपवन संरक्षक उत्तर एवं जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से निःशुल्क पौध वितरण किया गया।

इस दौरान 'स्टेट क्लाईमेंट चैंज एक्शन प्लान का विमोचन किया गया। यह एक्शन प्लान मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के बजट घोषणा की अनुपालना में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल तथा आई आई टी मुंबई के सयुंक्त अनुबंध में बनवाई गयी है। वायु गुणवत्ता निगरानी हेतु प्रयुक्त मोबाईल वैन को हरी झण्डी दिखाकर रवानगी की गयी। यह मोबाईल वैन चलती-फिरती प्रयोगशाला के रूप में कार्यरत होंगी तथा आवश्यकता पड़नें पर विभिन्न स्थानों पर अस्थायी रूप से कुछ दिनों के लिये संचालित कर वहां की वायु गुणवत्ता का मापन किया जा सकेगा। वायु प्रदूषकों की मात्रा निर्धारित मानकों से अधिक पाये जाने पर कारण चिन्हित कर इसके निराकरण हेतु उचित उपाय किये जा सकते हैं जिससे कि पूरे साल वायु गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप बनी रहें।

इस दौरान ई-वेस्ट संग्रहण हेतु प्रयुक्त वाहनों को हरी झण्डी दिखाकर रवानगी की गयी। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा डोर-टू-डोर ई-वेस्ट संग्रहण हेतु जागरूकता अभियान चलाकर ई-वेस्ट के संबंध में आमजन को जागरूक किया जायेगा।

जयपुर शहर में डोर-टू-डोर जाकर ई-वेस्ट एकत्रित किया जाएगा। ई-वेस्ट के बदले में उचित मूल्य भी उपभोक्ता को दिया जाएगा। इस सुविधा के उपयोग हेतु टोल फ्री नम्बर 18001029882 पर भी कॉल किया जा सकता है या क्लीन इंडिया पोर्टल (www.cleaneindia.org) का उपयोग कर भी ई-वेस्ट दिया जा सकता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर ई-वेस्ट संग्रहण एंव जागरूकता वैन ने सिविल लाइंस (5 जून), मालवीय नगर (6 जून), गांधी नगर (7 जून), बनीपार्क (8 जून), वैशाली नगर (9 जून) में आमजन को ई-वेस्ट के नियमानुसार निस्तारण किये जाने हेतु जागरुक किया।

इसी प्रकार के जनजागरूकता अभियान राज्य मंडल के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा जिला मुख्यालय स्तर पर आयोजित किये गए।

विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने हेतु जवाहर कला केन्द्र के रंगायन थियेटर, जयपुर में पीपल्स मीडिया थियेटर के सहयोग से खेजड़ी की बेटी का मंचन किया गया।

विश्व पर्यावरण दिवस का समारोह पूर्ण रूप से पर्यावरण संरक्षण के प्रति जनजागरूकता अभियानों से भरपूर सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। ●

- **इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस-2022 की थीम 'ऑन्ली वन अर्थ' (Only One Earth) रखी गयी। साथ ही राजस्थान सरकार द्वारा इस अवसर पर विशेष थीम 'सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध' रखी गयी।**

इस दौरान राज्य में हुए निम्न शुभारम्भ-

- **''स्टेट क्लाईमेंट चेंज एक्शन प्लान'' का विमोचन।**
- **वायु गुणवत्ता निगरानी हेतु प्रयुक्त मोबाईल वैन को हरी झण्डी दिखाकर रवानगी।**
- **ई-वेस्ट संग्रहण हेतु प्रयुक्त वाहनों को हरी झण्डी दिखाकर रवानगी।**
- **पर्यावरण जन-जागृति हेतु ''रन फॉर एन्वायरमेंट'' को हरी झण्डी दिखाकर रवानगी।**
- **पर्यावरण जन-जागृति हेतु लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन।**

पर्यावरण संरक्षण की जगाई अलख

इच्छा शक्ति के साथ कार्य किया जाए तो सफलता जरूर मिलती है। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में श्री चंडीप्रसाद भट्ट ने इसे साबित कर दिखाया है। पर्यावरण संरक्षण की अलख एक छोटे से गांव से जलाई, धीरे-धीरे उसकी चिंगारी पूरे देश में फैल गई। श्रीमती सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह ने श्री भट्ट को 31वें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार से नवाजा, तब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने न केवल उन्हें बधाई दी बल्कि भट्ट के साथ अपनी तस्वीर ट्वीटर पर शेयर कर उनके साथ हुई बातचीत की जानकारी दी। उल्लेखनीय है कि इससे पहले श्री भट्ट पद्म भूषण, रैमन मैग्सेसे अवार्ड, गांधी शांति पुरस्कार सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों और सम्मान से सम्मानित हो चुके हैं।

डॉ. राजकमल पारीक
वरिष्ठ पत्रकार

- **गांधीवादी विचारक श्री चंडीप्रसाद भट्ट की मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत कर चुके हैं सराहना**
- **मुख्यमंत्री श्री गहलोत ने ट्वीटर पर साझा की थी श्री भट्ट के साथ बातचीत**

राजस्थान से रहा जुड़ाव

श्री भट्ट ने न केवल पहाड़ी इलाकों में बल्कि राजस्थान के जैसलमेर, पाली और बीकानेर जिले में मरुस्थलीय स्थिति को बदलने

को लेकर आयोजित चर्चाओं में सक्रिय रूप से भाग लिया। श्री भट्ट ने जयपुर में भी ग्राम भारती के श्री भवानी शंकर कुसुम को जिम्मेदारी सौंपी। बाद में श्री भट्ट व श्री भवानी शंकर कुसुम ने राज्य के अधिकांश जिलों में संपर्क कर मरुस्थलीकरण के विभिन्न कार्यों के लिए कमेटियां गठित की। जयपुर जिले में पर्यावरण संरक्षण व श्रमदान के लिए युवाओं व ग्रामीणों को प्रेरित किया। जमवारामगढ़ में गांधी वन बनाया गया था, तब भी काफी सक्रिय भूमिका निभाई। पाली जिले में पर्यावरण को लेकर कई आयोजन किए गए।

पर्यावरण संरक्षण के लिए संघर्ष

श्री चंडी प्रसाद भट्ट का जन्म 23 जून 1934 को उत्तराखंड के चमौली जिले में हुआ। ऋषिकेश में एक बस यूनियन के ऑफिस में क्लर्क की नौकरी करनी पड़ी। वहां भी इन्होंने बाहर की सवारियों से ज्यादा किराया वसूलने के विरोध में संघर्ष शुरू कर दिया था। नौकरी से त्यागपत्र देकर अनेक आंदोलन में से जुड़े। इसी दौरान पहाड़ों में विकास के नाम पर वृक्ष कटते देख उनका अंतर्मन कराह उठा और वह पर्यावरण की रक्षा के लिए मैदान में उतर गए। उनके गांव गोपेश्वर में संघ बनाया। उन्होंने स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों से रोजगार सृजित करने का काम शुरू किया। इसके साथ ही श्री चंडी प्रसाद भट्ट ने क्षेत्र में श्रम की प्रतिष्ठा, सामाजिक समरसता, नशाबंदी और महिलाओं-दलितों के सशक्तीकरण का कार्य किया।

चिपको से बनी पहचान

यों तो पहाड़ पर जन्मे श्री भट्ट ने पहाड़ के लोगों की सेवा में स्वयं को समर्पित कर दिया लेकिन उनकी पहचान चिपको आंदोलन से बनी है। वनों पर स्थानीय लोगों का वैधानिक अधिकार बहुत कम था। वनों के ज्यादातर हिस्सों पर ठेकेदारों का कब्जा था। ठेकेदार वनों के कानूनी हकदार थे। इस स्थिति से निपटने के लिए श्री भट्ट ने 1973 में अलग-अलग वनों के क्षेत्र में ग्रामीणों को संगठित कर उन्हें चिपको आन्दोलन के लिए तैयार किया। वनों की इस सम्पदा से वंचित होने का सबसे ज्यादा कष्ट गांव की स्त्रियों को था, भट्ट ने स्त्री वर्ग को विशेष रूप से इस चिपको आन्दोलन के लिए जोड़ा। स्वयं श्री भट्ट बताते हैं कि यह उनके लिए रोमांचकारी था। गांव की स्त्रियां एक-एक पेड़ से चिपककर उसे बांहों में भर लेती थीं और खड़ी रहती थी। इस आन्दोलन का संकेत था कि पेड़ काटने के लिए ठेकेदार के लोगों को आन्दोलनकारियों पर वार करना होगा। यह उनके लिए एक कठिन स्थिति थी। चिपको आंदोलन धीरे-धीरे पूरे उत्तराखंड में फैल गया और लोग पेड़ों को बचाने के लिए पेड़ों से लिपट गए थे। बड़ी बात यह भी थी कि इस आंदोलन में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भागीदारी की थी। इस आंदोलन में श्री भट्ट के साथ प्रसिद्ध पर्यावरणविद श्री सुंदरलाल बहुगुणा भी थे। उस दौरान वनों को बचाने के लिए लोगों ने नारा लगाया था कि क्या हैं जंगल के उपकार, मिट्टी, पानी और बयार। मिट्टी, पानी और बयार, जिंदा रहने के आधार। आंदोलन के बाद न केवल वनों की रक्षा के लिए कानून बनाया गया बल्कि पर्यावरण मंत्रालय का भी गठन किया गया। ●

श्री भट्ट को अब तक मिले ये पुरस्कार

- 1982 में रैमन मैग्सेसे पुरस्कार
- 1983 में अमेरिका का अरकांसस ट्रेवलर्स सम्मान
- 1983 में लिटिल रॉक के मेयर द्वारा सम्मानित नागरिक सम्मान
- 1986 में पद्मश्री सम्मान
- 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा ग्लोबल 500 सम्मान
- 1997 में कैलिफोर्निया में प्रवासी भारतीयों द्वारा इंडियन फॉर कलेक्टिव एक्शन

मेघड़ासर का जलाशय : पानी का खजाना

ग्रामीणों को जीवन निर्वाह का सुकून

डॉ. दीपक आचार्य
उप निदेशक, जनसम्पर्क

बरसाती पानी को अपने ही गांव में रोकने और दीर्घकाल तक सभी के लिए उपयोगी बनाने की दिशा में सरकार द्वारा ग्रामीण अंचलों में महात्मा गांधी नरेगा योजना के अन्तर्गत परंपरागत जलाशयों के जीर्णोद्धार एवं क्षमता विस्तार के लिए व्यापक स्तर पर कार्य हाथ में लिए गए हैं।

इससे एक ओर जहां जरूरतमन्द ग्रामीणों को अपने ही क्षेत्र में रोजगार प्राप्त हो रहा है वहीं गांवों में जल संरचनाओं के विकास एवं विस्तार तथा सुदृढ़ीकरण को नई रफ्तार मिल रही है। मनरेगा में अब तक बने जलाशयों में कई सारे ऐसे हैं जिनमें पानी का भराव साल भर रहने लगा है और इससे गांवों की जल समस्या पर काफी हद तक नियंत्रण पाया जा सका है, वहीं कई जलाशयों का ऐसा कायाकल्प हो उठा है कि वे अब केवल जलाशय न होकर ग्राम्य पर्यटन के नए स्थल बन गए हैं। इन्हीं में एक है मेघड़ासर का जलाशय।

जोधपुर जिले के बाप क्षेत्र अन्तर्गत मेघड़ासर ग्राम पंचायत में महात्मा गांधी नरेगा योजना के अन्तर्गत हुए कार्यों ने पुराने तालाब की काया पलट दी। कूड़ा-कचरा और गंदगी के ढ़ेर से अटे इस तालाब को फिर से आबाद करने की दिशा में ग्राम पंचायत ने प्रस्ताव लिया और 39 लाख 03 हजार रुपए की वित्तीय स्वीकृति से इसका काम मनरेगा में हाथ में लिया गया।

मन मोह रहा पानी का यह धाम

इसके अन्तर्गत जलाशय को गहरा करने के साथ ही पाल निर्माण और पिचिंग एवं घाट का निर्माण करने के बाद इसका स्वरूप निखर आया। लम्बे समय से अनुपयोगी पड़ा रहा तालाब अब ग्रामीणों के लिए बेहद उपयोगी सिद्ध हो रहा है। कुदरत ने भी इस नेक सार्वजनिक काम पर मोहर लगाते हुए मेहरबानी की और इसी का नतीजा है कि 1 लाख 20 हजार घन मीटर जल भराव क्षमता वाले इस जलाशय में जलस्तर में अपेक्षित अभिवृद्धि सामने आयी।

जलाशय के पुन: आबाद हो जाने के बाद परिवेशीय नैसर्गिक रमणीयता में भी चार चाँद लगे। अब यह तालाब पशु-पक्षियों से लेकर सभी को सुकून दे रहा है। मनरेगा में हुए कार्यों की बदौलत जलाशय में साल भर पानी रहने लगा है और गांव के लोगों को जल सुविधा प्राप्त होने के साथ ही आस-पास के क्षेत्र में कूओं का जलस्तर भी बढ़ा है।

मनरेगा का तोहफा

इससे खेती-बाड़ी के लिए सिंचाई को भी सम्बल प्राप्त हुआ है। 'जल ही जीवन है' के मूल मंत्र को साकार करता हुआ यह जलाशय महात्मा गांधी नरेगा योजना की वजह से न केवल ग्रामीणों बल्कि जीवों

और जगत के लिए सरकार का वो तोहफा है जो हर किसी को दिली सुकून का अहसास करा रहा है। इस लिहाज से यह योजना मेघड़ासर के लोगों के लिए वरदान ही सिद्ध हुई है।

पसरने लगी हरियाली, कुरजां का कलरव

जल भण्डार विकसित होने के बाद से ही पेड़-पौधों के पल्लवन का नया दौर आरंभ होने से हरियाली का विस्तार होने लगा है। विदेशी पक्षी कुरजां का कलरव और जल क्रीड़ाएं हर किसी का मन मोहने लगी हैं। आस-पास के इलाकों के ग्रामीणों तथा बाहर से पर्यटकों के लिए भी यह जलाशय आकर्षण का केन्द्र बना हुआ है।

आस्था और परिवेशीय सुकून का समन्वय

मेघड़ासर के ग्रामीण जलाशय के बहुउद्देशीय विकास से बहुत खुश हैं। उनका कहना है कि तालाब का सौन्दर्य निखरने से यह गांव और आस-पास के लोगों के लिए पर्यटन स्थल जैसे आनंद की अनुभूति कराता है वहीं घाट निर्माण की वजह से वर्षा के मौसम में यहाँ झील का जैसा माहौल नज़र आता है। तालाब पर आस्था स्थल बटुक भैरव मन्दिर व प्राचीन छतरियां और दूर-दूर तक पसरे जल सौन्दर्य के साथ ही विदेशी पक्षी कुरजां के समूहों का कलरव और मुग्धकारी क्रीड़ाओं को देखकर आत्मसंतोष व असीम मन शांति का सुकून मिलने लगा है।

आधुनिक तीर्थ के रूप में उभरा

कायाकल्प हो जाने के बाद मेघड़ासर तालाब पानी की जरूरतों को पूरा करने के साथ ही ग्राम्य विकास के आधुनिक तीर्थ के रूप में उभर रहा है और इसके लिए ग्राम पंचायत तथा गांव के लोग राज्य सरकार के आभारी हैं।

जोधपुर जिले में मनरेगा के अन्तर्गत ऐसे कई सारे काम हुए हैं जिनकी वजह से ग्राम्यांचलों में जल संरचनाओं के निर्माण से जल समस्या का समाधान करते हुए ग्राम्य विकास में कई नए आयाम स्थापित किए हैं। ●

जलाशय का सुरम्य दृश्य

मेघड़ासर जलाशय

वर्षा जल संचयन

रामजीलाल मीना
सहायक निदेशक, जनसम्पर्क

जन सहयोग से बावड़ी का पुनरूद्धार

दौसा जिले को भू-जल वैज्ञानिकों ने डार्क जोन घोषित कर दिया है। जिले के सभी उपखण्डों, तहसील एवं पंचायत समिति स्तर सहित शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या का सामना करना पड रहा है। जलदाय विभाग द्वारा टैंकरों के माध्यम से पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। जिले में कुओं एवं बावड़ियों का जल सूख गया है। जानवरों के लिये भी पीने का पानी उपलब्ध करवाना आमजन को भारी पड़ रहा है। सिंचाई के लिये भी अब पर्याप्त मात्रा में पानी नही रहा है। बोरिंग सूख गये है तथा जल स्तर बहुत नीचे जा चुका है।

जिले में जल स्तर को गिरते देख तथा पेयजल समस्या को देखकर जिला प्रशासन ने वर्षा के बहते जल का संरक्षण करने के लिये एक अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत वाटर हार्वेस्टिंग, पुराने कुओं एवं बावडियों की सफाई एवं खुदाई के कार्य को प्राथमिकता से लिया गया है। अभियान का शुभारम्भ जिले के अधिकारियों ने किला सागर दौसा में बने एनिकट की सफाई एवं खुदाई के कार्य से किया। इस कार्यक्रम में जिला कलक्टर ने स्वयं फावड़ा एवं गैंती लेकर एनिकट में खुदाई का कार्य करना चालू किया तो उनके सहयोग के लिये सभी सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस के अधिकारी एवं कर्मचारियों सहित क्षेत्रीय जनप्रतिनिधिगण एवं गणमान्य नागरिकों ने भी सहयोग प्रदान कर एनिकट की सफाई एवं खुदाई में सहयोग प्रदान किया। ग्राम पंचायत भांकरी में बालाजी वाली बावड़ी की सफाई एवं खुदाई कार्य में जिला प्रशासन के सहयोग के लिये लोगों का तांता लग गया। बावड़ी की सफाई एवं खुदाई के लिये महिला एवं पुरूषों की कतारें लगाकर पराती से मिट्टी निकालने का कार्य किया गया। इसी प्रकार जिले के सभी उपखण्ड, तहसील, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत स्तर पर अभियान को आगे बढ़ाते हुये कुओं, बावड़ी, तालाब, एनिकट आदि की सफाई एवं खुदाई का कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षा जल के संरक्षण के लिये सभी सरकारी एवं गैर सरकारी भवनों की छत के पानी को संरक्षित करने के लिये रैन वाटर हार्वेस्टिंग किया जायेगा। इसके लिये भी अभियान चलाया जा रहा है। इसमें सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों के भवनों, सरकारी कार्यालयों,गैर सरकारी संस्थानों के भवनों एवं निजी आवासीय भवनों पर भी रैन वाटर हार्वेस्टिंग करवाने का कार्य किया जा रहा है। इससें वर्षा के बहले जल को संरक्षित किया जाकर आमजन के उपयोग में लाने का कार्य किया जायेगा।

वर्षा जल संचयन

वर्षा जल संचयन या रेन वाटर हारवेस्टिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम वर्षा के पानी को जरूरत की चीजों में उपयोग कर सकते हैं। वर्षा के पानी को एक निर्धारित किए हुए स्थान पर जमा करके हम वर्षा जल संचयन कर सकते हैं।

वर्षा जल संचयन के तरीके व उपाय

वर्षा जल संचयन करने के कई तरीके हैं। इनमें से कुछ तरीके वर्षा जल का संचयन करने में बहुत ही कारगर साबित हुए हैं। संचयन किए हुए वर्षा जल को हम व्यावसायिक और साथ ही घरेलू उपयोग में भी ला सकते हैं। कुछ तरीकों से बचाए हुए पानी का हम व्यावसायिक क्षेत्र में उपयोग में ला सकते हैं।

सतह जल :- सतह जल वह पानी होता है जो वर्षा के बाद जमीन पर गिर कर धरती के निचले भागों में बहकर जाने लगता है। गंदी अस्वस्थ नालियों में जाने से पहले सतह जल को रोकने के तरीके को सतह जल संग्रह कहा जाता है। बड़े-बड़े ड्रेनेज पाइप के माध्यम से वर्षा जल को कुए, नदी, तालाबों में संग्रहण करके रखा जाता है जो बाद में पानी की कमी को दूर करता है।

छत प्रणाली :– इस तरीके में छत पर गिरने वाले बारिश के पानी को संचय करके रख सकते हैं। ऐसे में ऊंचाई पर खुले में टंकियों का उपयोग किया जाता है। जिनमें वर्षा के पानी को संग्रहण करके नलों के माध्यम से घरों तक पहुंचाया जाता है। यह पानी स्वच्छ होता है जो थोड़ा बहुत ब्लीचिंग पाउडर मिलाने के बाद पूर्ण तरीके से उपयोग में लाया जा सकता है।

बांध :– बड़े बड़े बांध के माध्यम से वर्षा के पानी को बहुत ही बड़े पैमाने में रोका जाता है जिन्हें गर्मी के महीनों में या पानी की कमी होने पर कृषि, बिजली उत्पादन और नालियों के माध्यम से घरेलू उपयोग में भी इस्तेमाल में लाया जाता है। जल संरक्षण के मामले में बांध बहुत उपयोगी साबित हुए हैं। इसलिए प्रदेश में कई बांधों का निर्माण किया गया है और साथ ही नए बांध बनाए भी जा रहे हैं।

भूमिगत टैंक :– यह भी एक बेहतरीन तरीका है जिसके माध्यम से हम भूमि के अंदर पानी को संरक्षित रख सकते हैं। इस प्रक्रिया में वर्षा जल को एक भूमिगत गड्ढे में भेज दिया जाता है। जिससे भूमिगत जल की मात्रा बढ़ जाती है। साधारण रूप से भूमि के ऊपरी भाग पर बहने वाला जल सूर्य के ताप से भाप बन जाता है और हम उसे उपयोग में भी नहीं ला पाते है। इस तरीके में हम ज्यादा से ज्यादा पानी को मिट्टी के अंदर बचा कर रख पाते हैं। यह तरीका बहुत ही मददगार साबित हुआ है। मिट्टी के अंदर का पानी आसानी से नहीं सूखता है और लंबे समय तक पंप के माध्यम से हम उसको उपयोग में ला सकते हैं।

जल संग्रह जलाशय :– यह साधारण प्रक्रिया है। बारिश के पानी को तालाबों और छोटे पानी के स्रोतों में जमा किया जाता है। इस तरीके में जमा किए हुए जल को ज्यादातर कृषि के कार्यों में लगाया जाता है।

वर्षा जल संचयन के फायदे

घरेलू काम के लिए ज्यादा से ज्यादा पानी बचा सकते हैं और इस पानी को कपड़े साफ करने के लिए, खाना पकाने के लिए, घर साफ करने के लिए, नहाने के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है। वर्षा जल को संचय करके उपयोग में लाना जल को संरक्षित करने का एक बेहतरीन उपाय है।

वर्षा जल संचयन के द्वारा ज्यादा से ज्यादा पानी एकत्र किया जा सकता है जिससे गर्मी के महीनों में कृषि से किसान पैसे कमा सकते हैं तथा पानी पर होने वाले खर्च को भी बचा सकते हैं। इसकी मदद से साथ ही ज्यादा बोरवेल वाले क्षेत्रों में पानी को सूखने से भी रोका जा सकता है। ऐसा तभी संभव हो सकता है जब वर्षा ऋतु में ज्यादा से ज्यादा वर्षा के पानी का उपयोग कृषि के लिए लगाया जाए और गर्मी के महीने में वर्षा ऋतु में बचाए हुए जल का इस्तेमाल किया जाए।

वर्षा जल संचयन किसानों के लिए सबसे कारगर साबित हुआ है। क्योंकि वर्षा के पानी को बचाकर आज ज्यादातर किसान गर्मियों के महीने में बहुत ही आसानी से पानी की कमी को दूर कर पाए हैं। ज्यादा से ज्यादा प्राकृतिक पानी को इस्तेमाल करने से स्वच्छ पीने लायक पानी को हम ज्यादा से ज्यादा बचा सकते हैं। वर्षा पानी को शौचालय के लिए, नहाने के लिए और बर्तन धोने के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग की मदद से जमा किए हुए पानी को इस्तेमाल करने से पहले अच्छे से फिल्टर किया जाना चाहिए जिससे कि इसमें मौजूद अशुद्धियां पानी से अलग हो जाए। वर्षा के पानी को ऐसे बर्तन या पात्रों में रखना चाहिए जो धूप के संपर्क में आने पर जहरीले तत्त्व ना बनाते हों। वर्षा जल संचयन द्वारा जमा किए हुए पीने के पानी को अच्छे से उबालना बहुत जरूरी है ताकि इसमें मौजूद बैक्टीरिया का सफाया हो जाए। ●

बावड़ी की साफ–सफाई करते ग्रामीण

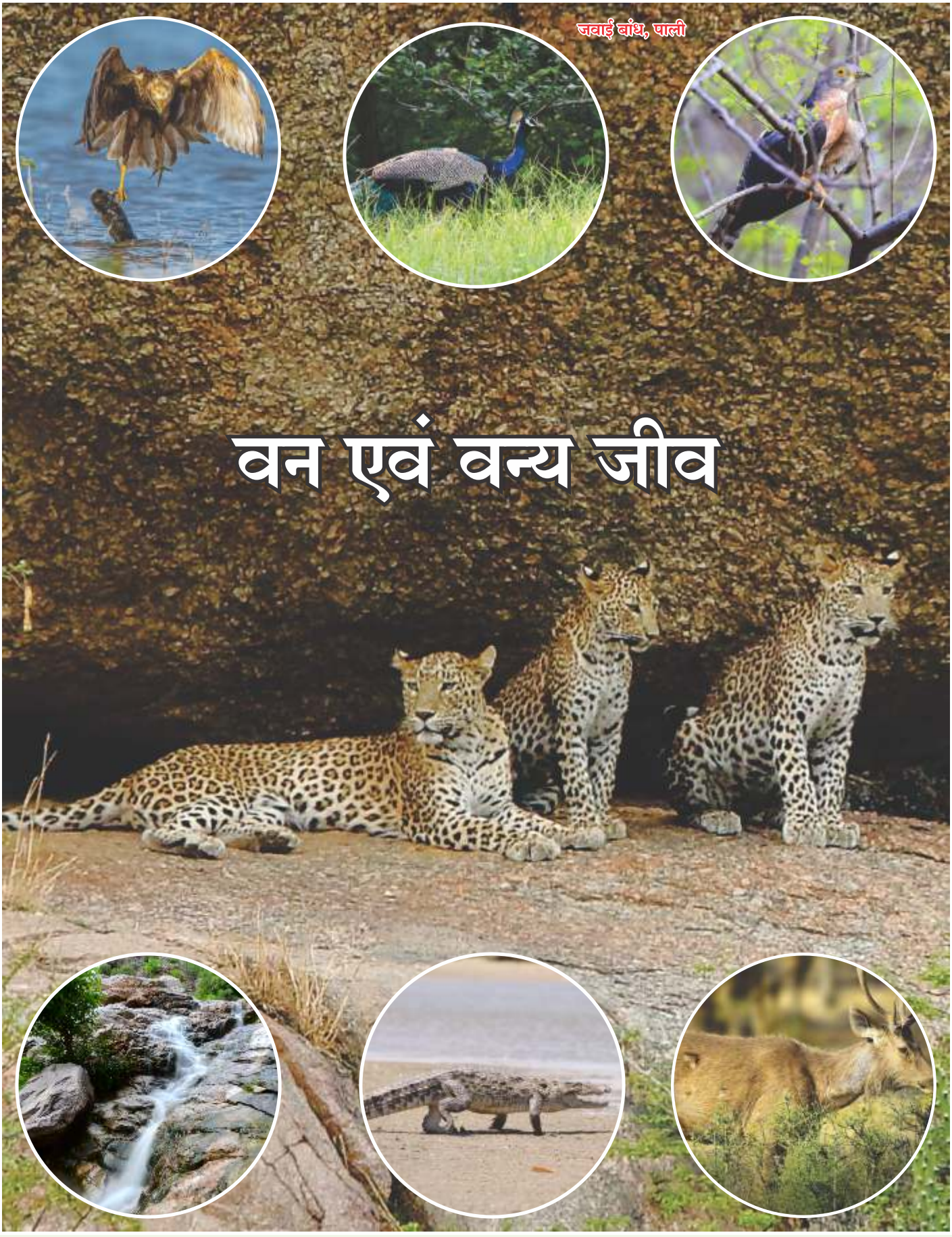

छाया चित्र : लक्ष्मण पारंगी

बच्चों के चेहरों पर मुस्कान लाने का प्रयास

वेदप्रकाश आशिया
जनसम्पर्क अधिकारी

अविनाश चौहान
ए.ए.ओ.

राज्य सरकार के बाल अधिकारिता विभाग द्वारा अनुदानित विशेष बाल गृह में एच.आई.वी. (एड्स) जैसी गंभीर बीमारी के साथ जीवन यापन करते मासूम बच्चों के मायूस चेहरों पर मुस्कान लाने का भरसक प्रयास किया जा रहा है।

जालौर जिला मुख्यालय पर समुदाय आधारित संगठन 'कम्यूनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन' के तहत विशेष बाल गृह ''वात्सल्य चाइल्ड केयर होम'' का संचालन किया जा रहा है।

मायूस चेहरों पर मुस्कान का प्रयास

विशेष बाल गृह में एच.आई.वी रोग से पीड़ित मासूम बच्चों की सेवा करने व उनके जीवन से मायूसी को दूर कर मुस्कान लाने की हर संभव कोशिश की जाती है। वर्तमान में 6 से 18 वर्ष उम्र के 27 बच्चे विशेष बाल गृह में निवासरत हैं। जिसमें से कुछ बच्चे तो ऐसे है जिनके माता-पिता दोनों नहीं हैं। इन मासूम बच्चों को पदाधिकारियों एवं कार्मिकों द्वारा जिनमें से कुछ स्वयं भी इस रोग से पीड़ित है, जीवन को हंसते-हंसते जीने की कला के साथ इस रोग के सम्बंध में बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में सिखाया जाता है। उन्हें नियमित रूप से विद्यालय भेजा जाता है ताकि वे समाज की मुख्य धारा से अपने को अलग ना समझें।

मजबूत इरादों के साथ जीवन पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देना

सभी बच्चों को अपने रोग से पीड़ित होने की जानकारी होती है। उन्हें अन्य सामान्य बच्चों के साथ व्यवहार में कुछ विशेष प्रकार से सावधानियां बरतने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। बच्चों के लिये खेलकूद, योग, संगीत एवं चित्रकारी सहित अन्य गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। कम्प्यूटर की क्लास के साथ उनके ज्ञानवर्धन व स्वास्थ्य के लिये प्रतियोगिताएं समय-समय पर की जाती हैं। उन्हें पिकनिक पर भी ले जाया जाता है। खुशनुमा माहौल में ये बच्चे कुछ हद तक अपना दर्द भूल जाते हैं। इन बच्चों के रिश्तेदार या माता पिता के साथ कभी-कभी उन्हे घर भी भेजा जाता है। इस रोग से पीड़ित होने के कारण इन बच्चों में खून की कमी, मानसिक तनाव और व्यवहार में चिड़चिड़ेपन की सामान्यत: समस्या रहती है। जिसके लिये इन्हे पर्याप्त मात्रा में पोषक आहार समय-समय पर दिया जाता है। साथ ही नियमित जांच व दवाइयों का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। केयर होम में निवासरत 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों की विशेष रूप से केयर की जाती है तथा 18 से 21 वर्ष की उम्र के बच्चे विशेष योजना के तहत यहां रह सकते हैं। वात्सल्य चाइल्ड केयर होम से निकल कर कई बच्चे जीवन पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। सही मायने में ये केयर होम मजबूत इरादों के साथ बच्चों को इस रोग के साथ जीवन पथ पर आगे बढ़ने के लिये प्रेरित कर समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करता है।

बाल अधिकारिता विभाग द्वारा समेकित बाल संरक्षण योजना के तहत प्रति बच्चों के लिये सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। संस्था में प्रवेश बाल कल्याण समिति के माध्यम से होता है। ●

ड्रोन द्वारा डिजीटल सर्वे

प्रदेश में ग्रामीण आबादी का ड्रोन सर्वे : ग्रामीणों को डिजिटल पट्टे

नवीन जैन
शासन सचिव, पंचायती राज विभाग

प्रदेशभर में ड्रोन सर्वे की सहायता से राजस्व गांवों में आबादी क्षेत्र की सम्पत्ति के डिजिटल पट्टे जारी करने सम्बन्धी 'स्वामित्व योजना' में तेजी से काम जारी है। पंचायतीराज दिवस 24 अप्रेल 2020 को प्रारम्भ हुई स्वामित्व योजना के पायलट फेज में प्रदेश के दो जिलों जैसलमेर और दौसा को शामिल किया गया था। इसके बाद यह योजना 24 अप्रेल 2021 से सम्पूर्ण देश में प्रारम्भ हो चुकी है। इसके अन्तर्गत दौसा एवं जैसलमेर के अलावा राज्य के छ% अन्य जिलों में इसे प्रारम्भ किया गया था। योजना में जैसलमेर, जयपुर, दौसा, जोधपुर, टोंक, अजमेर, बूंदी, पाली, जालौर एवं गंगानगर जिलों में ड्रोन सर्वे कार्य प्रारम्भ किया गया जिनमें दौसा में प्रथम चरण के सर्वे का कार्य पूरा हो चुका है और जैसलमेर में सैकड़ों ग्रामीणों को पट्टे जारी किए जा चुके हैं। वर्तमान में 19 ड्रोन के माध्यम से यह कार्य किया जा रहा है और आने वाले समय में ड्रोन की संख्या को बढ़ाकर 29 कर दिया जाएगा।

राजस्थान में 33 जिला परिषद, 352 पंचायत समिति, 11 हजार 304 ग्राम पंचायत एवं 46 हजार 354 राजस्व गांव हैं। इसमें से आबादी रहित राजस्व गांव ड्रोन सर्वे से बाहर रहेंगे। पांच अन्य जिलों में जल्द ही सर्वे प्रारम्भ करने के लिए प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इसके लिए टास्क फोर्स का गठन किया जा चुका है और हर सप्ताह इसकी समीक्षा की जा रही है।

स्वामित्व योजना की खास बात यह है कि डिजिटल पट्टे के लिए स्कीम के तहत आवेदन नहीं करना पड़ेगा। सरकार जैसे-जैसे सर्वे और मैपिंग का काम करती जाएगी, वैसे-वैसे लोगों को उनकी जमीन का पट्टा मिलता जाएगा। जमीन खुद के नाम होने पर गांव के लोग उसे आसानी से खरीद या बेच पाएंगे। साथ ही बैंक से ऋण आदि की सुविधा भी आसानी से मिल सकेगी। स्वामित्व योजना देशव्यापी एक बड़ी परियोजना है। इस योजना में एकत्र नक्शों और ग्रासरूट डेटा का लाभ डिजिटल पट्टों के साथ-साथ विभिन्न विकास योजनाओं में कई रूप में प्रदेश और देश को मिलेगा।

प्रदेश में औसतन ड्रोन एक सप्ताह में 14 बार उड़ान भर रहा है। फिलहाल दौसा, जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर, पाली, बूंदी, टोंक, अजमेर, गंगानगर और जालौर में 3200 से अधिक गांवों में प्रथम सर्वे किया जा चुका है। जैसलमेर में 664 पट्टे वितरित किए जा चुके हैं। अगले चरण में सिरोही, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और हनुमानगढ़ के करीब 5985 गांवों में सर्वे किया जाएगा।

इस योजना में पंचायती राज विभाग, राजस्व विभाग एवं भारतीय सर्वेक्षण विभाग संयुक्त रूप से काम कर रहे हैं। स्वामित्व योजना के अन्तर्गत सबसे पहले ग्राम पंचायत द्वारा पटवारी के सहयोग से सम्बन्धित गांव के आबादी क्षेत्र की चूने से मार्किंग करवाई जाती है। इसके बाद सर्वे ऑफ इण्डिया के सर्वेयर्स द्वारा सम्बन्धित राजस्व गांव का ड्रोन सर्वे कर हजारों चित्र लिए जाते हैं। इन इमेज के आधार पर निर्मित प्रथम नक्शा कम्पोजिट इमेज ग्राम पंचायत को सौंपी जाती है।

प्रथम नक्शा इमेज में अंकित आबादी क्षेत्र की बाहरी सीमा की जांच पटवारी एवं ग्राम विकास अधिकारी द्वारा की जाती है। आबादी के अन्दर की सीमाओं की जांच सम्बन्धित ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी, कनिष्ठ सहायक एवं दो वार्ड पंचों के द्वारा की जाती है। इस जांच में उस गांव का एक वार्ड पंच अनिवार्य रूप से शामिल रहता है। ग्राम पंचायत द्वारा घर-घर जाकर सर्वे किया जाता है।

आवश्यक संशोधन करने हेतु नक्शा सर्वे ऑफ इण्डिया को पुन: सौंपा जाता है। इसके बाद सर्वे ऑफ इण्डिया द्वारा पुन: संशोधित नक्शा द्वितीय ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराया जाता है। इसे ग्राम पंचायत अपने यहां चस्पा कर एक माह के भीतर आपत्ति मांगती है। सभी संशोधनों के बाद ग्राम सभा में इसे पास करवाकर डिजिटल पट्टे जारी किए जाने की योजना है।

विभाग का लक्ष्य है कि अगले तीन माह में 15 जिलों में ड्रोन सर्वे पूरा कर लिया जावे। सर्वे ऑफ इण्डिया द्वारा अतिरिक्त ड्रोन उपलब्ध करवाए जाने पर एक सितम्बर के बाद हर माह करीब 3 से 4 हजार

गांवों में सर्वे किये जाने का लक्ष्य है। सितम्बर, 2022 से मार्च, 2023 तक 50 ड्रोन लगातार कार्य करेंगे तथा सात माह में करीब 25 हजार अन्य गांवों में सर्वे किया जाएगा।

इस योजना के जरिए आने वाले समय में गांव के लोगों को अपनी आबादी की जमीन का मालिकाना हक मिल सकेगा। गांवों में आबादी क्षेत्र का डिजिटल डेटा एकत्र हो जाने से ग्रामीण राजस्थान और भारत के लिए योजनाएं बनाने में और उन्हें प्रदेश और देश की आर्थिक प्रगति में शामिल करने में मदद मिलेगी। धीरे-धीरे यह कदम गांवों के मास्टर प्लान बनाने की महत्त्वाकांक्षी योजना का मार्ग भी प्रशस्त करेगा। ●

ड्रोन द्वारा डिजीटल छाया चित्र

जयपुर शहर : जुलाई की आकाशीय स्थिति

सन्दीप भट्टाचार्य
सहायक निदेशक, बिड़ला तारामण्डल

संध्याकाश में शनि, देर रात बृहस्पति, और भोर में मंगल व शुक्र अपनी छटा बिखेर रहे हैं। बुध को इस माह देखना मुश्किल है। झिलमिलाते–टिमटिमाते सितारों के बीच इन्हीं पाँच ग्रहों को कोरी आँखों से हम देख पाते हैं। ग्रहों की अपनी रोशनी नहीं होती, ये सभी सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करते हैं। इनकी चमक–दमक भी दूरी के हिसाब से घटती–बढ़ती रहती है। फिर भी हर ग्रह की अपनी एक अलग रंगत होती है। यही रंगत ग्रह की ठीक–ठाक पहचान करवा देती है। एक छोटी दूरबीन या बाइनाकुलर के सहारे ये और भी आकर्षक लगते हैं। समय निकालकर कभी इन ग्रहों को पहचानने का प्रयास कीजिये। सफलता अवश्य मिलेगी। सूर्य का नजदीकी सबसे छोटा ग्रह बुध 7 जुलाई तक भोर में पूर्वी क्षितिज पर है। यह 27 जुलाई से संध्याकाश में पश्चिमी क्षितिज पर जगह बनायेगा। इसे देखने के लिए अगला महीना ठीक रहेगा। बीच के समय बुध सीधी चाल में सूर्य की प्रभा में ओझल रहेगा। सबसे चमकदार ग्रह शुक्र 'भोर का तारा' बना हुआ है।

वृषभ से मिथुन तक गतिमान यह ग्रह, पूर्वी क्षितिज पर धीरे–धीरे नीचे सरक रहा है। सुबह–सवेरे पूर्वी क्षितिज पर लगभग 20 डिग्री ऊपर दैत्यगुरु एक चमकदार बल्ब की शक्ल में नजर आ रहा है। महारथी मंगल भोर में पूर्वी क्षितिज पर काफी ऊँचाई पर है। धीरे–धीरे यह ओर ऊँचाई पर चढ़ रहा है और इसकी लालिमा भी बढ़ रही है। तारों की झिलमिलाहट खत्म होने के पहले पूर्वी क्षितिज से लगभग 55–60 डिग्री ऊपर गुलाबी रंगत में लाल ग्रह को पहचाना जा सकता है। सबसे विशाल – ग्रहराज बृहस्पति, मीन राशि में 28 जुलाई से वक्री हो रहा है। धीरे–धीरे देवगुरु संध्याकाश की ओर बढ़ रहे हैं। भोर में संध्याकाश के पश्चिमी भाग में सफेद उज्ज्वल आभा में इसे आप पहचान लेंगे। बृहस्पति तारों से काफी ज्यादा चमकदार है और एक छोटी दूरबीन से इसके इर्द–गिर्द मंडरा रहे चार चन्द्रमा भी दिख जाते हैं। संध्याकाश में शासन चल रहा है वलयधारी शनि का। वक्री शनि, कुम्भ से मकर में 12 जुलाई को वापस लौट रहा है। अंधेरा घिरते ही पूर्वी क्षितिज पर यह जरा इन्तजार के बाद नजर आ जायेगा। शनि पूरे माह पूरी रात नजर आयेगा। एक छोटी दूरबीन से इसके सुन्दर वलय भी दिख जाते हैं। चन्द्रमा 15 को शनि, 19 को बृहस्पति, 21 को मंगल के आसपास रहेगा।

चन्द्रमा 21 जुलाई को लाल मंगल को अपनी ओट में छिपा लेगा। खगोल की भाषा में इसे आच्छादन (Occultation) कहते हैं। यह नजारा भारत भूमि से नजर नहीं आयेगा। बरसात के मौसम में आसमान रूठा–रूठा सा लगता है। मानसून आते ही सितारों की चमक और आसमान की रंगत हमारी नजरों से ओझल हो जाती हैं। शनि और बृहस्पति की मौजूदगी में रात्रि आसमान की रौनक जरुर बढ़ गयी है। उत्तरी आसमान में भव्य सप्तर्षिमण्डल जरा पश्चिम में आपको दिख जायेगा। इसमें सात सितारें लगभग एक ही रंग–रुप के हैं। मानचित्र में बनाई गयी रेखा की मदद से ध्रुव तारा तक पहुँचा जा सकता है। ध्रुव तारे की चमक ज्यादा नहीं मध्यम दर्जे की ही है, लेकिन यह सदा एक ही जगह विद्यमान रहता है और ठीक उत्तर दिशा को इंगित करता है। पृथ्वी की धुरी के ऊपरी नोक कि सीध में बैठा है

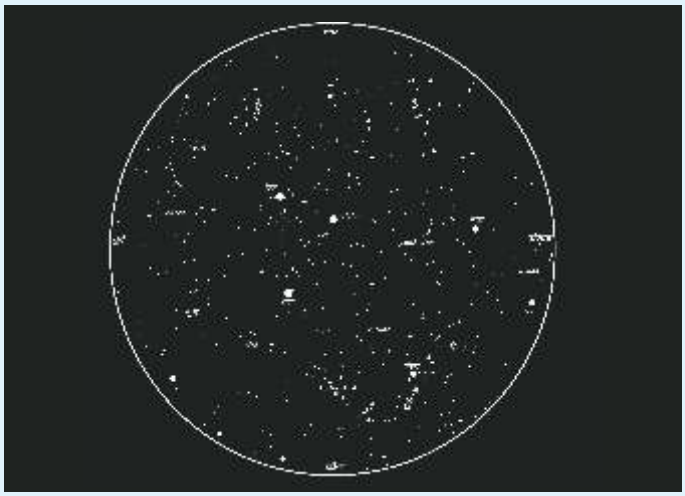

ध्रुव तारा। इस समय ध्रुव तारे से पूर्व दिशा में पाँच चमकदार तारे झिलमिला रहे हैं। अंग्रेजी अक्षर 'डब्ल्यू' के आकार में यह है काश्यपि (Cassiopeia) तारामण्डल या शर्मिष्ठा। उत्तरी आसमान में ही मौजूद है एक वृहद तारामण्डल – महाश्व। काश्यपि व माहाश्व की मदद से प्रसिद्ध मंदाकिनी देवयानी (Andromeda Galaxy) को आसमान स्वच्छ होने पर दूरबीन या बाइनोक्युलर के माध्यम से देखा जा सकता है। देवयानी हमसे लगभग 24 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। कोरी आँखों से यह एक सफेद बादल के छोटे टुकड़े जैसी दिखती है।

मध्याकाश की गरिमा बढ़ा रहा है – ग्रीष्म त्रिकोण (Summer Triangle)। इसके शीर्ष पर चमकदार तारे हैं – डेनब, अभिजीत व श्रवण। डेनब हंसमण्डल (Cygnus) का सबसे चमकदार तारा है। सुनीतिमण्डल के तारे एक राजमुकुट की आकृति में झिलमिला रहे हैं। कन्या राशि का चमकदार तारा चित्रा पश्चिमी क्षितिज के निकट है। तुला, मकर व कुम्भ राशियाँ भी मौजूद है। इन राशियों में कोई चमकदार तारा नहीं है। मकर व कुम्भ की सीमा पर शनि ग्रह डेरा डाले हुये है। राशियों में सबसे सुन्दर वृश्चिक–आसमान में चिपका एक बिच्छू दक्षिणी आसमान में साफ–साफ नजर आ रहे है। इसमें लाल चमकदार नक्षत्र है ज्येष्ठा।

सूर्य जुलाई में मिथुन से निकल कर्क राशि प्रवेश करता है। 4 जुलाई को यह हमसे अधिकतम दूरी पर होगा। सूर्योदय व सूर्यास्त का समय निम्न प्रकार है:–

	जयपुर		श्रीगंगानगर		उदयपुर		जैसलमेर	
	उदय	अस्त	उदय	अस्त	उदय	अस्त	उदय	अस्त
03 जुलाई	5:00	7:00	5:00	7:00	5:00	7:00	6:00	7:00
15 जुलाई	5:00	7:00	5:00	7:00	6:00	7:00	6:00	7:00
30 जुलाई	5:00	7:00	5:00	7:00	6:00	7:00	6:00	7:00

प्रस्तुत मानचित्र 1 जुलाई को रात्रि 11:00 बजे, 15 जुलाई को रात्रि 10:00 बजे व 30 जुलाई को रात्रि 09:00 बजे की जयपुर शहर से आकाशीय स्थिति दर्शाता है।

'चुप्पी तोड़ो–सयानी बनो'

अभियान से किशोरी बालिकाओं में आई जागरूकता

हाइजीन एम्बेसडर माहवारी स्वच्छता के बारे में कर रही हैं जागरूक

मानसिंह मीना
सहायक निदेशक, जनसम्पर्क

माहवारी स्वच्छता प्रबंधन एवं गुड टच बेड टच जैसे संवेदनशील विषय किशोरी बालिकाओं, महिलाओं के स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का अभिन्न अंग हैं। ऐसे विषयों पर वर्तमान समय में काफी हद तक जागरूकता आयी है। किन्तु ग्रामीण अंचल में अभी भी महिलाओं एवं किशोरी बालिकाओं में इस विषय को लेकर हिचकिचाहट है। जिसे अब दूर करने की नितान्त आवश्यकता है। जयपुर जिला कलक्टर श्री राजन विशाल की अनोखी पहल से जिले में इसे संचालित किया जा रहा है।

इस संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण विषय पर महिलाओं और बालिकाओं की शंकाओं का मिथक टूटे, चुप्पी टूटे और वे सयानी बने तथा गुड टच बेड टच जैसे विषय पर वर्तमान सामाजिक परिस्थितियों को देखते हुये बच्चों में जागरूकता आवश्यक है क्योंकि बच्चे देश का भविष्य हैं इसलिये बच्चे के पहले 10 साल बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन विषयों पर जागरूकता का प्रचार-प्रसार करने के लिये जिला प्रशासन एवं महिला अधिकारिता विभाग द्वारा 'उड़ान योजना' एवं स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत एक अनुपम नवाचार 'चुप्पी तोड़ो सयानी बनो' अभियान के प्रथम चरण की पहल अन्य विभागों के समन्वय से की गई है।

2 हजार 223 अध्यापिकाओं को दिया गया प्रशिक्षण

जयपुर जिले के प्रत्येक उपखण्ड एवं ग्राम पंचायत स्तर पर इस अभियान के प्रथम चरण में कार्यशाला, प्रशिक्षण, जन जागरूकता कार्यक्रम एवं अन्य गतिविधियों का आयोजन चरणबद्ध रूप से किया गया। प्रथम चरण में राजकीय विद्यालय में कार्यरत 2 हजार 223 अध्यापिकाओं को माहवारी स्वच्छता प्रबंधन तथा गुड टच एवं बेड टच जैसे विषय पर विशेषज्ञ के रूप में प्रशिक्षित किया गया।

929 विद्यालयों में हुआ कार्यशाला का आयोजन

चुप्पी तोड़ो सयानी बनो अभियान के द्वितीय चरण के तहत जिले के 929 विद्यालयों में कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें लगभग 1 लाख 30 हजार किशोरी बालिकाओं द्वारा भाग लिया गया। कार्यशाला में प्रशिक्षित अध्यापिकाओं द्वारा माहवारी स्वच्छता प्रबंधन के बारे में जानकारी दी गई। माहवारी स्वच्छता प्रबंधन विषय पर प्रकाशित बुकलेट का वितरण विद्यालयों में पंजीकृत छात्राओं एवं विद्यालय नहीं जाने वाली छात्राओं, अभिभावकों, जनप्रतिनिधियों, आंगनबाडी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी, एएनएम आदि को किया गया।

हाइजीन एम्बेसडर सर्टिफिकेट दिए

कक्षा 9वीं से 12वीं मे पढ़ने वाली छात्रा जो हाइजीन एम्बेसडर नियुक्त की गई है उन्हें विद्यालय प्रशासन द्वारा हाईजीन एम्बेसडर सर्टिफिकेट प्रदान किये गये। इस दौरान उन्हें अभियान की निरन्तरता बनाये रखने एवं जिम्मेदारी के बारे में भी अवगत कराया है।

3 हजार 716 छात्राओं को नियुक्त किया है हाइजीन एम्बेसडर

कक्षा 9 से 12वीं तक चयनित की गई 3 हजार 716 छात्राओं को हाइजीन एम्बेसडर नियुक्त किया गया। कार्यशाला में राज्य सरकार की उड़ान योजना के अन्तर्गत बालिकाओं को सैनेटरी नैपकीन निःशुल्क उपलब्ध कराए गए। अभियान के तहत कार्यशाला में प्रत्येक छात्रा को माहवारी स्वच्छता प्रबंधन पर बुकलेट व प्रत्येक राजकीय विद्यालय को गुड टच बेड टच विषय पर पोस्टर एवं बैनर उपलब्ध करवाये गए।

राज्य सरकार की अनूठी पहल

राजीव गांधी ग्रामीण ओलम्पिक खेल

प्रवीण प्रकाश चौहान
जनसंपर्क अधिकारी

किसी भी प्रदेश के सर्वांगीण विकास में खेलों की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। राज्य सरकार का यह प्रयास है कि प्रदेश के नागरिकों को खेलों में भाग लेने की बुनियादी सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हों, ताकि वे स्वस्थ एवं अनुशासित नागरिक बनकर प्रदेश की प्रगति में अधिक से अधिक योगदान दे सकें।

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत का यह सपना है कि प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा खेल सुविधाओं का विकास हो, जिससे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के पर्याप्त अवसर उपलब्ध हो सकें। साथ ही प्रदेश खेल के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो। खेल के क्षेत्र में राज्य को राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिले।

राज्य सरकार खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश में खेल का वातावरण एवं आधारभूत सुविधाएं विकसित कर रही है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के प्रतिभावान खिलाड़ियों के हित में अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। राज्य सरकार राजीव गांधी ग्रामीण ओलम्पिक का आयोजन कर एक नया कीर्तिमान स्थापित करने जा रही है। देश में ऐसा पहली बार हो रहा है जब कोई राज्य सरकार खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण ओलम्पिक का आयोजन कर रही है।

29 अगस्त से 2 अक्टूबर तक होगा आयोजन

प्रदेश में 28 अगस्त से शुरू होने वाले ग्रामीण ओलम्पिक खेलों की अलख जगाने के लिए 29 मई को मुख्यमंत्री ने जयपुर से एक मशाल रैली को रवाना किया। मशाल रैली राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में घूमकर युवाओं और प्रतिभावान खिलाड़ियों को ग्रामीण ओलम्पिक में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करेगी। प्रदेश में ग्रामीण ओलम्पिक खेलों का आयोजन 29 अगस्त से 2 अक्टूबर तक किया जाएगा।

इन खेलों का होगा आयोजन

ग्रामीण ओलम्पिक के तहत कबड्डी, शूटिंग, वॉलीबाल, टेनिस, क्रिकेट, हॉकी, खो-खो आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। ग्रामीण ओलम्पिक खेल का आयोजन 35 दिन तक चलेगा। इस पर राज्य सरकार करीब 40 करोड़ रुपये खर्च करेगी।

15 से 70 वर्ष तक की आयु के खिलाड़ी होंगे शामिल

राज्य सरकार ने प्रदेशभर में आयोजित इस प्रतियोगिता में उम्र के बंधन में छूट दी है। ग्रामीण ओलम्पिक में 15 से 70 वर्ष तक की आयु वर्ग के खिलाड़ी शामिल हो सकते हैं।

करीब 27 लाख प्रतियोगियों ने करवाया रजिस्ट्रेशन

राजीव गांधी ग्रामीण ओलम्पिक के लिए 27 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रदेश के ग्रामीण इलाकों की खेल प्रतिभा को तराशने में ग्रामीण ओलम्पिक मील का पत्थर साबित होगा।

पुरुष और महिला दोनों श्रेणी में होंगे मुकाबले

ग्रामीण ओलम्पिक में पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों में मुकाबले होंगे। ग्रामीण ओलम्पिक खेलों का आयोजन गांव, ग्राम पंचायत और ब्लक स्तर पर किया जाएगा, जिसमें प्रदेश के 44 हजार 795 गांव, 11 हजार 341 ग्राम पंचायत और 352 ब्लॉक स्तर पर खेलों का आयोजन किया जाएगा। ग्रामीण ओलंपिक खेल दो चरण में आयोजित होंगे। पहले चरण में ग्राम पंचायत स्तरीय खेल प्रतियोगिताएं होंगी। दूसरे चरण में ब्लॉक स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। इससे ग्रामीण स्तर की प्रतिभाएं निखरेंगी और उनका हौसला बढ़ेगा।

राज्य सरकार का ग्रामीण खेल प्रतिभा खोज के लिए नवाचार

प्रदेश के खिलाड़ियों को तैयार करने और गांव में छुपी हुई खेल प्रतिभाओं को खोजने के लिए राज्य सरकार ने ग्रामीण ओलम्पिक की शुरुआत की है, ताकि आगामी ओलम्पिक और कॉमनवेल्थ एशियाई गेम्स में प्रदेश के खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन कर सकें। ग्रामीण ओलम्पिक में ग्रामीण स्तर पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। साथ ही उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल करवाने का प्रयास किया जाएगा। ●

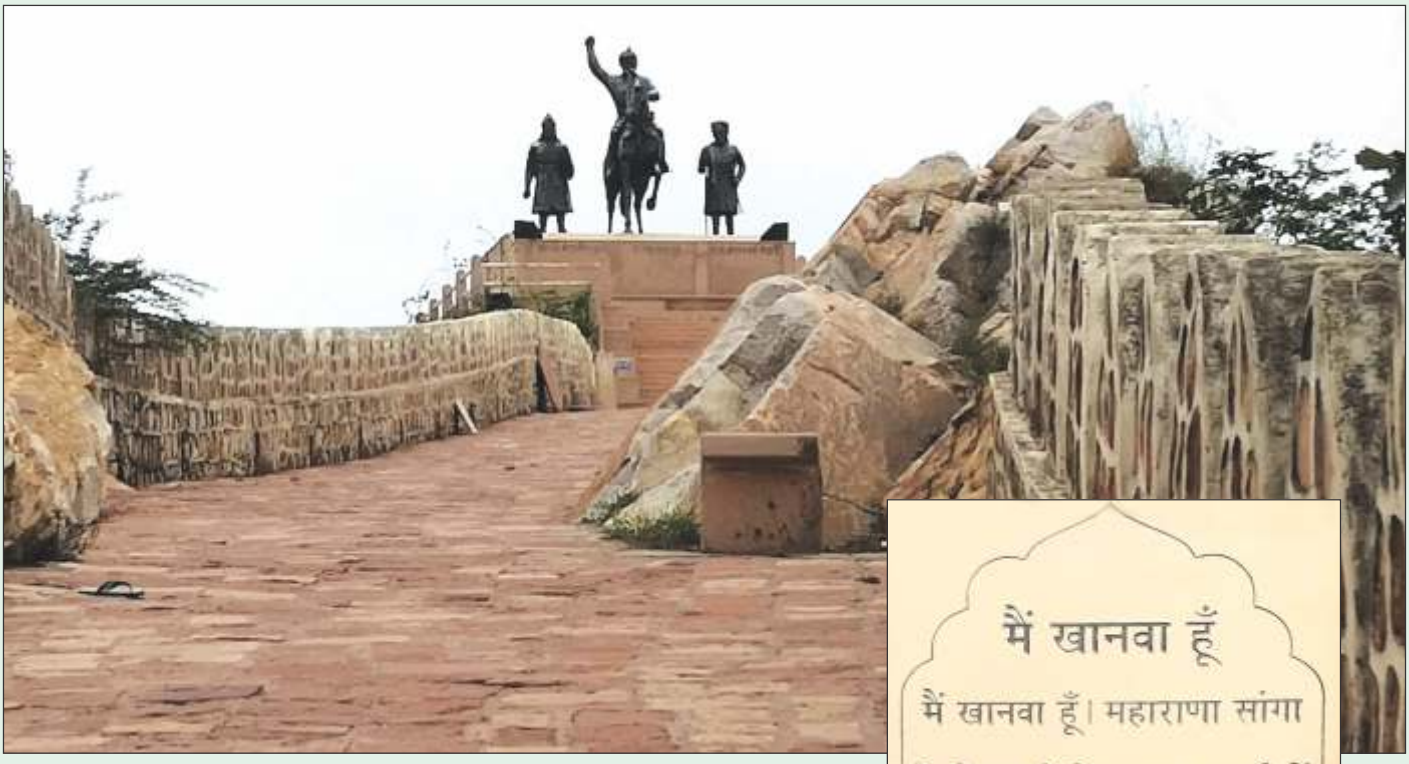

खानवा स्मारक, भरतपुर

भरतपुर जिले की रूपवास तहसील में स्थित है खानवा स्मारक। मार्च 1527 में हिंदुस्तान में मुगलों का प्रवेश रोकने के लिए मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने बाबर से युद्ध किया। पहली बार इस युद्ध में बाबर ने तोपखाने और बंदूकों का उपयोग किया था, जिससे पूरे पहाड़ छलनी हो गए थे, जिसके प्रमाण आज भी मौजूद हैं। एक हाथ, एक पैर और एक आँख से गंभीर रूप से जख्मी होने एवं शरीर पर अस्सी घाव होने के उपरांत भी राणा सांगा लड़ते रहे। राणा सांगा के साथ इस युद्ध में मेवात से हसन खां मेवाती, चंदेरी के मेदिनी राय, रतन सिंह चूण्डावत सहित खेतसी, आमेर, जोधपुर, हलवद, डूंगरपुर, मैनपुरी के करीब 24 वीर योद्धाओं की गाथाओं का साक्षी है खानवा स्मारक।

गोपाल गुप्ता, वरिष्ठ पत्रकार

Postal Regd. No. Jaipur City/413/2020-22
Registered with Registrar of Newspapers of India under R. No. 56175/1991

प्रकाशक व मुद्रक – सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशक, पुरुषोत्तम शर्मा द्वारा सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के लिए, शासन सचिवालय, जयपुर (राजस्थान) से प्रकाशित
सम्पादक – श्रीमती अलका सक्सेना, मै. कृष्णा प्रिन्टर्स, डी–14, सुदर्शनपुरा, जयपुर से मुद्रित, 'राजस्थान सुजस'–पृष्ठ संख्या 60, लागत मूल्य 30.56 रुपये ● 5,00,000 प्रतियां